



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 54]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

अंतिम जाँच परिणाम

(पाटनरोधी जाँच )

**विषय :** ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

**सं. 14/20/2015-डीजीएडी.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

यतः मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें ईरान, कतर, चीन जन. गण. और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या 'एलएबी' कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

**ख. प्रक्रिया**

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क.निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त नियमों के तहत संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें ईरान, कतर, चीन जन. गण. और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन'(जिसे आगे संबद्ध वस्तु या 'एलएबी' कहा गया है) के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया है।

ख.याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत के लिए एक उचित ढग से दस्तावेजित रूप में विचार किया गया है।

ग.प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 उप-नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत की कार्यवाही से पहले आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया है।

घ.प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ईरान, कतर, चीन जन. गण. और सउदी अरब (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जाँच की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। जाँच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख के अनुसार, प्राधिकारी ने जाँच अवधि के दौरान सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में ऋणात्मक पाटन मार्जिन पाया है और इसलिए वह वर्तमान जाँच में संबद्ध देश के रूप में सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जाँच की शुरुआत को उचित नहीं मानते हैं।

ङ.प्राधिकारी ने भारत में राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 7 दिसंबर, 2015 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई। जाँच शुरुआत में एक मामूली त्रुटि में सुधार करने के लिए दिनांक 13/1/2016 को एक शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था।

च.प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग एसोसिएशनों (जिनके ब्योरे याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनके विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया।

छ.प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने की सलाह दी।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप भारत में चीन जन. गण. के दूतावास, भारत में ईरान इस्लामिक गणराज्य के दूतावास और कतर के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति को उपलब्ध कराई थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को भी प्रदान की गई थी।

झ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत स्थित चीन जन. गण. के दूतावास को भी भेजी गई थी जिसमें विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया। यद्यपि जाँच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके किया गया है तथापि, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया है कि उन्होंने आवेदक के दावे की यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में जाँच का प्रस्ताव किया है। अंतः चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से ऊपर दिए गए अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि चीन जन. गण. के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान किया जा सकता है। तथापि चीन जन. गण. से किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने चीन जन. गण. को दिए गए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का खंडन करते हुए एमईटी प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ञ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं:

ईरान कैमिकल्स इंडस्ट्रीज इनवेस्टमेंट कंपनीज, सं. 91 सैदी एसटी अफ्रीका एवेन्यु तेहरान (19679 ) ईरान	कोल्मर ग्रुप एजी, लोबेहोफ, मैटलस्ट्रेस 9, 6300 जुग, स्विटजरलैंड
सीफ लिमिटेड, कतर, सीफ लिमिटेड पो. बा.: 50077, मेसाइड, कतर राज्य	जिआंगसु जिंटोंग कैमिकल कं. लि. 201 याओक्सिन एव. किंसीआ, नांजिंग जिआंगसु चीन, 210046
जिंझू यांगजिआ कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.; सं.25, बाई गुआन ली, लिंगही जिला, जिंझू सिटी लाओनिंग प्रोविंस चीन जन. गण.	पेट्रोचाइना इंटरनेशनल फुशुन कं. लि. 16-हुंहे रोड, नार्थ फुशुन लाओनिंग प्रोविंस चीन जन. गण

सिनोपेक जिनलिंग पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन; सं. 22, चाओयंगमेन नार्थ स्ट्रीट, चाओयंग जिला, बिजिंग, चीन जन. गण.	ग्रेट ओरिएंट कैमिकल (टाइकेंग) कं. लि.; रूम 807, सेंचुरी वेल्थ बिल्डिंग, नं.86 शंघाई रोड (ई), टाइकांग, जिआंगसु प्रोविंस चीन 215400
ग्रेट ओरिएंट कैमिकल (टाइकेंग) कं. लि. ; 11 साउथ बिजिंग रोड, टाइकांग रोड डेवलपमेंट जोन, जिआंगसु 215433 – चीन	

ट. जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया:

- मैं. सीफ लि., कतर (उत्पादक)
- मैं. ग्रेट ओरिएंट कैमिकल (टाइकेंग) कं. चीन
- मैं. कतर कैमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुटाजाट) क्यू.जे.एस.सी., कतर (निर्यातक)
- मैं. जिआंगसु जिंटुंग कैमिकल कोर्प लि. और उसके संबंधित पक्ष होटुंग कैमिकल कार्प और शार्पिंवेस्ट, चीन जन. गण.
- रेनिश पेट्रोकेम एफजेडई

ठ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थी :

मैं. फैशन सूटिंग (पी) लि. 3, छाबड़ा मेंशन पुरी रोड भीलवाड़ा-311001	मैं. श्री युनिकान आर्गेनिक्स प्रा. लि. बीएस, एपजी; 130 मुंबई समाचार मार्ग मुंबई-400023
ए.आर. सल्फोनेट्स प्रा. लि. प्लाट नं. एन41 ; अतिरिक्त अंबरनाथ, एमआईडीसी आनंद नगर ; जिला थाणे -421501 ; महाराष्ट्र	तमिलनाडु स्माल स्केल श्राप एंड डिटरजेंट्स; चेदू डी अंपा, IV तल , सं. 37, पुराना नं. 110 ; नेल्सन मनिकम रोड चेन्नई - 600029
शांतिनाथ डिटरजेंट्स (पी) लि. पी-15, कलाकार स्ट्रीट ; कोलकाता-700007	राजाराम गुप आफ इंडस्ट्रीज; 14, अजीज नगर सेकेंड स्ट्रीट ; कोडमबक्कम चेन्नई.600024
किशोर संस डिटरजेंट्स लि. 15-9-469, महनूनगंज हैदराबाद – 500012. (आं.प्र.)	एडवांस सर्फैक्टेंट्स इंडिया लि. 511/2/1. रजोकरी, नई दिल्ली-110038
ए. आर. स्टेनकेम प्रा. लि., निर्यातक और विनिर्माता ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट दूसरा तल, कोक एंड कालवे बिल्डिंग कोलकाता 700001	न्यू इंडिया डिटरजेंट्स लि. ए-2/25 माडल टाउन -1 दिल्ली-110009
मैं. स्माल स्केल डिटरजेंट्स 43 यूरोपियन एसाइलम लेन, कोलकाता -700016	स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट्स लि. 8/5 आर्य नगर, कानपुर-208002
गोरा मल हरि राम लि. 39, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक एरिया नई दिल्ली -15	डिटरजेंट मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 148 न्यू ओखला, इंडस्ट्रीयल कांप्लेक्स-I नई दिल्ली-110020

बारकुर सर्फेक्टेंड्स प्रा. लि. यूनिटाप हाउस, ईस्ट वेस्ट इस्टेट सफेद पूल, अंधेरी कुर्लारोड मुंबई -400072	इसरो प्रोडक्ट यूनिटाप हाउस, ईस्ट वेस्ट इस्टेट सफेद पूल, अंधेरी कुर्लारोड मुंबई -400072
एस.कुमार्स डिटरजेंट्स प्रा. लि. 4-डी, लोकल शापिंग सेंटर, ए ब्लॉक, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली -110028	सकी-कैम 59 और 60 डीएसआईडीसी, इंडस्ट्रीयल कांप्लेक्स ओखला, फेस-1, नई दिल्ली-110020
हिपोलीन लि. मधुवन, चौथा तल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006	आल इंडिया फेडरेशन आफ डिटरजेंट्स मेन्युफेक्चरर्स; 511/2/1, रजोकरी, नई दिल्ली -38
महाराष्ट्र स्माल स्केल शाप डिटरजेंट्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन श्री वीराबाई मा निवास, शास्त्री नगर स्क्वायर, नागपुर-8, महाराष्ट्र	गुजरात स्माल स्केल डिटरजेंट्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, द्वारा किशोर शाप इंडस्ट्रीज, महेश्वरी मिल रोड तावडीपुरा, शाहीबाग अहमदाबाद - 380004
पावर शाप्स लि., 62-बी, नार्थ बोग रोड, टी. नगर चेन्नई -600017	मै. भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट्स प्रा. लि., भवानी कांप्लेक्स, 35, हनुमानगंज, जुमेरती कार्नर के पास, भोपाल- 462001 (म.प्र.)
मै. अबडोर कंज्यूमर केयर लि., जालान कम्पाउंड, बाम्बे हाइवे, एनएच सं. 6, बिपारन्नपारा, हावड़ा- 711411	मै. प्रभु शाप वर्क्स, पो. बा.न. 5115, 3/ए1; थायिर इट्टेरी रोड, कन्नप्पन नगर, रतिनापुरी (डाकघर) कोयम्बटूर - 641 027
मै. शिवा शाप वर्क्स नंथावना पट्टी, डिंडीगुल- 624005	मै. भारती शाप वर्क्स, पहली लाइन नल्लाचेरुवू गुंटूर - 522 003 (आं.प्र.)
मै. सबरी डिटरजेंट्स 191 बलपराई रोड, अवलचिन्नमपलायम, जमीन कोट्टमपट्टी, पोल्लची- 642 123	मै. एस. एस. एंटरप्राइजेज सं.-43, सिडको इंडस्ट्रीयल इस्टेट, डिंडीगुल -624003
मै. मान कैमिकल्स, 20/1, सिवाकामी इल्लम, लक्ष्मी सुंदरम कालोनी, एम.एस.पी. स्कूल ग्राउंड के पीछे डिंडीगुल - 624 005	मै. शक्ति ट्रेडर्स, सं.. 5/810, मल्लीगाई रोड, कूट्टूरावू नगर, डिंडीगुल - 624 005
मै. श्रीराम भारत कैमिकल्स एंड डिटरजेंट्स (प्रा.)लि., 1/56, संजय गांधी नगर, नोचीपलायम रोड, 46, पुंढूर गांव, इरोड - 638002	मै. नेशनल शाप कंपनी, 138/1, सम्मान पलायम पिरिवु नसियानूर रोड विल्लारसमपत्ती नाल रोड, नसियानूर (डाकघर) इरोड - 638107, तमिलनाडु
मै. श्री मनाकुला विनायगा कैमिकल्स, आरएस सं. 89/1-एफ एंड डी, पन्नीथिट्टू रोड किरुमपक्कम,	मै. सिल्वर कैमिकल्स, 1/255, मेन रोड, वलायनकुलम,

पुदुचेरी – 607 402	मदुरै – 625 022, तमिलनाडु
मै. राजा कैमिकल वर्क्स, # 137, समी अयर न्यू स्ट्रीट, कोयंबटूर – 641 001	मै. श्री पुष्पम इंडस्ट्रीज, आरएस सं. . 121/1 और 63/7, मडागडीपूट और तिरुबुवानी गांव, तिरुबुवानाई पोस्ट, पांडिचेरी– 605107
मै. लिंगम कैमिकल इंडस्ट्रीज, 8/55, अंबाई रोड, अलंगुलम – 627851, तिरुनेवेली, तमिलनाडु	मै. आनंद कैमिकल्स, 13/4 कामाराजार नगर, अवनीयापुरम (डाकघर) ; अयानपप्कुडी मदुरै– 625012 (तमिलनाडु)
मै. हाई-टेक इंडिया, नं. 1, वेंगुर रोड, थिरुवेरुम्बूर, त्रिची – 620 013	मै. फ्लोरा कैमिकल्स 2/226, अम्माची अम्मन कोइल स्ट्रीट, उथानगुडी, मदुरै– 625 107
मै. देवी क्रापसाइंस प्रा. लि. पो. बा. नं. 274, 29-ए, वर्कशाप रोड मदुरै – 625 001	मै. शनमुगा इंडस्ट्रीज, 139-एबीसी, सुंडाक्मुथुर रोड, सेल्वापुरम, कोयंबटूर – 26
मै. साइमोस प्रोडक्ट्स, 4/139. अयनारपुरममेन रोड, पनाईयूर (डाकघर), मदुरै – 625009	मै. रेसमे प्रोडक्ट्स, 2/221., अयनार कोविल स्ट्रीट, उथनगुडी, मदुरै– 625 017
मै. अर्चिड कैमिकल्स, 183, नेडुनगुलम रोड, पोटापलायम, सिवागाना जिला-630611	मै. मुथुकनी इंडस्ट्रीज, 2/104 (1)- नयू कालोनी, अंडीपल्ली– डाकघर, अलनगुलम – 627 851
मै. वरदान डिटरजेंट प्रा. लि., प्लाट नं. 131, सेक्टर – 24, फरीदाबाद – 121005	मै. राइनो इंडस्ट्रीयल आर्गेनिक्स प्रा. लि., बी-93, मायापुरी– I, नई दिल्ली – 64
फेना प्रा. लि., ए- 67 और 68 मेट्रपलायम, पीआईपीडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, पांडिचेरी-605009	स्किल डाइकेम, विलेज पंचपारा, डाकघर राधादासी - 711309, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल

ड. जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है:

- हिंदुस्तान यूनिलिवर लि.
- डिटरजेंट मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
- आर्डर इंटरनेशनल प्रा. लि. , आर्डर ग्लोबल प्रा. लि. और कैम-एज इंटरनेशनल प्रा.लि.
- सर्फेक्टेंट्स मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
- इंडियन होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री एसोसिएशन

ड. जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों को भी भेजी गई थी :

मै. इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल भवन, नं. 1, श्री अरविंदो मार्ग, यूसूफ सराय नई दिल्ली – 110 016	मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. मेकर चैम्बर्स IV तीसरा तल, 222, नरीमन प्वाइंट मुंबई– 400 021
--	---

ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को वर्तमान जाँच परिणामों में ध्यान में लिया गया है।

त. प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्यातकों/आयातकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उसके मिलान में कुछ और समय की जरूरत को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 19 फरवरी, 2016 की अधिसूचना द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 8 मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया था।

थ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

द. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्योरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य तथा क्षति विश्लेषण की गणना के लिए डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों को भी यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक भारत को पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़ों को सह-संबंधित करने के लिए प्राप्त किया गया था।

ध. याचिकाकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों से आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सूचना मांगी गई थी। वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग को सत्यापन किया गया था।

न. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर आधारित क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को ज्ञात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

प. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि अप्रैल, 2014 – जून, 2015 (15 महीनों) ( जिसे आगे जाँच की अवधि या जाँच अवधि भी कहा गया है) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच में 2011 - 2012, 2012- 2013, 2013-14 और जांच की अवधि शामिल है।

फ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11। में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक जाँच की है ताकि भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षतिरहित कीमत ज्ञात की जा सके और इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ब. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 8 जून, 2016 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। बाद में 4 नवंबर, 2016 को एक और आम सुनवाई आयोजित की गई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने भाग लिया। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध को विरोधी हितबद्ध पक्षों को परस्पर आदान-प्रदान के लिए अन्य द्वारा उनके बाद खंडन प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

भ. पीओआई के लिए अम. डा. से रूपये में परिवर्तन के लिए विनिमय दर इस प्रकार है :

1 अम.डा. = 62.13 रूपये

1 अम.डा. = 3.64 न्यू आर

1 अम.डा. = सीएनवाई 6.1

म. अंतिम जाँच परिणाम में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार/अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

य. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 21 फरवरी को मामले के अनिवार्य तथ्यों प्रकटन किया था। 1 मार्च, 2017 तक टिप्पणियों का अनुरोध किया गया था। प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।

र. केन्द्र सरकार द्वारा इस जाँच को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि को 06/03/2017 तक बढ़ा दिया गया था।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ईरान, कतर और चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' है।

**निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार**

3. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच अंतर हैं, चीन से आयातित उत्पाद में एलएबी के प्रति टन अणु 1.6 प्रतिशत कम हैं और ईरान से आयातित में भारतीय घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम है। समान उत्पादों की तुलना सुनिश्चित करने पर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

**घरेलू उद्योग के विचार**

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- क. वर्तमान जॉच में पीयूसी 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' (एलएबी) है और उसमें मिश्रित बेंजीन शामिल है और मिश्रित अलकाइल नेपथलीन उसमें विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है।
- ख. एलएबी को पैराफीन और बेंजीन के कच्ची सामग्री के रूप में निकालकर केरोसीन के प्रयोग से विनिर्मित किया जाता है। पैराफीन को फीडस्टॉक केरोसीन से हाइड्रोबोन मोलेक्स प्रक्रिया से निकाला जाता है। इन पैराफीन को उच्च ताप पर सिलेक्टिव डिहाइड्रोजेनेशन द्वारा उनके ओलेफिन में बदला जाता है। उसके बाद 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' बनाने के लिए ओलेफिन को बेंजीन में अल्काइलेटेड किया जाता है।
- ग. एलएबी का प्रयोग मुख्यतः 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' सल्फेट के उत्पादन में होता है जिसे उसके बाद लाउंड्री डिटरजेंट, लाइट-इसूटी डिशवाशिंग तरल, औद्योगिक क्लीनरों और घरेलू क्लीनरों को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है।
- घ. संबद्ध वस्तु के कोई ज्ञात वाणिज्यिक रूप से मौजूद ग्रेड नहीं हैं।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एलएबी और संबद्ध देशों से आयातित एलएबी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं।
- च. पीयूसी में अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाए कि लीनियर अल्काइल बेंजीन के निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशन हैं जिनमें अंतर्निहित अन्य घटकों के लिए सीमाएं परिभाषित हैं। सभी विनिर्माताओं, भारतीय और विदेशी द्वारा उत्पादित एलएबी इन विनिर्देशनों को पूरा करती है। यह उत्पाद विनिर्देशन की केवल गलत व्याख्या है।

**प्राधिकारी द्वारा जॉच**

5. वर्तमान जॉच में पीयूसी 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' (एलएबी) है और उसमें मिश्रित बेंजीन शामिल है और मिश्रित अलकाइल नेपथलीन उसमें विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद को बाजार शब्दावली में वाणिज्यिक रूप से लीनियर अल्काइल बेंजीन (लघु रूप में एलएबी) के रूप में जाना जाता है।

6. एलएबी कार्बन अणुओं की एकल श्रृंखला से जुड़े बेंजीन रिंग के संघटित पदार्थों के मिश्रण के रूप में उपलब्ध है। विचाराधीन उत्पाद के अनेक आइसोमर संभव हैं क्योंकि बेंजीन रिंग टर्मिनल कार्बन के अलावा अल्काइल श्रृंखला के सभी कार्बनों में हो सकती है। प्रति अल्काइल श्रृंखला में कार्बनों की संख्या किसी दिए गए उत्पाद में दस से सोलह हो सकती है। यह  $C_{6}H_{5}C_{n}H_{2n+1}$  वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें 10 से 16 के बीच होता है। यह रंगहीन और गंध रहित तरल होता है और जल में थोड़ा घुलनशील होता है। उसे ज्वलनशील रासायनिक उत्पाद माना जाता है। यह रासायनिक मध्यवर्ती का कार्य करता है और मुख्यतः लीनियर अल्काइलबेंजीन सल्फोनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसे उसके बाद लाउंड्री डिटरजेंट, लाइट-इसूटी डिशवाशिंग तरल, औद्योगिक क्लीनरों और घरेलू क्लीनरों को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 38 के अधीन आयात किया जा रहा है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जॉचके दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि उनके द्वारा विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया भी तुलनीय हैं।

8. हितबद्ध पक्षों ने संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में एलएबी प्रति टन अणुओं में अंतर की दलील दी है। हितबद्ध पक्षों के दावे की रिकार्ड में सूचना और भारतीय उत्पादकों और कतर में उत्पाद के परिसर में मौके पर सत्यान के समय जाँच की गई थी। यह नोट किया जाता है कि कतर में प्रतिवादी उत्पादक ने अणु के भार में अंतर के कारण उत्पादन लागत में किसी अंतर का दावा न करने को स्वीकार किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अणु भार में अंतर कच्ची सामग्री या प्रक्रियाओं में अंतर का परिणाम है। कोई उत्पादक किसी अणु भार विशेष के उत्पाद के उत्पादन की मंशा नहीं रखता है। हितबद्ध पक्षों ने अणु भार में अंतर के आधार पर लागत और कीमत में किसी मात्रात्मक अंतर को सिद्ध नहीं किया है।

9. उक्त के अधीन, विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के दायरे के संबंध में किसी हितबद्ध पक्ष से कोई तर्क प्राप्त नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्पाद और आयात आकड़ों की जाँच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है। विनिर्माण प्रक्रिया और प्रतिस्थापनीयता में समानता को देखते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ इन्हें समान और एक उत्पाद मानते हैं।

#### **घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति**

##### **निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार**

10. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. याचिकाकर्ता कुल भारतीय उत्पादन का मुख्य हिस्सा नहीं बनाते हैं क्योंकि वे कुल घरेलू उत्पादन के केवल 32 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं के आकड़ों पर विचार करके प्राधिकारी समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों के रूझान का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।
- ख. घरेलू उद्योग के लिए मुख्य हिस्से और स्थिति संबंधी सीमा की अपेक्षाएं एडी नियमों के तहत दो अलग अपेक्षाएं हैं जैसा कि ईसी-फास्टेनर्स (चीन) में डब्लूटीओ अपीलीय निकाय की स्थिति है। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 32 प्रतिशत है जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर विकृति के जोखिम पर घरेलू उद्योग बनाने के लिए पर्याप्त माना गया है, विशेष रूप से क्योंकि घरेलू उद्योग बिखरा हुआ नहीं है और शेष 68 प्रतिशत संबद्ध वस्तु के केवल दो प्रमुख उत्पादकों के पास है।
- ग. आरआईएल और आईओसीएल को अपने पूरे क्षति संबंधी आकड़े प्रस्तुत करने चाहिए ताकि प्राधिकारी सभी चार उत्पादकों के आकड़ों पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के लिए निष्पक्ष विश्लेषण कर सकें। यह निर्विवाद है कि समर्थकों के लिए विस्तृत क्षति अनुरोध प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, परंतु आरआईएल और आईओसीएल का केवल समर्थकों के रूप में भाग लेना उनके प्रमुख हिस्से के होने के कारण अपर्याप्त है।
- घ. आरआईएल का दिनांक 14 जून, 2016 का पत्र अत्यंत त्रुटिपूर्ण है और उसे जाँच की शुरुआत के 7 महीने से अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं के साथ आरआईएल का कोई संयुक्त आकड़ा नहीं दिया गया है।
- ङ. दूसरी सुनवाई के स्तर पर, हितबद्ध पक्षों ने यह दलील दी की प्राधिकारी को आरआईएल के आकड़े स्वीकार नहीं करने चाहिए क्योंकि वह काफी देरी से थे।
- च. संशोधित आवेदन के अनुसार, एक याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है जिससे याचिकाकर्ताओं के बिक्री के हिस्से में कमी आ जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा आयातों का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

11. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए याचिका को घरेलू उद्योग द्वारा दायर माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता कुल भारतीय उत्पादन के 32 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं जो एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अधीन प्रमुख हिस्सा बनता है। इस संबंध में *लुब्रिजोल (इंडिया) प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले को निणायक* के रूप में माना गया है।
- ख. किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने संबद्ध देशों में से उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- ग. याचिकाकर्ताओं के अलावा भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन के दो और उत्पादक अर्थात् मै. इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. हैं। दोनों उत्पादकों ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया है।
- घ. जहां तक आरआईएल और आईओसीएल द्वारा क्षति संबंधी आकड़े प्रस्तुत करने का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने प्रयास किये हैं और इन कंपनियों से अनुरोध किया है। यद्यपि याचिकाकर्ता संगत सूचना प्रदान करने के लिए किसी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं तथापि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ मै. आरआईएल से आकड़े मांगे थे जिसने जाँच की प्रक्रिया के दौरान क्षति सूचना प्रदान की।
- ङ. आरआईएल की विलंबित क्षति सूचना के मुद्दे के संबंध में, हितबद्ध पक्षों ने स्वयं रिलायंस की भागीदारी का मुद्दा यह कहते हुए उठाया है कि याचिकाकर्ताओं का हिस्सा भारतीय उत्पादन में कम है। अतः इस संदर्भ में सूचना का खंडन करना तार्किक नहीं है जबकि उसे जाँच शुरुआत के काफी बाद में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी तरह से, हितबद्ध पक्षों को आरआईएल द्वारा प्रदत्त सूचना पर टिप्पणी



करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

च. कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणन और जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना दर्शाती है कि याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। प्रस्तुत याचिका के भाग 4 में त्रुटि को सुधार दिया गया है।

#### **प्राधिकारी द्वारा जॉच**

12. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

13. यह आवेदन मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. द्वारा दायर किया गया है। किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने जॉच अवधि के दौरान न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही याचिकाकर्ता कंपनियां संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। संबद्ध वस्तु के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं अर्थात् मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसीएल) जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है। यद्यपि आरआईएल का समर्थन पत्र याचिका का हिस्सा है तथापि आईओसीएल ने समर्थन का अपना पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा है।

14. पीओआई के दौरान आवेदकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और वे नियम 5(3) के अनुसार योग्यता को पूरा करते हैं और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के पात्र हैं।

15. जॉच शुरूआत के बाद, हितबद्ध पक्षों ने यह दलील दी कि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा कम है और विचाराधीन उत्पाद के अन्य कड़े उत्पादकों ने अपनी क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। आरआईएल ने जॉच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है। आरआईएल द्वारा प्रदत्त सूचना सार्वजनिक फाइल के जरिए हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई थी और विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने उस पर टिप्पणियां भी दी थी। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आरआईएल ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है न ही वे भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। आरआईएल द्वारा प्रदत्त सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनके परिसर में मौके पर सत्यापन करके सत्यापित किया है। इसके अलावा, आरआईएल ने प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सूचना प्रदान की है।

16. यह आवेदन मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. द्वारा दायर किया गया है। निम्नांकित तालिका पीयूसी के उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा दर्शाती है।

भारतीय उत्पादन का विवरण				
	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
टीएनपीएल	***	***	***	***
निरमा	***	***	***	***
याचिकाकर्ता	185,781	173,646	138,651	184,836
आरआईएल	***	***	***	***
आईओसीएल	***	***	***	***
याचिकाकर्ता समर्थकों सहित	453,722	455,618	421,962	519,420
विभिन्न पक्षों का हिस्सा				
टीएनपीएल	***	***	***	***
निरमा	***	***	***	***

याचिकाकर्ता	41%	38%	33%	36%
आरआईएल	37%	36%	39%	36%
आईओसीएल	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	100%	100%	100%	100%

जैसा ऊपर नोट किया गया है मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने भी पहले याचिका का समर्थन किया है। आवेदन के पास प्रमुख हिस्सा भी है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) और नियम 2(ख) के अधीन घरेलू उद्योग की योग्यता को भी पूरा करते हैं। तथापि मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने जाँच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी आकड़े और उत्पादन लागत प्रदान की है प्राधिकारी ने उस पर विचार किया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया है। इस शामिल करने के बाद, घरेलू उद्योग अर्थात मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का हिस्सा निम्नानुसार है

घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल होने पर भारतीय उत्पादन का विवरण				
	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
घरेलू उद्योग	351,722	336,098	302,442	370,020
आईओसीएल (समर्थक)	***	***	***	***
समर्थक के साथ घरेलू उद्योग	453,722	455,618	421,962	519,420
विभिन्न पक्षों का हिस्सा	%			
घरेलू उद्योग	78%	74%	72%	71%
आईओसीएल	22%	26%	28%	29%
कुल भारतीय उत्पादन	100%	100%	100%	100%

17. इस बात पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) के अधीन समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के रूप में या ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका समग्र उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा कम है, और यह कि केवल आरआईएल का ही हिस्सा भारतीय उत्पादन में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग में आरआईएल के जुड़ने से घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 78 प्रतिशत हो गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ अपीलिया निकाय ने माना है कि सकल घरेलू उत्पादन में उत्पादकों का हिस्सा पर्याप्त होना चाहिए और यह कि प्राधिकारी को किसी मामले विशेष में यथासंभव अधिकाधिक उत्पादक घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने चाहिए। प्राधिकारी उक्त को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों पर विचार करके आरआईएल के आकड़ों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करना उचित समझते हैं और मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि., मै. निरमा लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग मानते हैं।

#### **ड. गोपनीयता**

18. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

### **निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार**

19. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :

क. याचिका में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के संबंध में विरोधाभासी आकड़ें दायर किये गए हैं जिन्हें घरेलू उद्योग ने 2 जून 2016 के अपने पत्र में भी स्वीकार किया है जिसमें यह बताया गया है कि गोपनीय अंश में सही आकड़े हैं। तथापि सही सूचना हितबद्ध पक्षों को कभी भी प्रदान नहीं की गई। याचिका के अगोपनीय अंश में आकड़े सही नहीं हैं जो एडी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन है।

ख. सामान्य मूल्य की गणना की हर बात को गोपनीय रखा गया है।

### **घरेलू उद्योग के विचार**

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. याचिका में प्रदत्त आकड़ों में एक छोटी सी मामूली गलती हुई है। इस त्रुटि को बाद में सार्वजनिक सुनवाई से काफी पहले सुधार दिया गया। यह त्रुटि बिल्कुल अप्रासंगिक है क्योंकि वह वर्ष 2013-14 के लिए कटौती तालिका में बताई गई आयात मात्रा में थी जो वर्तमान मामले में पीओआई नहीं है। इसके अलावा, कीमत कटौती सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई जिसे सही बताया गया।

ख. समस्त सूचना विधिक प्रावधान के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुसार अगोपनीय अंश में प्रदान की गई है। केवल उसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है जिसे याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जॉच**

21. प्राधिकारी मानते हैं कि हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता की अपेक्षा को पूरा करती है। प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है। ऐसी सूचना जिसे गोपनीय माना गया है को अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों से गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्राधिकारी ने इस पहलू के संबंध में एक संगत प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के ऐसे अगोपनीय अंश को उपलब्ध रखा है।

### **च. विविध मुद्दे**

### **निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार**

22. हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

क. जॉच की शुरुआत के समय, आवेदन के गोपनीय और अगोपनीय दोनों अंशों को प्राधिकारी की फाइल में होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.3 पर भरोसा करते हुए, याचिका की प्रति प्रदान करने में 37 दिनों की देरी को तत्काल कार्रवाई नहीं माना जा सकता है इसलिए वर्तमान जॉच का समाप्त किया जाना चाहिए।

ख. हितबद्ध पक्षों को प्रदत्त दस्तावेज जॉच की शुरुआत के अलग आवेदन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्राधिकारी उनके आधार पर जॉच की शुरुआत नहीं करते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सउदी अरब से संबंधित सूचना शामिल थी तथापि हितबद्ध पक्षों को प्रदान की गई आवेदन की प्रति में सउदी अरब से संबंधित कोई आकड़े नहीं हैं इसलिए वर्तमान जॉच को समाप्त करना चाहिए।

ग. जॉच की शुरुआत के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त आवेदन हितबद्ध पक्षों के लिए संगत दस्तावेज/साक्ष्य का एक हिस्सा है और हितबद्ध पक्षों के पास पाटनरोधी जॉच की शुरुआत के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त समस्त सूचना तक पहुंच होनी चाहिए। वर्तमान जॉच में अनुच्छेद 6.4 का उल्लंघन हुआ है इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

घ. वर्तमान जॉच में जॉच शुरुआत का आवेदन जॉच शुरुआत की सूचना में प्रकाशित सूचना के आधार पर जॉच शुरुआत के बाद दायर किया गया है।

ड. हितबद्ध पक्षों को जॉच की शुरुआत के लिए आवेदन प्रदान किया जाना चाहिए :

- i. उनके पास जॉच की शुरुआत पर टिप्पणी करने का अधिकार है। इसके अलावा नियम 5(3) डीए को (क) और (ख) में शर्तों को पूरा किए बिना जॉच की शुरुआत करने से निषिद्ध करता है।
- ii. अप्रैल 2015 से जून 2015 तक चीन से आयात 10584 मी.टन हैं औ यदि पीओआई के लिए आयात में अप्रैल 2015 से जून 2015 के आयात शामिल हैं तो पीओआई के लिए अप्रैल 2014 से जून 2014 के आयात केवल 9720 मी. टन थे जो इस तथ्य के साथ है कि दो लगातार पूर्ववर्ती वर्षों में कोई आयात नहीं हुए हैं और 2011-12 में नगण्य रहे हैं। ईरान का भी ऐसा ही मामला है जिसमें पीओआई के दौरान आयात मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम थी। इस प्रकार जॉच शुरुआत नियम 5 को पूरा नहीं करती है।
- iii. आवेदन में आकड़े के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सत्यता का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे जॉच की शुरुआत के बाद दायर किया गया है। आयातों का कुल सीआईएफ मूल्य संबद्ध देशों के लिए लाख रुपये में प्रत्येक देश से आयातों के सीआईएफ मूल्य के योग के बराबर नहीं है जिससे मामूली कीमत कटौती को भारी कटौती बना दिया गया है।
- iv. निरमा के लिए उत्पादन के आकड़े केवल पीओआई के लिए हैं क्योंकि क्षमता भी दर्शाई गई है और आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन क्षति संबंधी विवरण के आकड़ों से मेल नहीं खाता है।
- v. घरेलू उद्योग को आवेदन के केवल गोपनीय अंश में ही सही सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- vi. सउदी अरब से पंहुच कीमत संशोधित जॉच अवधि के दौरान कतर और चीन की कीमत से काफी अधिक नहीं है। इसके अलावा आवेदन मार्च 2015 तक की अवधि के लिए सीमित है जिससे प्राधिकारी कतर और चीन के विरुद्ध जॉच की शुरुआत करने में सक्षम हुए हैं। नये आवेदन में घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करने में सक्षम बनाने की सूचना नहीं है कि अन्य देशों से क्षति मार्जिन सकारात्मक था।
- vii. घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती आवेदन में केवल डीजीसीआईएंडएस के आयात टी/टी आकड़े प्रदान किए होंगे और उसी को नये आवेदन के मुद्रित रूप में दायर किया गया है अर्थात कोई साफ्ट प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- viii. प्राधिकारी ने आवेदन दायर करने की योग्यता निर्धारित करने के लिए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के आकड़ों की जॉच नहीं की है क्योंकि पीओआई और क्षति अवधि के आकड़े जॉच की शुरुआत के समय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं कराए गए।

च. सउदी अरब को बिना किसी आधार के संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखा गया है:

- i. सउदी अरब से आयात पीओआई के दौरान ईरान से आयातों का लगभग दुगना और चीन से आयातों के तीन गुने से अधिक हो गये हैं।
- ii. जॉच अवधि के दौरान सउदी अरब से आयात संबद्ध देशों से तुलनीय कीमत पर भारत में आये हैं।
- iii. हाल की अधिकांश अवधि (अप्रैल 2015 से जून 2015) के दौरान सउदी अरब से आयात भारत में सभी संबद्ध देशों की तुलना में कम कीमत पर आए हैं। भारतीय कानून और डब्लूटीओ कानून दोनों में से किसी में भी इस आधार पर किसी देश को संबद्ध देश मानने पर कोई रोक नहीं है कि क्या पीओआई की प्रत्येक तिमाही या माह में आयात प्रभावित हुए हैं।

छ. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के संबंध में याचिका में दिए गए विरोधाभासी विवरणों के बावजूद वर्तमान जॉच में एक आम सुनवाई की जिससे प्रदत्त सूचना के संबंध में सार्थक रूप से टिप्पणी करने के लिए निर्यातकों को एक उचित अवसर नहीं दिया गया है।

ज. हितबद्ध पक्षकार आईओसीएल द्वारा प्रदत्त कथित समर्थन पत्र को नहीं देख पाये हैं।

### घरेलू उद्योग के विचार

23. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं :

- i. घरेलू उद्योग ने जांच प्रारंभ होने के बाद तत्काल याचिका के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराईं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अद्यतन याचिका को परिचालित करना उचित समझा। प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए आंकड़े भरने की जरूरत के बारे में सूचित किए जाने पर, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए सभी संगत सूचना और प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए सभी संगत सूचना समेकित भी की है।
- ii. चूंकि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को सूचना मांगने संबंधी पत्र जारी होने के बाद उनके हितों की संरक्षा के लिए 40 दिन का समय प्रदान किया है, इसलिए प्रश्नावली जारी होने और याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने में कथित विलंब के कारण किसी पक्षपात का दावा नहीं किया जा सकता। यह ऐसी स्थिति नहीं है कि प्राधिकारी ने पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिनों का समय प्रदान नहीं किया है। अतः जहां तक संरक्षा के अधिकार का संबंध है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया है।

- iii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और अनुरोध करने के लिए जांच शुरू होने की तारीख से 90 दिनों का समय प्रदान किया था। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि पक्षकारों को जांच शुरू होने से 37 दिनों तक याचिका प्राप्त नहीं हुई थी, तो भी किसी भी तरह से पक्षकारों को याचिका उपलब्ध कराने के बाद पक्षकारों के पास प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और अनुरोध करने के लिए 53 दिनों का समय उपलब्ध था। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पक्षकारों को 53 दिनों का प्रभावी समय दिया था जबकि नियमों में दस्तावेज भेजने के लिए केवल 30 दिनों और 7 दिनों का प्रावधान है। अतः नियमों और करार के तहत 37 दिन प्रदान करने के स्थान पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने के बाद हितबद्ध पक्षकारों को 53 दिन का समय प्रदान किया था।
- iv. मैक्सिको से डब्ल्यूटीओ पैनल ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट में, पैनल ने यह भी विश्लेषण किया था कि क्या उल्लंघनों से पाटनरोधी करार के तहत सदस्य देश को होने वाले लाभ अप्रभावी अथवा बाधित हो गए। वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों के संरक्षण के लिए 40 दिन का समय प्रदान किया गया है।
- v. कतर में उत्पादकों ने इनवॉयस के पश्चात छूट प्रदान की है। वस्तुओं की ऊंची कीमत पर इनवॉयस प्राप्त की जाती है और बाद में निर्यातक आयातकों को छूट देते हैं।
- vi. सऊदी अरब को जांच से बाहर करने के संबंध में, यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने सऊदी अरब के संबंध में याचिका दाखिल की है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नकारात्मक क्षति मार्जिन के आधार पर उसे निकालकर न्यायोचित कार्य किया है, क्योंकि भारत कमतर शुल्क नियम को अपनाता है और क्षति मार्जिन में जांच की अवधि के दौरान सुधार नहीं हो सकता। संबद्ध देशों से आयात सऊदी अरब से हुए आयात की बजाए कमतर मूल्य पर आ रहे हैं। आईओसीएल ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपना पत्र सीधे भेजा था, जो वह हितबद्ध पक्षकारों को भेज सकता है।
- vii. जहां तक विरोधात्मक विवरण के बावजूद सार्वजनिक सुनवाई करने का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने डीजीएडी के पास जन सुनवाई होने से यथा समय पूर्व दिनांक 2 जून, 2016 के एक पत्र में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के बारे में सही सूचना प्रदान की है।

आईओसीएल ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सीधे अपना पत्र भेजा था, जो वह हितबद्ध पक्षकारों को भेज सकता है।

#### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उपरोक्त विविध अनुरोधों का विश्लेषण किया है, जो इस प्रकार है:

- i. इस तर्क के संबंध में कि याचिका को जांच शुरू करने से 37 दिनों के विलंब के बाद परिचालित किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस मामले के लिए चुनी गई जांच की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं से अद्यतन सूचना मांगना उचित समझा है और उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के अद्यतन आंकड़ों सहित याचिका के साथ प्रश्नावली जारी करना उचित समझा। प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और उनके हितों का संरक्षण करने के लिए कोई अन्य सूचना प्रदान करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को याचिका परिचालित करने की तारीख से 40 दिन का समय प्रदान किया। उसके बाद कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और अपना अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे वर्तमान मामले में उदारतापूर्वक प्रदान कर दिया गया था। इसके अलावा, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई की अवस्था में पहली बार के लिए अपने कानूनी अनुरोध किए, जो जांच शुरू होने के 184 दिनों के बाद शुरू हुई थी। तथापि, प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने और इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी और जांच में उन पर विचार भी किया गया है। प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी हितबद्ध पक्षकार अपने हितों के संरक्षण के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अवसर प्राप्त करें और इस आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार को परेशान नहीं होने दिया है कि उनके द्वारा किए गए अनुरोध विलंब से है। वास्तव में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारंभिक मामले, जैसे आयातित और घरेलू उत्पाद के मोलिक्यूलर भार में कथित अंतर जांच शुरू होने के बाद पहली बार उठे हैं और अब इन पर प्राधिकारी द्वारा विचार करके इनका समाधान किया है।
- ii. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने याचिका प्रदान नहीं की है, जिस पर जांच शुरू करने के लिए विचार किया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विचार की जा रही जांच की अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों पर टिप्पणियों के साथ जांच की उत्तर देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को उचित और सार्थक अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णित अद्यतन अवधि के लिए सूचना और जांच शुरू करने के लिए प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय मानी गई याचिका, दोनों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई। यह हितबद्ध पक्षकारों को प्रभावी अवसर प्रदान करने और जांच शुरू करने के प्रयोजन से संगत आंकड़े और अवधि पर टिप्पणियां चाहने और उसके बाद इस जांच के तहत निर्धारण करने के लिए किया गया था। जांच शुरू करने के लिए प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय मानी गई याचिका की एक प्रति वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई थी और अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने संकलित करके उन पर टिप्पणियां प्रदान की हैं।

- iii. इस तर्क के संबंध में कि ईरान और चीन से आयात घरेलू उद्योग द्वारा मूल जांच में विचार की गई जांच की अवधि के लिए काफी कम प्रतीत होते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों के अंश पर संतुष्ट होने के बाद ही वर्तमान जांच शुरू की गई थी। वास्तव में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा नहीं किया कि इन देशों से आयातों का अंश बहुत ही कम था।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे गलत आंकड़े दिए गए हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गई थी और उसके बाद उसे जांच शुरू करने के प्रयोजन से स्वीकार किया गया था।
- v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र का जांच की अवधि के लिए विश्लेषण नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के समय आधार का निर्धारण उस अवधि के लिए याचिका में शामिल सूचना पर आधारित है जिसके लिए याचिका में आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्तमान मामले में, यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग के पास उनकी जांच में घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई जांच की अवधि के लिए अपेक्षित आधार था। यहां तक कि ऐसे मामले में, जहां जांच की अवधि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित अनुसार रखी गई है, आधार की वास्तविकता का आगे सत्यापन किया जा सकता है और जांच की जा सकती है। रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि में प्रथम दृष्टया आधार नहीं रखा है। जहां याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि में पर्याप्त आधार नहीं दिया हो, जांच को नियम 14 के तहत समाप्त किया जाना चाहिए था। हितबद्ध पक्षकार का तर्क इस आधार को पुष्ट करता है कि प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाई गई जांच की अवधि से भिन्न अवधि नहीं चुन सकते। तथापि, प्राधिकारी पर याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा प्रस्तावित अवधि के लिए विचार करने की कोई बाध्यता भी नहीं है। विस्तृत जांच के लिए जांच की अवधि याचिका में प्रस्तावित जांच की अवधि से ज्यादा अलग नहीं हो सकती। जैसा कि इस जांच परिणाम के संगत भाग में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग ने इस जांच में अपेक्षित आधार पर विचार किया है और यह प्रस्तावित और स्वीकार की गई जांच की अवधि में नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- vi. जहां तक सऊदी अरब को निकालने का संबंध है, प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ करने की अवस्था में सऊदी अरब से आयातों की जांच की थी और यह पाया था कि सऊदी अरब से आयातों के मामले में क्षति मार्जिन नकारात्मक था। अतः सऊदी अरब को वर्तमान जांच में एक संबद्ध देश के रूप में नहीं माना गया। वास्तव में, चीन, कतर और सऊदी अरब से अलग कीमतों में काफी भिन्नता थी। इसके अलावा, जांच के दौरान प्राधिकारी उपरोक्त की पुष्टि करते हैं कि सऊदी अरब से आयातों का क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

#### छ. सामान्य मूल्य (एनवी), निर्यात कीमत (ईपी) और पाटन मार्जिन (डीएम)

##### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित निम्नलिखित मामले उठाए हैं:
  - क. ईरान और कतर के लिए परिकल्पित किया गया मूल्य अधिनियम की धारा 9क(1ग), पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 तथा डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद-2 का उल्लंघन है क्योंकि इसके लिए भारतीय घरेलू उत्पादकों से संबंधित कुछ लागत घटकों और अन्य देशों के संबंध में कुछ लागत घटकों का उपयोग करके गणना की गई है। सूचना उपलब्ध न होना ऐसी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए एक कारक नहीं हो सकता जो लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
  - ख. ईरान और कतर में निर्माताओं द्वारा एन-पैराफिन का उत्पादन एलएबी के निर्माण के लिए खरीद करने की बजाए कैरोसिन से किया जाता है। अतः ईरान और कतर के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने के लिए एन-पैराफिन की आयात कीमतों का उल्लेख गलत है।
  - ग. चीन के लिए सामान्य मूल्य की गणना भी गलत है क्योंकि ऐसा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के पहले 2 विकल्पों को समाप्त किए बिना अंतिम विकल्प के आधार पर किया गया है।
  - घ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए किए गए समायोजनों के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
  - ङ. त्रुटिपूर्ण सामान्य शुल्क और कमतर निर्यात कीमत के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन से पाटन मार्जिन के कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। संबद्ध देशों के लिए निर्धारित किया गया कथित पाटन मार्जिन जांच की अवधि में कुछ तिमाहियों के दौरान नकारात्मक और शून्य रहा है। अतः संबद्ध देशों से बढ़ाए गए पाटन मार्जिन आयातों के साथ भी भारत में पाटन नहीं हुआ है।

- च. मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स, जो मैसर्स एसईईएफ, मैसर्स मुंताजत और मैसर्स रेनिश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ने अपने दिनांक 28 दिसंबर, 2016 के पत्र के तहत यह कहा है कि सामान्य मूल्य के लिए सऊदी अरब जैसे देशों को तीसरे देश की बिक्री पर विचार करते हुए विभिन्न उपभोक्ता प्रोफाइल, व्यापार के स्तर आदि के कारण उचित नहीं हो सकता।

### घरेलू उद्योग के विचार

26. सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन के पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा जांची गई स्थिति के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।
- ii. बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति तब तक प्रदान नहीं की जा सकती, जब तक कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा न कर लिया जाए:
  - क. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई एक प्रमुख शेयरधारक राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्था न हो।
  - ख. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित न कर दें कि प्रमुख निविष्टियों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार के मूल्यों को दर्शाती है।
  - ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित न कर दें कि उनके खातों की अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गई है।
  - घ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक मानदंड की भी संतुष्टि नहीं हुई हो।
  - ङ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदारी चीन के प्रतिवादी निर्यातकों की है न कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की।
  - च. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसकी समूह कंपनियां मिलकर दावा न करें।
  - छ. ऐसी स्थिति में, जहां पर कि वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, लेकिन किसी अन्य पक्षकार से अर्जित की हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि परिवर्तन की प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से पूरी तरह से प्रमाणित न हो जाए।

27. सामान्य मूल्य का निर्धारण ऐसे कारण से एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर नहीं हो सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
28. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत का विधिवत समायोजन करने के बाद किया गया है।
29. ईरान और कतर के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में एलएबी की बिक्री की वास्तविक लेन-देन कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और संबद्ध देश से अन्य देशों को किए जा रहे निर्यात की सामग्री की कीमत के लिए प्रयास किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता संबद्ध देश के घरेलू बाजार के लिए अथवा अन्य देशों को निर्यातों के लिए सौदा कीमतों के पर्याप्त और वास्तविक साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अतः याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
30. जहां तक निर्यात कीमत समायोजनों के लिए साक्ष्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने उपलब्धता के अनुसार साक्ष्य प्रदान किए हैं और जहां कहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, सर्वाधिक रूढ़िवादी अनुमान दिए हैं।
31. जहां तक एन-पैराफिन का भी संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने सर्वाधिक उपलब्ध सूचना का उपयोग किया है। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातों से उत्तर दाखिल किए गए हैं, प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उन पर विचार किए जाने की संभावना है।
32. जहां तक चीन के सामान्य मूल्य के लिए पहली दो पद्धतियों का उपयोग करने का संबंध है, यह कहा जाता है कि सबसे पहले तो संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और दूसरे याचिकाकर्ता एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में एक उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।
33. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों के तहत परिकलित किए गए हैं। इस प्रकार से निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न केवल न्यून से अधिक है बल्कि पर्याप्त भी है।

## प्राधिकारी द्वारा जांच

### पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली – चीन

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि धारा 9 (क) (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:

*"व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो; अथवा*

*जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-*

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

*वशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।"*

34. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के तहत एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किए जाने की जरूरत है, यदि चीन जन गण से निर्यातक पैरा 8 में उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करे और इसे विरोधी प्रमाणित करे। चीन से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की जरूरत थी ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) दर्जा प्रदान करने के लिए विचार कर सके।

35. प्राधिकारी ने चीन से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और उन्हें यह परामर्श दिया कि निर्धारित प्रश्नावली में निर्धारित रूप से और निर्धारित तरीके से तथा साथ ही उपरोक्त पैरा (35) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना उपलब्ध कराए। तथापि, केवल मैसर्स जियांग्सू जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए दावा नहीं किया था।

चूंकि चीन की किसी भी कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था के पहलु का निर्धारण नहीं किया है और नियम 6(8) के तहत सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के मूल्यांकन की संगत कार्यप्रणाली अपनाई है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स जियांग्सू जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड ने दो संगत संस्थाओं अर्थात् मैसर्स शार्पइन्वेस्ट और मैसर्स होटुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से तीन सौदों में वस्तुओं का निर्यात किया है जिसकी मात्रा \*\*\* मी. टन है और दो वास्तविक प्रयोक्ताओं को सीधे \*\*\* मी. टन का निर्यात किया है। मैसर्स शार्पइन्वेस्ट और मैसर्स होटुंग केमिकल कारपोरेशन ने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं। उसने किसी असंगत व्यापारी, डिनो-विक को \*\*\* मी. टन की बिक्री की है जिसने सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा संगत संस्थाओं के माध्यम से और सीधे भारत को अपनी बिक्रियों पर प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए विश्लेषण किया है और अन्य माध्यमों के लिए, जहां पर कि व्यापारी ने भाग लिया, विश्लेषण व्यवहार्य नहीं है। अतः सहयोगी उत्पादक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण निर्यातों के इनके सहयोगी माध्यमों तक सीमित है और उत्तर न देने वाले निर्यात माध्यम अवशिष्ट श्रेणी के भाग के रूप में माने गए हैं। पाटन मार्जिन का मूल्यांकन भारतीय औसत के आधार पर समग्र जांच की अवधि के लिए किया गया है।

### चीन में सामान्य मूल्य

चूंकि चीन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सामान्य मूल्य के संबंध में उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के तहत ऊर्जा लागतों, मानक परिवर्तन लागतों, एसजीए और उत्पादन लागत पर \*\*\*% के एक तर्कसंगत लाभ के संबंध में समायोजनों के साथ भारत में उत्पादन की लागत अपनाकर नियम 6 (8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य \*\*\* डॉलर/मी. टन होता है।



### **चीन में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

36. प्राधिकारी ने मैसर्स जियांग्सू जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के अलग-अलग निर्यातों के दो माध्यमों की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

मैसर्स जियांग्सू जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मैसर्स शार्पइन्वेस्ट और मैसर्स होटुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से \*\*\* मी. टन निर्यातों की कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिसमें बैंक प्रभारों, ऋण लागत, पैकिंग और सीमा शुल्क ब्रॉकर चार्ज के लिए सकल सीआईएफ, इनवॉयस मूल्य से, जिसे \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन (सीआईएफ) माना गया है, क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के समायोजनों पर विचार किया गया है। कारखाना बाह्य कीमत \*\*\* डॉलर/मी. टन होती है।

मैसर्स जियांग्सू जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के भारत में वास्तविक प्रयोक्ताओं को सीधे कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिसमें बैंक प्रभारों, ऋण लागत, पैकिंग और सीमा शुल्क ब्रॉकर चार्ज के लिए सकल सीआईएफ, इनवॉयस मूल्य से, जिसे \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन (सीआईएफ) माना गया है, क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के समायोजनों पर विचार किया गया है। दो माध्यमों के पहुँच मूल्य की लागू बुनियादी सीमा शुल्क और पहुँच मूल्य पर उप शुल्क का प्रयोग करके गणना की गई है, जिसे सीआईएफ आयात कीमत और \*\*\*% पहुँच प्रभार के रूप में विचार किया गया है। एफओबी/सीएफआर पर लेन-देन को यथा लागू बीमा/समुद्री माल-भाड़े पर समुचित व्यय को शामिल करके सीआईएफ में परिवर्तित किया गया है। असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए उच्चतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सहयोगी माध्यमों के मार्जिन से अपनाया गया है।

### **ईरान और कतर के लिए पाटन मार्जिन**

37. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी है। कतर के मूल के विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया गया था। तथापि, ईरान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके इस जांच में सहयोग नहीं किया है।

- मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड, कतर (उत्पादक)
- मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी., कतर (निर्यातक)
- मैसर्स रेनिश पेट्रोकेम एफजेडई

### **कतर के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण**

कतर में उत्पादक और निर्यातक से प्रश्नावली उत्तर को देखते हुए प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण कतर से उत्पादक और निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के आधार पर किया गया है। पाटन मार्जिन का निर्धारण दो माध्यमों अर्थात् मुंताजात से भारत के माध्यम से और मुंताजात व रेनिश से भारत के माध्यम से अलग-अलग किया गया है। एसईईएफ, कतर के संबंध में पाटन मूल्यांकन के पहलुओं पर विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के तहत एसजीए और सामान्य लाभों के साथ जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत पर परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार करते हैं। उत्तर न देने वाले माध्यमों, अर्थात् मैसर्स वेस्ट फोर्ड के लिए पाटन और क्षति मार्जिन पर असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार विचार किया गया है, अर्थात् सहयोगी माध्यमों के लिए मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर विचार किया गया है।

मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड, उत्पादक और उसके सहयोगी निर्यातक अर्थात् मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी. ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। निर्यातक और उत्पादक का मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी., निर्यातक को विशेष बिक्री अधिकार प्रदान करने के संबंध में एक करार है जिसके तहत सभी स्थानों अर्थात् घरेलू बाजार, भारत और भारत के अलावा अन्य देशों को मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की समस्त मात्रा की बिक्री के लिए एक सहमत विपणन शुल्क फार्मूला है। जांच की अवधि के दौरान निर्यातक ने भारत को \*\*\* मी. टन संबद्ध वस्तुओं और भारत के अलावा अन्य देशों को \*\*\* मी. टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की जिसमें उनके घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं थी। निर्यातक ने भारत से बाहर के व्यापारियों के माध्यम से भारत को आगे निर्यात किया है और भारत में ऐसी आयातक संस्थाओं को भी सीधे निर्यात किया है, जो व्यापारी भी हैं। मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी. के अलावा मैसर्स रेनिश पेट्रोकेम एफजेडई, व्यापारी, यूएई द्वारा उत्तर दाखिल किया गया था। जांच की अवधि में भारत को \*\*\* मी. टन बिक्री में से मैसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी. ने भारत में मैसर्स अर्डोर ग्रुप (3 आयातक) को \*\*\* मी. टन और मैसर्स रेनिश पेट्रोकेम एफजेडई के माध्यम से \*\*\* मी. टन निर्यात किया है।

39. पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत की कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की तुलना सामान्य मूल्य के साथ की गई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है।
40. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक संबद्ध देशों से किए गए निर्यातों के संबंध में नियमों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।

**पाटन मार्जिन****क.**

		कतर		
क्र.सं.	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन अम.डॉ./मी.ट.	पाटन मार्जिन % (रेंज)
i.	मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंताजात	***	0 - 10
ii.	पाटन मार्जिन	मै. मुंताजात और मै. रेनिश पेट्रोकेम एफजेडई (ट्रेडर)	***	30 - 40
iii.	मै. सीफ	उपरोक्त i तथा ii की भारित औसत	***	0- 5
iv.	कोई	कोई	***	30 - 40

**ख.**

		चीन जन. गण.		
क्रम सं.	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन % (रेंज)
i.	मैसर्स जियांग्सु जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड	मैसर्स हुतोंग केमिकल कारपोरेशन और मैसर्स शार्प इनवेस्ट	***	10 - 20
ii.	मैसर्स जियांग्सु जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड	मैसर्स जियांग्सु जितुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड	***	20 - 30
iii.	उपरोक्त (i) और (ii) के अलावा कोई अन्य	उपरोक्त (i) और (ii) के अलावा कोई अन्य	***	20 - 30

**ग.**

		ईरान		
क्रम सं.	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन % (रेंज)
i.	कोई	कोई	***	10 - 20

**ज. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संबंध**

41. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी भी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाएं "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए .....". कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा

क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में कीमतों में अन्यथा कोई कटौती हुई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हो गई होती।

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए आवेदन संबंधित उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से मैसर्स निरमा लि. तथा मैसर्स तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. द्वारा किया गया है और उसे आईओसीएल तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा समर्थन किया गया था। तथापि, बाद में जांच शुरू करने के समय, प्राधिकारी ने मैसर्स निरमा लि., मैसर्स तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. की घरेलू उद्योग के रूप में प्रयोज्यता पर विचार किया है। तथापि, जांच के दौरान मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., जिसने प्रारंभ में याचिका का समर्थन किया है, ने आंकड़े प्रदान किए जिसकी पुष्टि की गई है। अंतिम निर्धारण की अवस्था में सभी 3 उत्पादक अर्थात् मैसर्स निरमा, मैसर्स तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग माना गया है। अतः निर्धारण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की लागत और क्षति की सूचना, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, की जांच की गई है।

#### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

43. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित मामले उठाए हैं :
- क. याचिकाकर्ताओं की बिक्री की प्रवृत्ति और बाजार अंश अन्य भारतीय उत्पादकों से बिल्कुल विपरीत है।
  - ख. संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों जैसे (क) स्टॉक की मात्रा, (ख) कर्मचारियों की संख्या, (ग) मजदूरी, (घ) उत्पादन, (ङ) घरेलू बिक्रियां, (च) बाजार अंश, (छ) लाभप्रदता और (ज) पूंजी पर प्रतिफल का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
  - ग. चीन जन. गण. से वस्तुओं की दर क्षति अवधि में आईएनआर/मी. टन 94632 से बढ़कर आईएनआर/मी. टन 96381 हुई है। निर्धारणीय मूल्य भी आईएनआर/मी. टन 95578 से बढ़कर आईएनआर/मी. टन 97344 हो गया है।
  - घ. कारणात्मक संबंध में कमी है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, तो वह अन्य कारकों के कारण हो सकती है, जैसा कि टीएनपीएल द्वारा अपनी 2014-15 की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।
  - ङ. निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, पूंजीगत उपयोग, उत्पादकता, मजदूरी और वस्तु सूची के संदर्भ में सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा, दो निष्पादकों का निष्पादन बिल्कुल अलग है कि टीएनपीएल ने निरमा से अलग निष्पादन किया है।
  - च. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 26% तक की वृद्धि होने के बारे में बताया गया है जबकि याचिकाकर्ताओं की बिक्री में क्षति अवधि के दौरान 8% तक की वृद्धि हुई है। तथापि, अन्य देशों से आयातों की मात्रा में 197% तक की पर्याप्त वृद्धि हुई है।
  - छ. याचिकाकर्ताओं द्वारा संबद्ध देशों और अन्य देशों से किए गए आयातों की कीमत से 10% कम तक कीमतें गिरी हैं।
  - ज. सऊदी अरब के आयातों की मात्रा और कीमतों, दोनों के संदर्भ में काफी प्रभाव पड़ा है।
  - झ. अन्य आर्थिक कारक जैसे बिक्री की मात्रा, बाजार अंश और उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। अंत स्टॉक में उल्लेखनीय कमी आई है और मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संबद्ध देश के आयातों में गिरावट के लिए यह आरोप नहीं लगाया गया था कि ये पाटित कीमतों पर हुए थे और याचिकाकर्ताओं की बिक्रियां और उत्पादन पर्याप्त रूप से कम हो रही थी तथा बाजार अंश स्थिर रहा जबकि वस्तु सूचियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
  - ञ. वर्ष 2012-13 और 2013-14 में जबकि आयातों की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, याचिकाकर्ताओं की घरेलू कीमतों में भी वृद्धि हो रही थी।
  - ट. टीएनपीएल कतर से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से क्षति का सामना नहीं कर सकता क्योंकि टीएनपीएल भारत के दक्षिण-पूर्व में स्थापित है जबकि निर्यातक केवल उत्तर-पश्चिम को ही बिक्री करता है।
  - ठ. निरमा एक डिजिट निर्माता है, जिसके पास अपना स्वयं का एलएबी तैयार करने के लिए एक बैकवर्ड इंटीग्रेटिड प्लांट है और इसीलिए यह कतर से संबद्ध आयातों का सीधे मुकाबला नहीं करता। निरमा के लिए अपने एलएबी को सीधे प्रतिस्पर्द्धियों को बिक्री करना मुश्किल है और इसको बाजार अंश में गैर- डिजिट और गैर- एलएबी आधारित उद्योगों की ओर ध्यान केंद्रित होने के कारण गिरावट आई है।
  - ड. याचिकाकर्ता संगठित नहीं हैं और इसीलिए उनकी लागतें प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं। टीएनपीएल पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जैसा कि इसकी वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है।
  - ढ. कैरोसिन की उच्च लागतों और फीड स्टॉक की गुणवत्ता के मामलों के कारण, जैसा कि टीएनपीएल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, भारत में एलएबी की उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अपेक्षाकृत अधिक रही है।
  - ण. याचिकाकर्ताओं ने हानि उठानी शुरू कर दी है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और नकदी प्रवाह के मामलों में भी कमी आई है, जैसा कि टीएनपीएल द्वारा अपनी वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।

- त. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां याचिकाकर्ताओं की बिक्रियों की मात्रा से लगभग दोगुनी है। साथ ही, अन्य उत्पादकों की बिक्रियों में क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि घरेलू उद्योगों की बिक्रियों में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में कमी आई है, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में इस अवधि में वृद्धि हुई है।
- थ. आरआईएल और आईओसीएल, दोनों ही याचिकाकर्ताओं की तरह संगठित नहीं हैं, परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कंपनियों का आरआईएल और आईओसीएल की तुलना में काफी नुकसान है। चूंकि घरेलू उद्योग फीड स्टॉक की आपूर्ति के लिए आरआईएल और आईओसीएल पर भरोसा करता है, घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है।
- द. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा की प्रवृत्ति वही रही है, जो प्रवृत्ति घरेलू उद्योग की बिक्रियों के मामले में रही है। साथ ही, वर्ष 2013-14 के दौरान जबकि संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई थी, यही स्थिति घरेलू उद्योग की बिक्रियों के मामले में रही। अतः यदि सभी घरेलू उद्योगों को नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो इसका कारण अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां रहा है।
- ध. कुछेक घरेलू उत्पादकों के समक्ष बिजली की समस्याएं रही हैं, जिससे उनकी निर्धारित लागतों में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की एलएबी की उत्पादन की लागतें उच्चतर कच्ची सामग्री कीमतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक हैं, जैसा कि टीएनपीएल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।
- न. टीएनपीएल के समक्ष कैरोसिन को सामान्य पैराफिन में बदलने के संबंध में समस्या है, जो कि क्षति का एक स्रोत है, जैसा कि टीएनपीएल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।
- प. निरमा लि. का आंतरिक अंतरण विगत चार वर्षों के दौरान कम हुआ है, जिसकी क्षति आकलन में जांच की जानी चाहिए।
- फ. संबद्ध देशों से आयात सऊदी अरब के आयातों की तुलना में उसी कीमत पर है। यदि सऊदी अरब के आयातों की जांच समाप्त करने का कारण नकारात्मक क्षति मार्जिन पर आधारित है तो संबद्ध देशों से आयात का घरेलू उद्योग की बिक्री पर नकारात्मक कीमत प्रभाव नहीं पाया जा सकता। जांच की अवधि में चीन जन गण से कीमतें सऊदी अरब की कीमतों से केवल 2% कम थी और ईरान तथा कतर से आयात की कीमत सऊदी अरब की कीमतों से केवल क्रमशः 4% और 2% कम थी।
- ब. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों, जैसे उत्पादन, क्षमता, उपयोग, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य और वस्तु सूची में कोई गिरावट नहीं है।
- भ. याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों के अनुसार फराबी की कीमत और चीन की कीमत के बीच अंतर केवल 2% का है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को फराबी के मामले में नकारात्मक मार्जिन का पता चला है और उसे जीओसी के मामले में प्रयोग किया जाए।
- म. जीओसी ने केवल भारत से वर्ष 2014-15 में निर्यात करना शुरू किया है और इसीलिए जीओसी के संबंध में कोई क्षति नहीं हो सकती।
- य. जांच की अवधि में भारत को चीन का निर्यात भारतीय मांग का काफी कम 1.48 % है, जिसे पाटन नहीं कहा जा सकता।
- कक. भारतीय आयात के आंकड़ों के अनुसार, चीन के उत्पाद की औसत आयात की कीमत मई, 2014 से जनवरी, 2016 तक के दौरान 1540 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। मई, 2014 में 1800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से जनवरी, 2016 में 1200 अमेरिकी डॉलर की कम दर रही। भारतीय निर्माता की उस अवधि में औसत निर्यात कीमत 1380 अमेरिकी डॉलर है जो आयातित कीमत से 10% कम है। यह मई, 2014 में 1580 अमेरिकी डॉलर की उच्च दर से जनवरी, 2016 में 900 अमेरिकी डॉलर की कम दर रही। भारतीय लैब उत्पादक अपना उत्पाद देश में आयात किए जा रहे एलएबी की कीमत से कम दर पर निर्यात कर रहे हैं।
- खख. आउटपुट में गिरावट, यदि कोई है, तो वह मार्च और अप्रैल, 2015 में दो मिडल ईस्ट आधारित एन-पैराफिन उत्पादकों द्वारा रख-रखाव करने, संयंत्र पर तकनीकी मामलों अथवा फीड स्टॉक सामान्य पैराफिन (एन-पैराफिन) की कमी, तथा 2012-2015 के दौरान उत्पादन में वृद्धि जारी रहने के कारण थी, जैसा कि रिलायंस के आंकड़ों में दिखाया गया है।
- गग. आईओसीएल अब अपनी क्षमता के 120% पर उत्पादन कर रहा है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- घघ. घरेलू उद्योग का बाजार अंश 82% है जबकि महानिदेशक, संरक्षा को किए गए अनुरोध में बाजार अंश वर्ष 2008-09 78.84% था। इसका तात्पर्य यह है कि आयात बाजार के अंश में वर्ष 2008-09 में 21.16% से गिरावट आई है जबकि मांग में विगत 5 वर्षों में 66% तक गिरावट आई है।
- डड. जहां तक याचिकाकर्ताओं का लाभों में गिरावट से संबंधित दावे का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने यह मत दिया है :

- i. लाभों में गिरावट, यदि कोई हो, वह अस्थिरता, याचिकाकर्ताओं के कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति न होने, रख-रखाव बंद होने, सामान्य पैराफिन कमी के कारण कम उत्पादकता होने तथा दो प्रमुख घरेलू निर्माताओं की कीमत होने के कारण थी।
  - ii. प्रमुख कच्ची सामग्री का अपस्ट्रीम एकीकरण न होने के कारण याचिकाकर्ताओं की कम लाभप्रदता का होना हो सकता है।
  - iii. बिक्री कीमत में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और उसके बाद कच्चे माल में गिरावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिरावट आई है।
  - iv. बड़े निर्माता अपने अधिकांश उत्पाद फार्मूला आधारित कीमत पर बेच रहे हैं ताकि इसे आयात कीमत का सहारा मिले।
- चच. एक याचिकाकर्ता का अधिकांश उत्पादन कैप्टिव खपत के लिए है। इसके अलावा, उनका निर्यात 75% तक गिर रहा है।
- छछ. एक अन्य याचिकाकर्ता जब भी निर्यात करता है, आयातित की जा रही कीमत से कम कीमत पर निर्यात करता है।
- जज. भारत में एलएबी आयात चीन से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आ रहे हैं, जैसे विश्व के किसी अन्य देश में आते हैं।
- झझ. चीन ने जांच की अवधि में केवल 20304 मी. टन बिक्री की है, जो कुल भारतीय मांग का 3.5% है।
- ञञ. जीओसी ने अप्रैल, 2014 से जून, 2015 तक चेन्नई बंदरगाह में केवल 600 मी. टन बिक्री की है, जो घरेलू निर्माता टीपीएल की दक्षिण में उत्पादन क्षमता का 0.5% है।
- टट. सभी निर्यातकों से चेन्नई में आयात एक वर्ष में 5000 मी. टन से कम है, जो टीपीएल की मासिक उत्पादन क्षमता का 4% है। इसका यह तात्पर्य है कि घरेलू उत्पादकों के लिए 96% बाजार उपलब्ध है।
- ठठ. जीओसी ने जांच की अवधि में और यहां तक कि अभी तक 2 माह को छोड़कर भारत के पश्चिमी घाट में किसी भी मात्रा में बिक्री नहीं की है।
- डड. एलएबी का निर्यात भी चेन्नई बंदरगाह से शुरू हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण में घरेलू कमी है, क्योंकि वहां केवल एक ही उत्पादक है।
- ढढ. पूर्वी घाट पर कोई निर्माता नहीं है। संभरण लागत पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट के लिए अधिक है। वर्ष 2015 में एक देश में अधिकांश आपूर्ति पूर्वी घाट अर्थात् कोलकाता को है, जो जांच की अवधि के लिए बहुत ही कम अर्थात् 3600 मी. टन है।
- णण. जीओसी के भारत को किए गए सभी निर्यात चीन की घरेलू कीमतों की तुलना में समान अथवा उच्च कीमत पर किए गए हैं।
- तत. 7.5% का सीमा शुल्क घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त उत्पादन है।
- थथ. किसी भी पर्याप्त वृद्धि वाले आयात से गहन सामग्री क्षति नहीं हो रही।
- दद. निर्यात के लिए अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए आयात को बाहर किया जाए। यदि ऐसा किया जाए तो आयात का अंश काफी कम होता है। इसके अलावा, भारतीय एचयूएल की ओर से उनके बांग्लादेश और नेपाल के कारखानों के लिए काफी आयात किए गए हैं, इसलिए वे भी निर्यात के लिए हैं।
- धध. पाटनरोधी शुल्क संरक्षण चाहने वाली कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत और बड़ी समूह कंपनियां हैं।
- नन. घरेलू बिक्रियां निर्यातों से की जा रही है। चेन्नई ने भी निर्यात शुरू कर दिया है।
- पप. कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है। बंद किए गए संयंत्र आयातों के लिए नहीं है। क्षति, यदि कोई है, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और कीमत में अस्थिरता के कारण है।
- फफ. भारत में संस्थापित क्षमता से अधिक मांग के कारण भारी कमी है।
- बब. एलएबी का बाजार वर्ष 2012-18 के दौरान 4.3% की एक मिश्रित वार्षिक विकास दर पर वैश्विक रूप से बढ़ेगा और भारत में खपत 2016-17 तक 5,95,000 मी. टन तक पहुँचने की संभावना है जो कि घरेलू उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। अतः घरेलू उत्पादक के विकास के लिए काफी स्थान है।
- भभ. घरेलू उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अवसर है, यदि वे निर्यातों पर ध्यान केंद्रित करें और वे अपना खोया आधार पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- मम. कोई भी पाटनरोधी शुल्क लगाने से एलएबी के प्रयोक्ताओं के लिए समस्याएं आएंगी।
- यय. आयात के कारण एलएबी के निर्यातकों को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि विश्वव्यापी समग्र अर्थव्यवस्था पर दबाव है।

- ककक. विगत 5 वर्षों के दौरान मांग में तकरीबन 66% तक की वृद्धि हुई है लेकिन संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत क्षमता में 60,000 मी. टन तक की कमी आई है। साथ ही, घरेलू निर्माण द्वारा बिक्रियों में वृद्धि विगत 5 वर्षों में उनके आंकड़ों के अनुसार 50% नीचे गया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि उनका निर्यात वर्ष 2006-07 में 60% तक कम हुआ है।
- खखख. वर्ष 2013-14 के दौरान आयातों में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की बिक्री में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसका तात्पर्य यह है कि आयात उनकी हानि का कारण नहीं है।
- गगग. घरेलू उद्योग के पास शेष वस्तु सूचियां घरेलू उद्योग के निर्यातों में पर्याप्त गिरावट के कारण है।
- घघघ. याचिकाकर्ता के आंकड़े 93% क्षमता उपयोग को दर्शाते हैं और रिलयांस के आंकड़े भी उत्पादन में निरंतर वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में वृद्धि को दर्शाते हैं।
- ङङङ. निवेश पर कम प्रतिफल लाभ में वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।
- चचच. पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित में नहीं है क्योंकि मांग आपूर्ति अंतर आयातों से ही पूरा होता है। विचाराधीन उत्पाद भी डिटर्जेंट और पेस्टिसाइड जैसे प्रमुख उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाते हैं जो समाज के निचले वर्ग की पूर्ति करते हैं।

### **घरेलू उद्योग के विचार**

44. क्षति के निर्धारण के संबंध में याचिकादाताओं द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जबकि जांच अवधि में भी उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (ख) संबद्ध देशों से आयात कुल आयातों का लगभग 62% हिस्सा बनते हैं।
- (ग) समस्त अवधि में पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (घ) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके फलस्वरूप बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हुई है।
- (ङ) समस्त क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन की लागत के स्तर से नीचे बनी रही है।
- (च) वर्ष 2013-14 तक बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में इनमें गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत के स्तर से काफी नीचे है। इस प्रकार आयातों ने जांच अवधि के दौरान बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को अत्यधिक मन्द करने का प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त जबकि विगत वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, यह बिक्रियों की लागत के स्तर से नीचे बनी हुई है जिसके फलस्वरूप घाटे हुए हैं।
- (छ) घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत है। निम्न आयात कीमतों के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में पाटन के अत्यधिक न्यूनीकरण के प्रभाव का सामना कर रहा है।
- (ज) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में विकट गिरावट आई है। विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन में मामूली सुधार आया था, लेकिन यह पहले प्राप्त हुए स्तर और अत्यधिक वित्तीय घाटों की लागत से नीचे था।
- (झ) वर्ष 2013-14 तक घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट आई थी और उसके बाद जांच अवधि में बिक्रियों में वृद्धि हुई है। लेकिन वर्ष 2011-12 और 2012-13 की तुलना में यह अभी भी निम्न स्तर पर बनी हुई है।
- (ञ) विचाराधीन उत्पाद की मांग के भारत में उपलब्ध क्षमता से अधिक होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है। क्षमता उपयोग जो कि आधार वर्ष में 81% था, जांच अवधि में गिर कर 64% हो गया है।
- (ट) क्षति अवधि में पाटित आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है, लेकिन जांच अवधि के बाद उसमें गिरावट आई है।
- (ठ) समस्त क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई है।
- (ड) क्षति अवधि में नकदी लाभ में भी गिरावट आई है। क्षति अवधि में व्याज पूर्व लाभ में भी गिरावट आई है और वर्ष 2012-13 से यह नकारात्मक बना हुआ है। इसके फलस्वरूप निवेश पर प्रतिलाभ भी वर्ष 2012-13 से नकारात्मक बना हुआ है।

- (ढ) घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर से क्षति अवधि में वृद्धि होने का पता चलता है। वेतन में सामान्य वृद्धि होने का पता चलता है, जो कि विशेष रूप से श्रम की लागत में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन में गिरावट के समनुरूप उत्पादकता में प्रति दिन और प्रति कर्मचारी, गिरावट आई है।
- (ण) वर्ष 2013-14 तक मालसूचियों के स्तर में वृद्धि हुई है और प्रस्तावित जांच अवधि में इनमें गिरावट आई है, लेकिन यह अत्यधिक बनी हुई है।
- (त) घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा कारणात्मक संबंध होने के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) बिक्रियों और बाजार के हिस्से की प्रवृत्ति के बारे में प्रतिवादी पक्षकारों का आरोप वास्तव में गलत है। घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जबकि क्षति अवधि में अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार का हिस्सा स्थिर बना हुआ है।
  - (2) चीन से वस्तुओं की दर में वृद्धि होने के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि उसमें सकारात्मक कीमत कटौती हुई है, अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य का पहुंच मूल्य, अभी भी घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत से नीचे बना हुआ है।
  - (3) टीएनपीएल की वार्षिक रिपोर्ट में क्षति के अन्य कारकों को स्वीकार करने के संबंध में यह नोट किया जाए कि वार्षिक रिपोर्ट में विवरण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आने से संबंधित नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, पाटन-रोधी मामले में क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद के निष्पादन में गिरावट आने से संबंधित संपूर्ण चित्र को प्रदर्शित नहीं करते हैं।
  - (4) आरापों के विपरीत दोनों याचिकादाताओं को घाटे हो रहे थे।
  - (5) अन्य देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को मात्रा की क्षति होने के साथ-साथ कीमत में भी क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही मात्रा और कीमत की क्षति का कारण केवल संबद्ध देशों से पाटित आयातों का होना है।
  - (6) कीमत में आरोपित अनुचित कमी की मनाही की जाती है क्योंकि यह वास्तव में गलत है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों की कीमत से अधिक कीमतों पर बिक्री की है, जैसा कि सकारात्मक कीमत में कटौती होने से प्रदर्शित होता है।
  - (7) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आने के तर्क के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आने के अनेक प्राचल हैं और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कारक में गिरावट आ रही है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण घाटे हुए हैं और इसलिए वह पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत राहत की मांग कर रहा है।
  - (8) वर्ष 2012-13 से 2013-14 में कीमत में वृद्धि होने की प्रवृत्ति के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग आयात के पहुंच मूल्य में वृद्धि के समानुपात अपनी कीमत में वृद्धि नहीं कर सका था। जबकि वर्ष 2011-12 की तुलना में पहुंच मूल्य में 121 बिन्दुओं तक की वृद्धि हुई है, उसी अवधि में बिक्री कीमत में केवल 113 बिन्दुओं तक ही वृद्धि हुई है।
  - (9) केवल उत्तरी और पश्चिमी भारत को विचाराधीन उत्पाद को बेचने के निर्यातक के तर्क के संबंध में यह निवेदन है कि क्षति को समग्र घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना चाहिए और न कि पृथक रूप से उसके भागों के लिए।
  - (10) निरमा द्वारा एलएबी की केप्टिव खपत के संबंध में यह निवेदन है कि उसके उत्पादन का पर्याप्त भाग व्यापारी बाजार के निमित्त होता है। इसके अतिरिक्त पाटित संबद्ध आयातों के कारण एलएबी की अर्थक्षम कीमत होने के कारण निरमा को अपना ध्यान नॉन-डिटरजेंट की ओर संकेन्द्रित करने के लिए बाध्य किया जाता है और न कि गैर-एलएबी आधारित उद्योगों पर।
  - (11) याचिकादाताओं की लागत और एकीकरण के संबंध में टीएनपीएल तुलनीय प्रोद्योगिकी का प्रयोग करता है और पाटन-रोधी कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादक संरक्षण प्राप्त करने के लिए संघटित होने चाहिए।
  - (12) मिट्टी के तोल और फीडस्टॉक की गुणवत्ता के मुद्दे के संबंध में यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को भारत में प्रचलित लागत और कीमत के अनुसार देखा जाए और न कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर। फीडस्टॉक का



प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है और न कि लाभ पर। वास्तव में यदि घरेलू उद्योग कम मात्रा में उत्पाद निर्मित करता है, तो उस पर उत्पाद को बेचने का कम दबाव पड़ता है और यदि घरेलू उद्योग की कम मात्रा होती है, तो उस पर बिक्री के लिए कम दबाव पड़ता है। इसलिए आरोपित कारक के फलस्वरूप लाभ में उस सीमा तक तेजी से गिरावट नहीं आती, जिसमें घरेलू उद्योग को लाभ की स्थिति से अत्यधिक वित्तीय घाटे हुए हों।

- (13) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद के पाटित आयातों के कारण एलएबी की कीमत में तेजी से गिरावट आने के कारण घाटे होने शुरू हुए थे और उसे अपरिष्कृत तेल की कीमतों अथवा नकदी प्रवाह के मुद्दों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- (14) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है, यह निवेदन है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, फिर भी अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार का हिस्सा स्थिर बना हुआ है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- (15) आरआईएल और आईओसीएल के पश्चगामी एकीकरण और फीडस्टॉक आपूर्ति पर उसके प्रभाव के संबंध में यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग को कच्चा माल अधिप्राप्त करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की क्षति का एक मात्र कारण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों का होना है।
- (16) आयात की मात्रा की प्रवृत्ति और घरेलू उद्योग की बिक्रियों की प्रवृत्ति से उसकी तुलना करना वास्तव में गलत है। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों गिरावट आई है, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- (17) विद्युत के मुद्दों से संबंधित टीएनपीएल की वार्षिक रिपोर्टों और घरेलू उद्योग के सामने पेश आ रहे अन्य मुद्दों पर आधारित तर्क के संबंध में पुनः निवेदन है कि वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण, इस निष्कर्ष को नहीं बदलते हैं कि उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट के बारे में नहीं हैं। प्राधिकारी का संबंध क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से है। तथापि, वार्षिक रिपोर्टें विचाराधीन अवधि पर ही ध्यान संकेन्द्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी घरेलू प्रचालनों के बारे में चिंतित हैं, जबकि वार्षिक रिपोर्टें कंपनी के समग्र प्रचालनों के बारे में होती हैं। इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, पाटन-रोधी मामले में संबंधित उत्पाद की क्षति अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन में गिरावट के बारे में पूर्ण छवि प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को भारत में प्रचलित लागत और कीमत के अनुसार देखा जाए और न कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर।
- (18) निरमा लिमिटेड के आंतरिक अंतरण के संबंध में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां अधिक प्रासंगिक है और न कि उसका केप्टिव अंतरण। घरेलू बाजार/बिक्री के लिए क्षति का निर्धारण करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री भाग में आर्थिक क्षति हुई है।
- (19) जीओसी के कारण क्षति होने के संबंध में यह देखा जाए कि क्या जांच अवधि के दौरान आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हुए हैं, क्या ये आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और क्या उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि समग्र जांच अवधि में प्रत्येक संबद्ध देश से आयात होने चाहिए।
- (20) वास्तव में यह गलत है कि भारत में चीन के निर्यात, कुल भारतीय मांग का केवल 1.48% हैं। इसका सही आंकड़ा 3% से अधिक का है। इसके अतिरिक्त यह तर्क असंगत है क्योंकि चीन से आयात, 3% की न्यूनतम सीमा की तुलना में कुल आयातों का 10% है।
- (21) एलएबी के भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्यात के संबंध में दिया गया तर्क वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने नगण्य मात्रा में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं और किसी भी स्थिति में यदि ऐसे निर्यातों से कोई क्षति हुई है, तो उसे पहले से ही पृथक् कर दिया गया है।
- (22) उत्पादन में गिरावट आने के कारणों को दर्शाने वाले तर्क निराधार हैं। एलएबी के सस्ते आयात के कारण उत्पादन में गिरावट आई है और न कि फीडस्टॉक की कमी के कारण। घरेलू उद्योग ने अपनी कुल आवश्यकता की केवल 14% आयातित एन-पेरिफिन की खपत की है। इसके अतिरिक्त याचिकादाताओं ने क्षति की मात्रा का कोई दावा नहीं किया है। याचिकादाताओं ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव का दावा किया है।

- (23) आईओसीएल के जांच अवधि पश्चात के कार्य-निष्पादन के संबंध में अन्य घरेलू उत्पादक के जांच अवधि पश्चात का कार्य-निष्पादन, वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के क्षति के प्रभाव से संरक्षण की मांग कर रहा है।
- (24) वास्तव में यह गलत है कि घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा 82% है और संबद्ध देश से आयातों का बाजार का हिस्सा कम हुआ है। इसके विपरीत क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है और क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जो कि 35% से घट कर 26% रह गया है।
- (25) पाटित आयातों के कारण कम बिक्री कीमत होने के कारण लाभ कम हुआ है। घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किया जाना चाहिए। उत्पादक और उसके सभी प्रचालनों के संबंध में क्षति का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है कि यदि कंपनी पश्चगामी एकीकृत थी अथवा अग्रगामी एकीकृत थी, तो प्राधिकारी केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में क्षति का निर्धारण करेंगे।
- (26) बिक्री कीमत में अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिरावट आने के संबंध में यह निवेदन है कि यदि घरेलू और निर्यात बाजार में बिक्री कीमत में कुछ सीमा तक गिरावट आई है, तो कोई पाटन नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि उत्पाद का निर्यात पाटित कीमत पर किया गया है, तो उससे स्पष्ट होता है कि उत्पाद को घरेलू बाजार में निर्यात कीमत से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था।
- (27) केप्टिव खपत के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उत्पादन का अत्यधिक भाग व्यापारी बाजार के निमित्त था।
- (28) कम कीमत पर निर्यात के संबंध में याचिकादाताओं का निवेदन है कि यह भारतीय बाजार में पाटन के फलस्वरूप हुआ है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता, संबद्ध देशों द्वारा अन्य ऐसे बाजारों में कम कीमत के निर्यातों का सामना कर रहे हैं, जहां याचिकादाता निर्यात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि याचिकादाता निर्यात में कम कीमत प्राप्त करेंगे।
- (29) चीन से आयात कीमत, पाटित कीमते हैं। यह तर्क संगत नहीं है कि ये आयात अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर हो रहे हैं। अधिक तर्क संगत यह तथ्य है कि आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं।
- (30) भारत में भौगोलिक स्थानों और क्षति के उसके प्रभाव से संबंधित जीओसी के विभिन्न तर्कों के संबंध में यह निवेदन है कि क्षति को समग्र घरेलू उद्योग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और न कि उसके संभागों के लिए पृथक् रूप से। इसके अतिरिक्त एलएबी के निर्यात के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान केवल कम मात्रा में एलएबी के निर्यात किए हैं।
- (31) जीओसी से आयात, चीन की घरेलू कीमत की तुलना में चाहे समान कीमत पर अथवा अधिक कीमत पर किए गए हैं, तर्क संगत नहीं है क्योंकि चीन एक एनएमई देश है और उसकी घरेलू कीमत, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए संगत नहीं है। चीन जनवादी गणराज्य के लिए घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित सामान्य मूल्य पर आधारित पाटन मार्जिन अत्यधिक है।
- (32) 7.5% के सीमा-शुल्क के संबंध में निवेदन संगत नहीं है।
- (33) जांच अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर अत्यधिक आयात हुए थे जिसके कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (34) इस तर्क के संबंध में कि उत्पादों का निर्यात करने के प्रयोजनार्थ आयात किए गए हैं, यह निवेदन है कि ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की जांच करने के लिए अग्रिम लाईसेंस के तहत आयातों को शामिल किया है। प्राधिकारी ने अन्य मामलों में भी इस तथ्य को माना है कि अग्रिम लाईसेंस के तहत किए गए आयातों का यह अभिप्राय नहीं है कि उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है।
- (35) याचिकादाता कंपनियों की वित्तीय क्षमता से संबंधित तर्क के बारे में यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2012-13 से वित्तीय घाटे हो रहे हैं और जांच अवधि में उनमें सघन वृद्धि हुई है। ऐसी गिरावट अत्यधिक हुई और यह आर्थिक है।

- (36) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में निवेदन है कि जांच के दौरान ये निर्यात बहुत नगण्य थे।
- (37) मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर होने के तर्क के संबंध में निवेदन है कि संबद्ध देशों से निर्यातक इस तर्क पर कि मांग और पूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है, पाटित कीमतों पर निर्यात नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है। इसके अतिरिक्त जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादकों की स्थापित क्षमता संबद्ध वस्तुओं की मांग से अधिक है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता अनप्रयुक्त पड़ी हुई है।
- (38) विश्वभर में एलएबी के बाजार का विस्तार होने के संबंध में निवेदन है कि संबद्ध देशों से एलएबी के पाटित आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होने पर ही घरेलू उद्योग संवृद्धि करने का प्रबंध करेगा।
- (39) घरेलू उद्योग को यह सलाह देना अनुचित है कि वह अपना ध्यान निर्यातों पर संकेन्द्रित करे क्योंकि घरेलू उद्योग कोई रिआयत नहीं मांग रहा है, बल्कि वह तो व्यवसाय करने का समान क्षेत्र प्रदान करने की प्रार्थना कर रहा है।
- (40) पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के कारण एलएबी के प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के और अधिक प्रतिस्पर्द्धी स्रोत प्राप्त होंगे।
- (41) उच्च क्षमता उपयोग के आरोप के संबंध में याचिकादाताओं ने वर्तमान मामले में क्षति की मात्रा का दावा नहीं किया है। याचिकादाताओं ने घरेलू उद्योग के कीमत प्राचल पर पाटन के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का ही दावा किया है।
- (42) लाभ संवृद्धि को प्रभावित करने वाले निवेश पर कम हुए प्रतिलाभ की अवधारणा ने यह सिद्ध कर दिया है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

45. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है।

46. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को मात्रा और कीमत दोनों के प्रभाव की जांच करके क्षति की जांच करने की आवश्यकता है। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

47. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

*"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

48. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी प्राचलों में गिरावट आए। जबकि कुछ प्राचल गिरावट दर्शा सकते हैं, कुछ प्राचल सुधार भी दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति के सभी प्राचलों पर विचार करना चाहिए और उसके बाद निष्कर्ष देना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है?

49. पहुंच मूल्य में मेसर्ज मुनताजत द्वारा पेश की गई छूट को उचित रूप से समंजित किया गया है, जैसे कि उनकी निर्यात आय में क्रेडिट को समंजित किया गया है।

50. प्राधिकारी ने तथ्यों और विभिन्न निवेदनों को ध्यान में रखते हुए क्षति के प्राचलों की जांच की है। निम्नोक्त जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया गया है।

51. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचक, नामतः उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार विचार किया गया है।

**संचयी मूल्यांकन**

52. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- II में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटन-रोधी जांच की जा रही है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे, जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; और
- (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

53. वर्तमान मामले में -

- (क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, ऊपर निर्धारित सीमाओं से बहुत अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित सीमाओं से बहुत अधिक है।
- (ग) आयातों का संचयी निर्धारण करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जाने वाली और भारतीय बाजार में बेची जाने वाली समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्तमान मामले में संचयी निर्धारण के विरोध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

54. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझते हैं।

**मांग का मूल्यांकन**

55. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/मांग का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों की मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों के साथ जोड़ दिया गया है और उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

**केप्टिव खपत सहित मांग**

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	2,72,963	2,76,097	2,68,849	2,77,987	3,47,483
अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***	***
संबद्ध आयात	मी.टन	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
अन्य आयात	मी.टन	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
मांग/खपत	मी.टन	***	***	***	***	***
मांग/खपत	सूचीबद्ध	100	109	105	117	147

**केप्टिव खपत रहित मांग**

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	2,24,390	2,27,036	2,27,605	2,44,078	3,05,097
अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***	***
संबद्ध आयात	मी.टन	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
अन्य आयात	मी.टन	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
मांग/खपत	मी.टन	***	***	***	***	***
मांग/खपत	सूचीबद्ध	100	109	108	123	153

56. यह देखा गया है कि मांग, वृद्धि होने की प्रवृत्ति दर्शाती है, चाहे उसमें केप्टिव खपत को शामिल किया गया है अथवा नहीं। हितद्व पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण केप्टिव खपत में गिरावट आना है। तथापि, चूंकि केप्टिव खपत के बिना भी मांग में वृद्धि हुई है, इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण केप्टिव खपत में गिरावट आना नहीं माना जा सकता है।

#### झ. पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव

##### आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के प्रसंग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्षति का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:-

आयात	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
चीन	मी.टन	514	-	-	16,227	20,283
ईरान	मी.टन	37,587	30,941	20,841	28,610	35,762
कातार	मी.टन	46,117	39,777	47,362	58,023	72,529
संबद्ध देश	मी.टन	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
अन्य	मी.टन	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
कुल	मी.टन	1,05,507	1,26,081	1,17,807	1,66,095	2,07,619

58. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2013-14 में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। तथापि, जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

59. वर्ष 2013-14 तक भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और घरेलू बाजार में उनकी खपत के प्रसंग में जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
केप्टिव खपत सहित खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा	%	17.60	13.61	13.53	18.32
केप्टिव खपत रहित खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा	%	19.59	15.03	14.74	19.50
उत्पादन के प्रसंग में आयात	%	23.94	21.04	22.55	34.74

#### ञ. आयातों के कीमत पर प्रभाव

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत के साथ तुलना करने से पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसा

आयातों से अन्यथा कीमत में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि होनी रुकती जो कि अन्यथा काफी अधिक होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती, कीमत में ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है।

### कीमत कटौती

61. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली से की है। प्राधिकारी ने कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने के बारे में घरेलू उद्योग के तर्क को नोट किया है और इस प्रकार जांच अवधि के लिए त्रैमासिक कीमत कटौती का निर्धारण किया है, जो कि निम्नानुसार है:-

कीमत में कटौती	चीन					
विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
आयात	मी.टन	514	-	-	16,227	20,283
आयात मूल्य	लाख रूपए	486	-	-	15,638	19,547
सीआईएफ कीमत	रूपए./मी.टन	94,632	-	-	96,370	96,370
निर्धारणीय मूल्य	रूपए./मी.टन	95,578	-	-	97,334	97,333
सीमा-शुल्क की राशि	रूपए./मी.टन	7,168	-	-	7,300	7,300
उपकर	रूपए./मी.टन	215	-	-	219	219
पहुंच मूल्य	रूपए./मी.टन	1,02,961	-	-	1,04,853	1,04,852
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	-	-	***	***
कीमत में कटौती	रूपए./मी.टन	***	-	-	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	0-10	-	-	0-10	0-10

कीमत में कटौती	ईरान					
विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
आयात	लाख रूपए	37,587	30,941	20,841	28,610	35,762
आयात मूल्य	रूपए./मी.टन	32,626	30,897	22,461	26,838	33,547
सीआईएफ कीमत	रूपए./मी.टन	86,801	99,859	1,07,772	93,806	93,806
निर्धारणीय मूल्य	रूपए./मी.टन	87,669	1,00,857	1,08,849	94,744	94,744
सीमा-शुल्क की राशि	रूपए./मी.टन	6,575	7,564	8,164	7,106	7,106
उपकर	रूपए./मी.टन	197	227	245	213	213
पहुंच मूल्य	रूपए./मी.टन	94,442	1,08,648	1,17,258	1,02,063	1,02,063
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	0 से (-10)	0 से (-10)	0 से (-10)	0-10	0-10

कीमत में कटौती	कातार					
विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
आयात	लाख रूपए	46,117	39,777	47,362	58,023	72,529
आयात मूल्य	रूपए./मी.टन	42,096	40,756	52,385	56,213	70,266
सीआईएफ कीमत	रूपए./मी.टन	91,281	1,02,462	1,10,606	96,880	96,880
निर्धारणीय मूल्य	रूपए./मी.टन	92,194	1,03,486	1,11,712	97,849	97,849
सीमा-शुल्क की राशि	रूपए./मी.टन	6,915	7,761	8,378	7,339	7,339
उपकर	रूपए./मी.टन	207	233	251	220	220
पहुंच मूल्य	रूपए./मी.टन	99,316	1,11,481	1,20,341	1,05,407	1,05,407
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	0 से (-10)	0-10	0-10	0-10	0-10

62. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक संबद्ध देश की पहुंच कीमत, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नीचे थी, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत में कटौती हो रही है।

#### कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों में अत्यधिक सीमा तक ह्रास हो रहा है अथवा इससे कीमत में वृद्धि होने में रूकावट आ रही है, जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो जाती, प्राधिकारी ने क्षति अविध को दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है। इसकी स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	124	114
बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	115	98
पहुंच कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	123	107

आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई है, जबकि बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2013-14 तक बिक्रियों और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें गिरावट आई है। तथापि, समस्त अवधि में बिक्री कीमत में हुई गिरावट, बिक्रियों की लागत में गिरावट से अधिक है। वास्तव में जबकि बिक्री कीमत में विगत वर्ष की तुलना में \*\*\* रूपए प्रति मी.टन की गिरावट आई है, विगत वर्ष की तुलना में लागत में \*\*\* रूपए प्रति मी.टन की गिरावट आई है। इस प्रकार आयातों के घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव पड़े हैं।

**कम कीमत पर बिक्री**

65. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री करने से हुई क्षति की भी जांच की है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:-

कम कीमत पर बिक्री (जांच अवधि)		
[[		
क्षति-रहित कीमत	अमरीकी डालर/मी.टन	***
बिक्री कीमत	अमरीकी डालर/मी.टन	***

बिक्री कीमत जांच अवधि के लिए निर्धारित क्षति-रहित कीमत से कम है। कम कीमत पर बिक्री 5 - 15% है।

66. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से कम थी। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री करने से अत्यधिक क्षति हुई है।

**ट. घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल**

67. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 उल्लिखित प्रावधान यह है कि क्षति का निर्धारण करने के लिए समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की सार्थक जांच करना आवश्यक है। नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों के बारे में नीचे उल्लेख किया गया है।

**(1). उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां**

68. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:-

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
क्षमता	मी.टन	4,12,400	4,12,400	4,12,400	4,12,400	5,15,500
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी.टन	3,51,722	3,36,098	3,02,443	2,96,064	3,70,080
क्षमता उपयोग	%	85%	81%	73%	72%	72%
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	2,24,390	2,27,036	2,27,605	2,44,078	3,05,097
केप्टिव खपत	मी.टन	***	***	***	***	***
निर्यात बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां	मी.टन	3,45,092	3,23,109	3,09,374	3,07,264	3,84,080

69. यह नोट किया जाता है कि -

- (क) घरेलू उद्योग की क्षमता उन्हीं स्तरों पर बनी हुई है।
- (ख) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है।



(ग) आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है।

(घ) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

## (2). मांग में बाजार का हिस्सा

70. घरेलू बिक्रियों पर पाटित आयातों के प्रभाव और घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

*केप्टिव खपत सहित मांग में हिस्सा*

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	57%	53%	53%	50%
अन्य उत्पादक	%	21%	23%	23%	21%
संबद्ध आयात	%	18%	14%	14%	18%
अन्य आयात	%	4%	11%	10%	11%
मांग/खपत	%	100%	100%	100%	100%

*केप्टिव खपत रहित मांग में हिस्सा*

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	52%	48%	49%	46%
अन्य उत्पादक	%	23%	25%	25%	22%
संबद्ध आयात	%	20%	15%	15%	19%
अन्य आयात	%	5%	12%	11%	12%
मांग/खपत	%	100%	100%	100%	100%

71. घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा, वर्ष 2011-12 में 52% था, जो कि जांच अवधि में घट कर 46% रह गया। संबद्ध देशों का बाजार का हिस्से में वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच अवधि में उसमें वृद्धि हो गई, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई और बाद में जांच अवधि में उसमें वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि में उसमें गिरावट आ गई। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में अन्य उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

## (3). लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ

72. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
विक्रियों की लागत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	116	124	114	114
विक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	108	115	98	98
लाभ/हानि	रूपए./मी.टन	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	11	13	(101)	(101)
कुल लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	11	13	(110)	(137)
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	79	52	63	78
पीबीआईटील-घरेलू	लाख रूपए	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	28	26	(88)	(110)
आरओआई	%	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	सीमा	35 - 45	5-15	5 -15	(30) से (40)	(30) से (40)

- (क) जबकि वर्ष 2013-14 तक उत्पादन की लागत और विक्री कीमत में वृद्धि हुई थी, जांच अवधि में दोनों में गिरावट आई है। चूंकि आयात घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे भी हुए हैं।
- (ख) इस अवधि के दौरान नकदी लाभ में भी अत्यधिक गिरावट आई है और यह आधार वर्ष की तुलना में नकारात्मक बन गया है।
- (ग) इस अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ में भी अत्यधिक गिरावट आई है और जांच अवधि में यह नकारात्मक बन गया है। इसके फलस्वरूप क्षति अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ में अत्यधिक गिरावट आई है और जांच अवधि में यह नकारात्मक बन गया है।
- (घ) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण वित्तीय घाटे हुए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग और पूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है और ऐसी स्थिति में आयात करना अपरिहार्य है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग 5,61,442 मी.टन थी। इसकी तुलना में भारतीय उद्योग द्वारा सृजित क्षमता 5,15,600 मी.टन थी। इस प्रकार देश में उत्पाद के लिए मांग और पूर्ति में स्वीकार्य अंतर व्याप्त था। ऐसी स्थिति में जिसमें देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग, घरेलू उद्योग की संयुक्त क्षमताओं से अधिक होती है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ सीमा तक अत्यधिक गिरावट आने से घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे होना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ का समाधान घरेलू उत्पादकों के बीच संभवतः बढ़ रही पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से नहीं हो सकता है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग ने 22% की वृद्धि

दर्शायी है। वस्तुतः इसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्द्धा में कुछ गिरावट आनी चाहिए लेकिन पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

#### (4). माल सूचियां

73. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
प्रारंभिक स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
अंत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
औसत स्टॉक	मी.टन	12,195	21,999	24,704	13,902

यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और जांच अवधि के अंत में उनमें गिरावट आई है।

#### (5). रोजगार, उत्पादकता और वेतन

74. रोजगार, उत्पादकता और वेतन से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
रोजगार	संख्या	853	984	791	797
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	104	94	116
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन/प्रति दिन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	96	86	84
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	83	93	90

यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। अदा किए गए वेतन में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी गिरावट आई है।

#### (6). संवृद्धि

संवृद्धि (अलग-अलग वर्ष)		2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन	%	-	-4.44%	-10.01%	-2.11%
घरेलू विक्रियां	%	-	1.18%	0.25%	7.24%
मालसूची	%	-	80.40%	12.30%	-43.73%
बाजार का हिस्सा	%	-	-3.91%	0.20%	-3.83%
लाभप्रदता	%	-	-88.97%	20.34%	-861.14%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-19.46%	-0.73%	-33.57%

यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि और क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से और उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर दृष्टिगत हुई है।

75. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की समग्र संवृद्धि नकारात्मक थी।

**(7). पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन**

76. यह देखा गया है कि भारत में संबद्ध देश से आयात, पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन अत्यधिक है।

**(8). घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

77. संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात की कीमतों को ध्यान में रखते हुए लागत के ढांचे, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों से भिन्न कारक, जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में कटौती हो रही है। सऊदी अरब से आयात कीमत, संबद्ध देशों से आयात कीमतों से बहुत अधिक बनी रही है। लेकिन सऊदी अरब से मास-वार आयात कीमत के विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतें, सऊदी अरब से आयात कीमतों से कम थीं। भारतीय उत्पादकों के लिए मानक (बैंचमार्क) आयात कीमतें हैं। उत्पाद का कोई अर्थक्षम स्थानापन्न नहीं है। उत्पाद की मांग अत्यधिक वृद्धि दर्शा रही थी और यह घरेलू उद्योग के सामने पेश आ रही कीमत ह्रास के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकती थी। घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार एक मात्र कारक, भारत में उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत है। जब लागत बढ़ रही थी, तो आयातों के कारण अत्यधिक कीमत ह्रास हुआ है और जब लागत घट रही थी, तो आयातों के कारण कीमत ह्रास हो रहा था।

**(9). पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता**

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन में वृद्धि करने की कोई नहीं बनाई है। किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने भी क्षमता में किसी प्रकार का संवर्धन करने की कोई योजना नहीं बनाई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसके उत्पाद का निरंतर प्रतिकूल निष्पादन हुआ है, जिसने उसे क्षमताओं को बढ़ाने से प्रतिबंधित किया है।

**आर्थिक क्षति पर निष्कर्ष**

79. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है, जब कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अत्यधिक आयात होने के कारण संबद्ध वस्तुओं की मांग में संबद्ध देशों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के अत्यधिक आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटे हो रहे हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग का आर्थिक क्षति हुई है।

**क्षति मार्जिन**

घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ करने पर जांच अवधि के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन का पता चलता है, जो कि निम्नानुसार है:-

(क)

कतर		
उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन %
मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंताजात	0-10
मै. सीफ लिमिटेड	मै. रेनिश पैट्रोकेम एफजैडई ट्रेडर द्वारा तथा मै. मुंताजात	20-30

मै. सीफ लिमिटेड	उपरोक्त i तथा ii की भारित औसत	5-10
कोई	कोई	20-30

(ख)

चीन जनवादी गणराज्य			
क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन %
1.	मेसर्ज जिआंग्सू जिनटुंग केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड	मेसर्ज होटुंग केमिकल कार्पोरेशन और मेसर्ज शार्पिनवेस्ट	0-10
2.	मै. जियांग्सू जिनटुंग केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड	मै. जियांग्सू जिनटुंग केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड	0-10
3	कोई भी	कोई भी	0-10

(ग)

ईरान			
क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन %
1.	कोई भी	कोई भी	0-10

#### ठ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

80. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभावों से उसकी कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने और कीमत ह्रास के प्रभाव के रूप में पाटन-रोधी संबंधी भारतीय नियमावली और करार के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से भिन्न कोई अन्य कारक भी घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार कारण हो सकता है।

#### (क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात अधिक कीमतों पर किए गए हैं अथवा वे संबद्ध वस्तुओं की मात्रा के आंकड़ों के रूप में नगण्य हैं। सऊदी अरब से आयातों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। तथापि, यह नोट किया गया था कि जिन कीमतों पर सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जा रहे थे, उनके कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी। इन कीमतों को वर्तमान मामले में भी दुबारा नकारात्मक पाया गया है।

#### (ख) मांग का संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

82. समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में गिरावट आना घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

#### (ग) प्रोद्योगिकी में विकास

83. संबद्ध उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोद्योगिकी में किसी भी प्रकार का कोई विघटनकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रोद्योगिकी में संभावित विकास, घरेलू उद्योग की क्षति का कारक नहीं है।

#### (घ) व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

84. ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

85. घरेलू उद्योग के निर्यात का हिस्सा, उनकी कुल बिक्रियों में बहुत कम बनता है। हालांकि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में गिरावट आई है, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति की सूचना, घरेलू प्रचालनों के लिए है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा यह माना गया है कि निर्यात की मात्रा में गिरावट आना घरेलू उद्योग की क्षति के लिए प्रासंगिक नहीं है।

**(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

86. यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान उत्पादन प्रति कर्मचारी के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट इतनी अधिक है कि उसमें गिरावट आने को उत्पादकता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

87. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों से क्षति हुई हो। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित प्राचलों से पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:-

- (क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात अत्यधिक थे जिनके कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को अत्यधिक कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मुख्यतया यह नोट किया जाता है कि देश में पाटन के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हुआ है।
- (ख) घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को अत्यधिक कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा था जिसके कारण उसको वित्तीय घाटे हुए हैं। इस प्रकार आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में अत्यधिक गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे हुए हैं।
- (ग) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप बिक्रियों, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। यदि इस पर विचार किया जाता है कि पूर्णतया पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में गिरावट नहीं आई है, फिर भी लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट बहुत अधिक है और यह वास्तविक है। अकुशलता और परिवर्तनीय प्रचालन कारकों के कारण हुई घरेलू उद्योग की क्षति का समाप्त करने के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने से ऐसे कारक समाप्त हो जाते हैं। घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटे हो रहे हैं। इस प्रकार उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

**प्रकटन पर टिप्पणियां :**

88. प्रकटीकरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित टिप्पणियां विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई हैं अर्थात् घरेलू उद्योग के लिए मै. टीपीएम, सीसीईएफ, मंताजत और रेनिश पेट्रो कैमिकल की ओर से मै. ई.एल.पी., मै. जियांगसू जिनतुंग कैमिकल्स कार्पो. लि., मै. होतुंग कैमिकल कार्पो. और शापेइवेस्ट, मै. ग्रेट ओरिएंटल कंपनी, चीन की ओर से मै. दुआ एसोसिएट्स, डीएमएआई और हिंदुस्तान यूनिलिवर की ओर से मै. एल के एस।

**1. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

- (क) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेचा गया उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य और विशेष रूप से ईरान द्वारा निर्यातित उत्पाद से भिन्न है। प्रयोक्ता उद्योग द्वारा ईरान और चीन से निर्यातित उत्पाद के मामले में अपेक्षित अतिरिक्त मात्रा क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत है। इसलिए, इसके लिए समंजन, पहुंच कीमत अथवा क्षति मार्जिन के लिए कारक होना चाहिए।

**2. घरेलू उद्योग का आधार/कार्यक्षेत्र**

- (क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के समय घरेलू उद्योग के लिए "मुख्य अंश" का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियाविधि का उपयुक्त रूप से प्रकटन नहीं किया है। हालांकि निरमा और टीएनपीएल का भारत के कुल उत्पादन में केवल 32 प्रतिशत अंशदान है, फिर भी जांच शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आरआईएल को शामिल करना भी आवश्यक समझा है, जिसने असावधानीपूर्वक से यह स्वीकार किया है कि निरमा और टीएनपीएल का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख भाग नहीं बनता है। इस तथ्य के बावजूद कि जांच शुरू करने के 6 महीने के बाद आरआईएल ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आरआईएल को शामिल करना स्वीकार कर लिया है। जांच के ऐसे विलंबित चरण में आर आई एल को शामिल करना न केवल उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करना भी है।
- (ख) संयुक्त आंकड़े सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में आरआईएल को शामिल करके प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के उत्पादन को प्रमुख अंश नहीं माना जा सकता है।

(घ) प्रकटन विवरण से यह सिद्ध होता है कि हितबद्ध पक्षकार यह मत प्रकट करके कि यदि आर आई एल के आंकड़ों को शामिल कर लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने का मामला नहीं बनता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे।

(ङ.) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के भाग के रूप में आर आई एल को शामिल करके स्थापित क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया है और जांच को समाप्त नहीं करके अपना दायित्व नहीं निभाया है।

### 3. सामान्य मूल्य

(क) चीन और ईरान के लिए सामान्य मूल्य की संरचना पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। प्राधिकारी ने चीन और ईरान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उल्लिखित प्रावधानों को उचित ढंग से लागू नहीं किया है।

(ख) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन, क्षति विश्लेषण, विलंबित तारीख को आर आई एल के द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र में हुए विलंब को माफ करने जैसे विविध निवेदनों तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अनेक अन्य मुद्दों पर विचार नहीं किया है।

(ग) कतर के मामले में परिकलित सामान्य मूल्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उप-उत्पाद की बिक्रियों के राजस्व को लागत से बाहर नहीं रखा गया है।

### 4. क्षति

(क) संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन आयातों का घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। घरेलू उद्योग की क्षमता का रिकॉर्ड उचित ढंग से नहीं रखा गया है क्योंकि इसमें आरआईएल के वदोदरा संयंत्र के बंद होने को नहीं दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यहास में वृद्धि होने के कारण आर आई एल की लाभप्रदता कम हुई है। बिक्रियों की लागत में गिरावट को आर आई एल के बढ़ते मूल्यहास के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है। क्षति और पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

(ग) घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों से हुई है, जैसे कि विद्युत कटौती में वृद्धि, मिट्टी के तेल की लागत में वृद्धि और उसके गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, सामान्य पैराफिन आयातों की उपलब्धता की अनिश्चितता और विनिमय में उतार-चढ़ाव होने का खतरा जैसा कि तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. द्वारा सूचित किया गया है।

(घ) क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निर्धारित एन आई पी के मिश्रित ब्यूरे घरेलू उद्योग को प्रकट किए जाने चाहिए थे ताकि याचिकादाता उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें।

(ङ.) प्राधिकारी ने सउदी अरब से आयातों के नकारात्मक क्षति मार्जिन का प्रकटन नहीं किया है और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसा वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर किया गया है।

(च) घरेलू उद्योग को कोई कीमत क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी ने केवल कीमत और लागत के चरण पर विचार किया है, लेकिन फीड स्टॉक लागत के साथ बिक्रियों की लागत को उचित ढंग से नहीं देखा है। घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि उसकी अंतरभूत कमियों के कारण हुई है।

(छ) घरेलू उद्योग और आरोपित पाटन के बीच कारणात्मक संबंध होने की स्पष्ट कमी है।

(ज) प्राधिकारी को सउदी अरब की सीआईएफ कीमत और नकारात्मक क्षति मार्जिन के परिकलन के विवरण प्रदान करने चाहिए।

(झ) मै. ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड को उत्तर देने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि, उसने एमईटी और एफओबी कीमतों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके बारे में हमें सूचित करना चाहिए था।

(ट) घरेलू उद्योग के लिए परिकलित एनआईपी कीमत के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बताया जाना चाहिए।

(ठ) पहुंच मूल्य का निर्धारण विभिन्न मानदंडों के अनुसार भिन्न रूप से किया गया है।

(ड) इसकी आयात सामग्री पश्चिम समुद्री तट के साथ-साथ पूर्वी समुद्री तट पर आयी थी। इनके कारण होने वाले कीमत अंतर को ध्यान में नहीं रखा गया है।

- (ढ) जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। केवल याचिकादाताओं ने ही क्षति के बारे में सूचित किया है न कि दो अन्य उत्पादकों ने। घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कीमत में गिरावट आने का कारण मुख्यतः कच्चे माल की कीमतें होना है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग के साथ घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों से क्षति होने का पता नहीं चलता है।
- (ण) प्राधिकारी ने एल ए बी का उत्पादन करने की एकीकृत सुविधा के मुद्दों पर विचार नहीं किया है और उन्होंने एनआईपी का परिकलन उचित ढंग से नहीं किया है।
- (त) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दायरे से सउदी अरब को बाहर रखने के लिए विश्वास की गई क्रियाविधि और परिकलनों का उपयुक्त रूप से प्रकटन नहीं किया है।
- (थ) हालांकि प्राधिकारी ने कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए त्रैमासिक आधार पर कीमत की तुलना करना महत्वपूर्ण समझा है, फिर भी ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग तथा त्रैमासिक विश्लेषण, पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए भी किया जाना चाहिए था।
- (द) याचिकादाताओं को हुई क्षति के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है क्योंकि याचिकादाताओं को मात्रात्मक क्षति सउदी अरब से आयातों के कारण हुई है। इसलिए संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की कीमत और याचिकादाताओं की कीमत के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। साथ ही, आयातों की मात्रा और मूल्य के बीच भी कोई सह-संबंध नहीं है तथा याचिकादाताओं के कार्य निष्पादन तथा बिक्रियों की मात्रा, बाजार का हिस्सा, उत्पादन, अन्त स्टॉक और उत्पादकता जैसे आर्थिक प्राचल से सकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है।
- (ध) प्राधिकारी ने विभिन्न गैर-जिम्मेदार कारकों जिनमें तृतीय देशों (सउदी अरब) से आयातों का मूल्य और कीमत, प्रौद्योगिकी में विकास, कतर से विचाराधीन उत्पाद के आयात जोकि टीपीएल के उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, याचिकादाताओं द्वारा अनुभव किए गए फीड स्टॉक की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे और याचिकादाताओं को अपरिष्कृत तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण शुरू हुए घाटे तथा नकदी प्रवाह के मुद्दे शामिल हैं, का प्रकटन और उनका समाधान उचित ढंग से नहीं किया है।
- (न) मै0 रेनिस, निर्यातक ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उसने उनकी जांच में सहयोग नहीं दिया है, इसलिए उसे वर्तमान तथ्यपरक सांचे में सहयोगी नहीं माना जा सकता है। तदनुसार उसके आंकड़ों को पाटन मार्जिन के परिकलन से बाहर रखा जाना चाहिए। पूर्वाग्रह के बिना मै. रेनिस के आंकड़ों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो अपनाई जा रही अभूतपूर्व पद्धति के लिए यथोचित कारण होने चाहिए कि जब कोई पक्षकार असहयोगी होता है और यह स्पष्ट होता है कि समय-समय पर बिक्रियों के निर्यात किए गए हैं, और वह भी जब प्राधिकारी द्वारा त्रैमासिक क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन पाटन और क्षति के परिकलन के लिए औसत क्रियाविधि का अनुपालन कर रहा है, ऐसा करना क्यों उचित है।
- (प) मै. दुआ एसोसिएट्स जोकि मै. जियांगसु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मै. होटंग कैमिकल कॉर्पोरेशन और मै. शार्प इन्वेस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं, ने बताया है कि गोपनीय प्रकटन में उनको प्रकट की गई कारखानागत निर्यात कीमत सही है। उन्होंने यह निवेदन किया है कि चीन से आयात होने के कारण कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की मात्रात्मक और कीमत संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी द्वारा इसकी पुनः संपुष्टि की जानी चाहिए कि सउदी अरब से आयातों के कारण कीमत में कोई कटौती नहीं की गई है अथवा क्षति होने का परिकलन नहीं किया गया है।
- (फ) मै. ग्रेड ओरिएण्टल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड की बिक्री कीमतें उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर फराबी की हैं और ये भारत में कुल बिक्रियों का केवल 1.35 प्रतिशत भाग है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और लाभ में गिरावट अन्य कारणों से हुई है, जैसे कि फीड स्टॉक की कमी, कच्चे माल की अनिश्चित आपूर्ति और उसकी अनिश्चितता तथा अपरिष्कृत तेल की कीमतों में गिरावट।

## 5. पाटन मार्जिन

- (क) संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय वृतांत घरेलू उद्योग को प्रकट किया जाना चाहिए।
- (ख) बिक्रियों के दोनों माध्यम के लिए कतर के मामले में निर्यातक वस्तुतः वहीं है, अर्थात् मुंताजत है, हालांकि एक माध्यम में रेनिस की उपस्थिति है। इसलिए अनुचित लाभ की रोकथाम करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्शाया गया है, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मुंताजत द्वारा की गई सीधी बिक्रियों के संबंध में कम है। इस प्रकार, निर्यातक के लिए यह बहुत सुगम होगा कि वह सीधी बिक्रियों को अपनाए ताकि रेनिस द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होने के बावजूद कम पाटनरोधी शुल्क लगे। वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अधिक मात्रा से पूर्णतः कुंठित होंगे।



- (ग) मै0 ईएलपी ने बताया है कि प्राधिकारी को तुलना की त्रैमासिक विधि को अपनाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने शुल्क के अधिक मार्जिन का परिकलन करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदला है। प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत का समंजन करने में मै0 सीफ लिमिटेड की एस एंड डी लागत पर विचार किया है, जिसे उत्पादन की लागत में भी शामिल किया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत के लिए घटाया गया विपणन शुल्क उचित नहीं है क्योंकि ग्राहकों के लिए बिक्री कीमत का निर्धारण विशिष्ट रूप से मै0 मुंताजद द्वारा किया गया है, जिसके लिए मै0 सीफ लिमिटेड के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के अपने परिकलन में सत्यापित आंकड़ों से विचलन के लिए क्रियाविधि और कारणों का प्रकटन उचित रूप से नहीं किया है तथा रेनिस पैट्रोकेम को वर्तमान जांच में सहयोगी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली के अपने उत्तर में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के सत्यापन में शामिल नहीं होने के साथ-साथ प्राधिकारी की जांच प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया है।

## 6. अन्य मुद्दे

- (क) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को याचिका के अगोपनीय वृत्तांत को प्रस्तुत करने में 37 दिनों का समय लेकर अत्यंत विलंब किया है, जोकि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.3 के असंगत है। इस कार्य में 37 दिनों के विलंब होने से जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसे माफ नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में मैक्सिको से ग्रे-पोर्टलैंड सीमेंट पर ग्वाटेमाला-सुनिश्चित पाटनरोधी उपाय संबंधी दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 के डब्ल्यू टी/ डी एस 156/आर के निर्णय का हवाला दिया गया है जिसमें यह माना गया है कि जांच शुरू होने के 8 दिनों के बाद याचिका उपलब्ध कराना पाटनरोधी करार का उल्लंघन करना है। इसलिए, वर्तमान जांच को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (ख) पाटनरोधी शुल्क लगाना, जनहित में नहीं है क्योंकि इसके फलस्वरूप डिटरजेंट और पेस्टीसाइड्स की कीमतों में वृद्धि होगी।
- (ग) प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रति तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की प्रति का भी प्रकटन किया जाना चाहिए।
- (घ) निर्धारित मात्रा में शुल्क लगाए जाने चाहिए क्योंकि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सीमाशुल्क बंदरगाह के प्राधिकारियों के पास ऐसा तंत्र नहीं है जिससे एक आयातक द्वारा सूचित की गई आयात कीमत की परिशुद्धिता सुनिश्चित हो सके। बंदरगाह के प्राधिकारियों के लिए आयात कीमत को सत्यापित करना न ही उपयुक्त है और न ही व्यवहार्य है। निदेशालय ने शुल्क को मानक के रूप में स्वीकृत किया है न कि शुल्क को उपयुक्त रूप में और उसने अनेक मामलों में उपायों के रूप में परिवर्तन किया है और यह कि शुल्क अमरीकी डॉलरों में लगाया जाना चाहिए।

## प्राधिकारी की जांच

89. प्राधिकारी ने प्रकटन के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है जोकि निम्नानुसार है :-

- (क) प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता मैसर्स निरमा लिमिटेड और मैसर्स तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. का याचिका दायर करने के समय भारतीय उत्पादन का प्रमुख अंश बनता है। तथापि, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर क्षति विश्लेषण को सुदृढ़ बनाने के लिए मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जोकि पहले उसका एक समर्थक था, उसे भी घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया गया है ताकि घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में उसको शामिल करके क्षति का गहन मूल्यांकन के लिए सार्थकता और प्रतिनिधिक बढ़ाया जा सके जोकि किसी भी माइने में यह नहीं माना जाए कि याचिकादाता का याचिका दायर करने के लिए आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षति का संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए आरआईएल के आंकड़ों पर विचार करना जांच प्रक्रिया का एक भाग है, जिसे प्राधिकारी ने विभिन्न प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण रखा है। जांच शुरू करने के समय विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा प्रत्युत्तर भेजने में विलंब नहीं करने के अनुरोध को समयबद्ध तरीके से भेजना अनुचित है क्योंकि यह पूर्णतया विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों पर सौंपा गया भिन्न दायित्व है।
- (ख) विभिन्न आर्थिक प्राचलों में घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 (2) के अनुबंध-2 में सूचीबद्ध सभी निर्धारित आर्थिक प्राचलों का क्षति मूल्यांकन किया है तथा विश्लेषित प्रभाव को विभिन्न प्राचलों पर पृथक रूप से देखा है तथा विशेषकर जांच अवधि में कीमत पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समग्र विश्लेषण किया है जोकि क्षति मार्जिन के रूप में मात्रा में निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित उत्पादन की भारित औसत लागत में कमी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विभिन्न लागत संघटकों का सामान्यकरण करके दूर कर दिया गया है।
- (ग) हितबद्ध पक्षकारों को संशोधित जांच अवधि के लिए एनसीवी की प्रति प्रदान करने में हुए 37 दिनों के विलंब के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि 12 महीनों की अवधि के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई एनसीवी याचिका पूर्णतः

सार्वजनिक फाइल पर उपलब्ध थी जिसको वांछित हितवद्ध पक्षकारों द्वारा देखा गया था/लिया गया था। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना सभी पक्षकारों के सूचनार्थ डीजीएडी की वेबसाइट पर उपलब्ध थी। हालांकि बाद में याचिका का संशोधित एनसीवी वृतांत उपलब्ध करा दिया गया था और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय था तथा प्राधिकारी द्वारा उसकी समयावधिक बढ़ाई गई थी। इसलिए किसी भी पक्षकार के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। वास्तव में विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच में हुई दो मौखिक सुनवाई में निवेदन किए गए हैं। उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने कतर और घरेलू उद्योग के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा उठाए गए सामान्य मूल्य और एनआईपी के सीमित मुद्दों पर दिनांक 2 मार्च, 2017 को प्रकटन पश्चात सुनवाई भी की है।

- (घ) प्राधिकारी सउदी अरब को शामिल नहीं किए जाने पर बार-बार किए गए निवेदनों को नोट करते हुए यह दोहराते हैं कि सउदी अरब से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का भारित औसत पहुंच मूल्य से नकारात्मक क्षति मार्जिन का पता चलता है कि जांच शुरू करने के चरण में ही जांच के कार्यक्षेत्र से सउदी अरब को बाहर निकालने की प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि होती है।
- (ङ.) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां जारी की थीं। मैसर्स जियांग्सु, मै.शार्पिन बेस्ट और मै0 होटिंग के प्रतिनिधि मै0 दुआ एसोसिएट्स ने ही निर्धारित प्रपत्र के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड सहित किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने समय पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। बड़ी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद उत्पादक/निर्यातकों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करने के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है। मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड के इस तर्क के संबंध में कि उसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों को 22 फरवरी, 2016 तक निर्धारित प्रश्नावली में आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था। कुछ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर समय सीमा को बढ़ाकर 8 मार्च, 2016 कर दिया गया था। प्राधिकारी द्वारा किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा विलंब से दिए गए उत्तर पर विचार नहीं किया गया है। मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड द्वारा उल्लिखित प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए गए आंकड़े अपूर्ण थे और वे निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे जिसमें निर्यात कीमत के समंजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार के समर्थक प्रमाण को प्रस्तुत किया गया है। अत्यधिक विलंबित तारीख को दिए गए ऐसे अपूर्ण उत्तर पर प्राधिकारी द्वारा उनकी सुसंगत पद्धति के अनुसार विचार नहीं किया गया है। ऐसे उत्पादक/निर्यातक को अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग के आधार, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी प्रश्नावली का भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, हालांकि उन्होंने ऐसी सूचना प्रदान किए जाने का दावा किया है। कंपनी ने मात्र यह बताया है कि वह सिंगापुर में पूर्णतः मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन है और एसीआरए के कारोबार की छवि के क्षेत्र के साथ किसी भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (च) कुछेक प्रयोक्ता ने यह उल्लेख किया है कि उनके निवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार, विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी प्रासंगिक मुद्दों का इस जांच परिणाम के संबंधित भागों में उपयुक्त रूप से समाधान करते हैं ताकि इस संबंध में बार-बार निवेदन न किए जाएं। घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र, घरेलू उद्योग की क्षति और पाटन के कारण होने वाली क्षति मोलेकुलर भार में भिन्नता होने के कारण समंजन पर जैसे मुख्य तर्कों पर उचित रूप से विचार किया गया है। प्राधिकारी ऐसे समंजन के संबंध में प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध को विशेष रूप से नोट करते हैं और दोहराते हैं कि आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग की समान वस्तु के बीच किसी प्रकार का अंतर होने के कारण कारखानागत निर्यात कीमत पर समंजन करने की मात्रा के निर्धारण को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में 2 मार्च, 2017 को हुई सिविल सुनवाई में दो सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने निवेदनों में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उन्होंने इस प्रकार के अंतर के कारण अपनी कारखानागत निर्यात कीमत में किसी प्रकार का समंजन करने का दावा किया है। इसलिए ऐसे किसी भी समंजन पर विचार नहीं किया गया है।
- (छ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सीफ लिमिटेड, मै. मुंताजत और मै. रेनिश पैट्रोकेम एफजैडई के प्रतिनिधि मै. ईएलपी ने यह बताया है कि मै. रेनिश एक असहयोगी उत्पादक/निर्यातक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. रेनिश ने प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के अपने उत्तर में सीआईएफ कीमतें उल्लिखित की हैं। निर्यात के इस माध्यम के लिए सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत का आधार सीफ, उत्पादक और उसके सहयोगी निर्यातक नामतः मुंताजत द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं, इसलिए ऐसे कानूनी प्रतिनिधि का तर्क जिसने रेनिश पैट्रोकेम की ओर से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, द्वारा यह घोषित करना कि वह

एक असहयोगी है, न युक्तिसंगत है और न ही तर्कसंगत। प्राधिकारी ने इसलिए इस माध्यम के लिए भी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।

- (ज) मुंताजात के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का समंजन करने के लिए विचार किए गए सीफ के एस एंड डी व्ययों को सही किया गया है क्योंकि उन्हें सीफ की उत्पादन लागत में शामिल किया गया है।
- (झ) मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मै. सीफ के संपूर्ण उत्पादन की मुंताजात, घरेलू और सभी भूमंडलीय लक्ष्यों के निर्यातक ने 2012 के डिक्री कानून के जरिए बिक्री की है। कीमत निर्धारण मुंताजात द्वारा किया गया है और विपणन शुल्क व निर्यातों पर विभिन्न व्ययों की कटौती के पश्चात निवल आय सीफ को अदा की गई है। यह नोट किया गया है कि मै. ई एल पी ने निर्यातों की दोनों तालिकाओं के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं अर्थात् मुंताजात के जरिए भारत को और मुंताजात और रेनिश से भी भारत को। दोनों तालिकाओं के लिए पाटन और क्षति मार्जिन का पृथक-पृथक निर्धारण किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादक और इसका विशिष्ट निर्यातक दोनों तालिकाओं के लिए समान हैं, हम दोनों तालिकाओं के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन और कम शुल्क नियम को लागू करने के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन भी निर्धारित कर सकते हैं।
- (ट) गोपनीय प्रकृति के एनआईपी/अन्य आंकड़ों को अन्य हितवद्ध पक्षकारों को सूचित करने के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से भिन्न अन्य हितवद्ध पक्षकारों को एनआईपी का प्रकटन नहीं करने की सुसंगत पद्धति का अनुपालन किया है।
- (ठ) क्षति और कारणात्मक संबंध पर किए गए निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी ने बंदरगाह के क्लियरेंस की ओर ध्यान दिए बिना सहयोगी और असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए पहुंच मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए भी इसी कार्यप्रणाली को अपनाया है। प्राधिकारी का विचार है कि समग्र जांच अवधि के लिए सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत के साथ करना भी समान रूप से प्रतिनिधिक और उपयुक्त होगा।
- (ड) 2 मार्च, 2017 को हुई सीमित सुनवाई में मै. ईएलपी द्वारा किए गए निवेदनों और तथा 2 मार्च, 2017 को दिए गए उनके स्पष्टीकरण के आधार पर प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत से उप-उत्पाद के बिक्री राजस्व का समंजन किया है। मै. सीफ लिमिटेड के एस एंड डी व्ययों को निर्यात कीमत में से घटाया नहीं गया है, जैसा कि निर्यातक द्वारा 2 मार्च, 2017 को हुई सीमित सुनवाई में दावा किया है और स्पष्टीकरण दिया गया है।

90. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है।

#### ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

91. मांग-पूर्ति की स्थिति और प्रयोक्ता उद्योग पर उसके प्रभाव पर प्रयोक्ता उद्योग के निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी इस बात को मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रुकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पर्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

#### निष्कर्ष

92. विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा तर्कों की जांच करने के बाद और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:

- (1) संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद का पाटन हो रहा है।
- (2) संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत ह्रास कर रहे हैं।
- (3) बाजार के हिस्से और लाभप्रदता के रूप में घरेलू उपयोग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है।
- (4) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

**सिफारिशें**

93. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर प्राधिकारी ऐसी सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं कि नीचे शुल्क तालिका में वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निम्नलिखित पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

94. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कालम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है। प्राधिकारी का यह विचार है कि यह सिफारिश करना आवश्यक है कि नीचे दी गई तालिका में यथा निर्धारित विधि और पद्धति से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

**शुल्क तालिका**

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	मेसर्ज होटुंग केमिकल कॉर्पोरेशन और मेसर्ज शार्पिनवेस्ट इन्टरनेशनल लि.	23.78	अम.डॉ.	मी.ट.
2	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	147.11	अम.डॉ.	मी.ट.
3	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रमांक 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य संयोजन		147.11	अम.डॉ.	मी.ट.
4	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	147.11	अम.डॉ.	मी.ट.
5	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	147.11	अम.डॉ.	मी.ट.
6	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंतजात*	46.49	अम.डॉ.	मी.ट.
7	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंतजात * और मै. रेनिश	46.49	अम.डॉ.	मी.ट.

					पेट्रोकेमिकल एफजेडई (व्यापारी)			
8	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	उपरोक्त क्रमांक 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य संयोजन	300.22		
9	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	300.22	अम.डॉ. मी.ट.
10	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कतर	कोई	कोई	300.22	अम.डॉ. मी.ट.
11	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	ईरान	कोई	कोई	71.8	अम.डॉ. मी.ट.
12	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	71.8	अम.डॉ. मी.ट.
13.	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	ईरान	कोई	कोई	71.8	अम.डॉ. मी.ट.

\*मै. कतर कैमिकल कैमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी., कतर

### आगे की प्रक्रिया

95. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2017

**FINAL FINDINGS****(Anti-Dumping Investigation)****Sub: Anti Dumping investigation concerning imports of ‘Linear Alkyl Benzene’ originating in or exported from Iran, Qatar and China PR**

**14/20/2015-DGAD:** Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

**A. Background of the case**

Whereas M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd and M/s Nirma Ltd (hereinafter referred to as “petitioners”) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter mentioned to as “the Authority”) in accordance with the Customs Tariff (Identification, Assessment And Collection Of Anti-Dumping Duty On Dumped Articles And For Determination Of Injury) Rules, 1995 (hereinafter “the Rules”) for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the imports of “Linear Alkyl Benzene” (hereinafter as “the subject goods” or “product under consideration” or “LAB”) originating in or exported from Iran, Qatar, China PR and Saudi Arabia.

**B. Procedure**

1. The procedure described below has been followed.
  - a. The Designated Authority under the above Rules, received a written application from M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd. and M/s. Nirma Ltd. as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of Linear Alkyl Benzene (*hereinafter referred to as “subject goods” or “LAB”*) originating in or exported from Iran, Qatar, China PR and Saudi Arabia and resultant injury to domestic industry.
  - b. The application filed by the petitioners was considered by the Authority as properly documented for initiation of the anti-dumping investigation.
  - c. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigations in accordance with Rule 5 sub-rule (5) of the AD Rules.
  - d. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from Iran, Qatar and China PR (*hereinafter referred to as the “subject countries”*). As mentioned in the initiation notification, the Authority found negative injury margin on imports of subject goods from Saudi Arabia for the period of investigation and therefore did not consider it appropriate to initiate investigation in respect of imports of subject goods from Saudi Arabia as a subject country in the present investigation.
  - e. The Authority issued a public notice dated September 7<sup>th</sup> December, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject countries. A corrigendum dated 13/1/2016 was also issued to rectify a minor error in the initiation.
  - f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Petitioners) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
  - g. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
  - h. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of the People’s Republic of China in India, Embassy of Islamic Republic of Iran and Embassy of Qatar in

India, in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, whenever requested.

- i. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/ producers of the subject goods from China PR were, therefore, advised to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in China PR. However, none of the respondent producers/ exporters from China PR have filed MET questionnaire response rebutting the non-market economy treatment meted out to China PR.
- j. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Iran Chemicals Industries Investment Companies, No.91 Saidi St Africa Ave Teheran (19679 ) Iran	Kolmar Group Ag, Laubehof, Metallstrasse 9, 6300 Zug, Switzerland
Seef Limited, Qatar, Seef Limited, Post Box: 50077, Mesaieed, State of Qatar	Jiangsu Jintong Chemical Co., Ltd 201 Yaixin Ave, Qixia, Nanjing, Jiangsu, China, 210046
Jinzhou Yongjia Chemical Industry Co., Ltd.; No.25, Bai Guan Li, LingHe District, Jinzhou City Liaoning Province China PR	Petrochina International Fushun Co., Ltd.; 16- Hunhe Road North Fushun Liaoning Province China PR
Sinopec Jinling Petrochemical Corporation ; No. 22, Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing, China PR	Great Orient Chemical (Taicang ) Co. Ltd ; Room 807, Century Wealth Building., No.86 Shanghai Road(E), Taicang, Jiangsu Province, China 215400
Great Orient Chemical (Taicang) Co. Ltd. ; 11 South Binjiang Road, Taicang Road Development Zone Jiangsu, 215433 – China	

- k. In response to the initiation notification, the following exporters/producers from the subject countries have responded:
  - i. M/s SEEF Limited, Qatar. (Producer)
  - ii. M/s Great Orient Chemical (Taicang) Co., China
  - iii. M/s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C., Qatar (Exporter)
  - iv. M/s Jiangsu Jintong Chemical Corp. Ltd and its related parties Hotung Chemical Corp and Sharpinvest, China PR
  - v. Renish Petrochem FZE
- l. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

M/s Fashion Suiting (P) Ltd. 3, Chhabra Mansion; Puri Road Bhilwara-311001	M/s Shree Unicon Organics Pvt. Ltd. BS, Apjee ; 130 Mumbai Samachar Marg Mumbai-400023
A.R Salphonates Pvt. Ltd. Plot No. N41 ; Additional Ambernath, MIDC Anand Nagar ; Dist.Thane -421501 ; Maharashtra	Tamil Nadu Small Scale Soap & Detergents ; Chateau 'D Ampa, IV Floor , No37, Old No. 110 ; Nelson Manickam Road ; Chennai-600029
Shanati Nath Detergents (P) Limited P-15, Kalakar Street ; Kolkata-700007	Rajaram Group of Industries ; 14, Azeez Nagar IInd Street ; Kodambakkam Chennai.600024
Kishors Sons Detergents Pvt. Ltd. 15-9-469, Mahanoongunj Hydrerabad – 500012. (A.P.)	Advance Surfactants India Limited 511/2/1. Rajokri, New Delhi-110038
A.R. Stanchem Pvt. Ltd. Exporters & Manufacturers Old Court House Street 2nd Floor, Coke & Kalvay Building Kolkata 700001	New India Detergents Limited A-2/25 Model Town -1 Delhi-110009
M/s Small Scale Detergents 43 European Asyum Lane , Kolkata -700016	Standards Surfactants Ltd 8/5 Arya Nagar, Kanpur-208002
Gora Mal Hari Ram Ltd. 39, Najafgarh Road, Indl. Area New Delhi -15	Detergents Manufacturers Associations 148 New Okhla, Industrial Complex-I New Delhi-110020
Barkur Surfactants Pvt. Ltd. Unitop House , East West Estate Safed Pool, Andheri Kurla Road Mumbai-400072	ISRO Product Unitop House , East West Estate Safed Pool, Andhari Kurla Road Mumbai-400072
S. Kumars Detergents Pvt. Ltd 4-D, Local Shopping Centre , A Block , Ring Road, Naraina , New Delhi-110028	Saci- Chem 59 & 60 DSIDC, Industrial Complex Okhla , Phase-I, New Delhi-110020
Hipolin Limited , Madhuban , 4th Floor , Ellis bridge, Ahmedabad -380006	All India Federation of Detergents Manufacturers ; 511/2/1, Rajokari, New Delhi -38
Maharashtra Small Scale Soap Detergents Manufacturers Association ; Shree Veerabai Maa Niwas ; Shastri Nagar Square, Nagpur-8 ; Maharashtra	Gujrat Small Scale Detergents Manufacturing Association ; C/o Kishore Soap Industries ; Maheshwari Mill Road, Tavdipura, Shahibaug ; Ahmedabad – 380004
Power Soaps Ltd ; 62-B, North Boag Road ; T. Nagar,	M/s Bhaskar Venkatesh Products Pvt. Ltd ; Bhawani Complex ; 35,



Chennai-600017	Hanumanganj, Near Jumerati Corner, Bhopal – 462001 (M.P.)
M/s Abdos Consumer Care Limited, Jalan Compound, Bombay Highway, NH No. 6, Biparannapara, Howrah – 711411	M/s Prabu Soap Works, P.Box No. 5115, 3/A1; Thayir Itteri Road, Kannappan Nagar ; Rathinapuri (P.O.) Coimbatore – 641 027
M/s Shiva Soap Works, Nanthavana Patti, Dindigul – 624005	M/s Bharathi Soap Works, Ist Line ; Nallacheruvu, Guntur – 522 003 (A.P.)
M/s Sabari Detergents, 191, Valparai Road ; Avalchinnampalayam, Zamin Kottampatti, Pollachi – 642 123	M/s S.S. Enterprises, No. 43, SIDCO Industrial Estate, Dindigul – 624 003
M/s Man Chemicals, 20/1, Sivakami Illam, Lakshmi Sundaram Colony, Behind M.S.P. School Ground, Dindigul – 624 005	M/s Sakthi Traders, No. 5/810, Malligai Road, Kootturavu Nagar, Dindigul – 624 005
M/s Shriram Bharat Chemicals & Detergents (P) Ltd., 1/56, Sanjay Gandhi Nagar, Nochipalayam Road, 46, Pundhur Village, Erode – 638002	M/s National Soaps Company, 138/1, Semmam Palayam Pirivu, Nasiyanur Road, Villarasampatti Nall Road, Nasiyanur (P.O.) Erode – 638107, T.N.
M/s Sree Manakula Vinayaga Chemicals, R.S. No. 89/1-F & D, Pannithittu Road, Kirumampakkam, Puducherry – 607 402	M/s Silver Chemicals, 1/255, Main Road, Valayankulam, Madurai – 625 022, Tamil Nadu
M/s Raja Chemical Works, # 137, Sami Iyer New Street, Coimbatore – 641 001	M/s Sree Pushpam Industries, R.S. No. 121/1 & 63/7, Madagadipet & Tirubuvani Village, Tirubuvanai Post, Pondicherry – 605107
M/s Lingam Chemical Industries, 8/55, Ambai Road, Alangulam – 627851, Tirunelveli, Tamilnadu	M/s Anand Chemicals, 13/4 Kamarajar Nagar, Avaniyapuram (P.O.) ; Ayanpappakudi Madurai – 625012 (T.N.)
M/s Hi-Tech India, No. 1, Vengur Road, Thiruverumbur, Trichy – 620 013	M/s Flora Chemicals, 2/226, Ammatchi Amman Koil Street, Uthangudi, Madurai – 625 107

M/s Devi Cropscience Pvt. Ltd. P.B. No. 274, 29-A, Workshop Road, Madurai – 625 001	M/s Shunmuga Industries, 139-ABC, Sundakkamuthur Road, Selvapuram, Coimbatore – 26
M/s Cymose Products, 4/139. Ayyanarpuram Main Road, Panaiyur (P.O.), Madurai – 625009	M/s Raceme Products, 2/221., Ayyanar Kovil Street, Uthangudi, Madurai – 625 017
M/s Orchid Chemicals, 183, Nedungulam Road, Pottapalayam, Sivagana Dt. 630611	M/s Muthukani Industries, 2/104 (1)- New Colony, Andipatti – P.O., Alangulam – 627 851
M/s Vardaan Detergent Private Limited, Plot No. 131, Sector – 24, Faridabad – 121005	M/s Reino Industrial Organics Pvt. Ltd., B-93, Mayapuri Phase – I, New Delhi – 64
Fena Pvt Ltd, A-67&68 Mettupalayam, PIPDIC Industrial Area, Pondicherry, 605009	Skill Dyechem, Village Panchpara, PO Radhadasi- 711309, Howrah, West Bengal

m. In response to the initiation notification, the following importers/users of subject goods in India have responded:

- vi. Hindustan Unilever Limited
- vii. Detergent Manufacturers Association of India
- viii. Ardor International Pvt. Ltd., Ardor Global Pvt. Ltd. And Chem-Edge International Pvt. Ltd
- ix. Surfactants Manufacturers Association of India
- x. Indian Home & Personal Care Industry Association

n. A copy of initiation notification was also sent to following Indian producers of the product under consideration:

M/s. Indian Oil Corporation Limited Indian Oil Bhavan No. 1, Sri Auribindo Marg, Yusuf Sarai New Delhi – 110 016	M/s. Reliance Industries Ltd Maker Chambers IV, 3 <sup>rd</sup> Floor, 222, Nariman Point, Mumbai – 400 021
--	---

- o. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in present findings.
- p. Keeping in view the request made by various exporters/importers, for an extension in time to file questionnaire response as the same required some more time in collation, the Designated Authority granted an extension of time to file responses to Questionnaires by 8<sup>th</sup> March, 2016 via Notification dated 19<sup>th</sup> February, 2016.
- q. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- r. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has referenced the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports and injury analysis. DG Systems data has also been obtained to correlate import data of subject goods during POI to India, to the extent considered necessary.
- s. Further information was sought from the petitioners and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present determination.

- t. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- u. The period of investigation for the purpose of the present investigation is April 2014 – June 2015 (15 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'Period of investigation'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2011-12, 2012-13, 2013-14 and POI.
- v. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the AD Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- w. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8<sup>th</sup> June, 2016. Subsequently another public hearing was held on 4<sup>th</sup> November, 2016 which were attended by various parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views for mutual exchange with opposing interested parties for filing rejoinders thereafter by others.
- x. Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as :
  - 1 US\$= Rs. 62.13
  - 1US\$= 3.64 QR
  - 1US\$= CNY6.1
- y. \*\*\* in this final finding represents information furnished by an interested party/any other party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- z. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 21<sup>st</sup> February, 2017 to the concerned interested parties. Comments were requested by 1<sup>st</sup> March, 2017. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
- aa. The last date to complete the investigation was extended by the Central Government till 06/03/2017.

### **C. Product Under Consideration and Like Article**

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Linear Alkyl Benzene" originating in or exported from Iran, Qatar and China PR.

### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

3. The interested parties have made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:
  - a. The product under consideration produced by domestic industry and that imported from subject countries have differences, in molecules per tonne of LAB in product imported from China being 1.6% less and from Iran 0.8% less as compared to the product supplied by the Indian domestic producers. This should be taken into account to ensure comparison of like products.

### **Views of the Domestic Industry**

4. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article.
  - a. The PUC in present petition is Linear Alkyl Benzene (LAB) and includes Mixed Alkyl Benzenes, and specifically excludes Mixed Alkyl Naphthalene.
  - b. LAB is manufactured using Kerosene, Extracted Paraffins and Benzene as raw materials. Paraffins are extracted from the Hydrobon Molex Process, from Feedstock Kerosene. These Paraffins are converted to their Olefins, by selective dehydrogenation at high temperature. The Olefins are then alkylated to Benzene, to form Linear Alkyl Benzene.

- c. LAB is mainly used to produce Linear Alkyl benzene Sulphonate, which is then used in preparation of laundry detergents, light- duty dishwashing liquids, industrial cleaners and household cleaners.
- d. There are no known commercially deployed grades of subject goods.
- e. There is no known difference in the LAB produced by the domestic industry and LAB imported from the subject countries. Both are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, product specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used (and are using) the two interchangeably.
- f. As regards the submission of interested parties with regard to differences in PUC, it is to be noted that there is a set quality specification for Linear Alkyl Benzene wherein limits for its inherent other components are defined. LAB produced by all the manufacturers, Indian or overseas meets these specifications. This is a mere misinterpretation of the product specification.

#### **Examination by The Authority**

5. The product under consideration in the present investigation is Linear Alkyl Benzene. It includes Mixed Alkyl Benzenes but excludes Mixed Alkyl Naphthalenes. The product under consideration is generally known as 'Linear Alkyl Benzene' (for short "LAB") in commercial market parlance.
6. LAB is available as a mixture of substances composed of a benzene ring attached to a single chain of carbon atoms. Several isomers of the product under consideration are possible since the benzene ring may be positioned at all carbons of the alkyl chain except the terminal carbon. The number of carbons per alkyl chain ranges for any given product from ten to sixteen. It is an organic compound with the formulae  $C_6H_5C_nH_{2n+1}$ , where 'n' ranges between 10 and 16. It is a colourless and odourless liquid, and is slightly soluble in water. It is considered to be a flammable chemical product. It performs the function of a chemical intermediate and is mainly used to produce Linear Alkyl benzene Sulphonate, which is subsequently used in preparation of laundry detergents, light- duty dishwashing liquids, industrial cleaners and household cleaners. The subject goods are being imported under Chapter 38 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
7. The petitioners have claimed that there is no known difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries. The petitioners also claimed that the technology and production process employed by them and the foreign producers are also comparable.
8. The interested parties contended difference in molecules per tonne of LAB in product imported from amongst subject countries and supplied by the domestic industry. The claim of the interested parties was examined from the information on record and at the time of on the spot verification at the premises of the Indian producers and the producer in Qatar. It is noted that the responding producer in Qatar admitted not having claimed any difference in the cost of production on account of difference in weight of molecules. It was clarified that the difference in weight of molecules is a result of difference in raw materials or processes. No producer tends to consciously produce product of a particular weight of molecules. The interested parties have not established any quantified difference in the cost and price on the basis of difference in weight of molecules.
9. Subject to above, no argument has been received from any interested party on the scope of product under consideration or like article. Examination of the product and import data submitted by the petitioners indicate that there is no difference between subject goods produced by the Domestic Industry and imported from subject countries. In view of the similarity in manufacturing process and substitutability, the Authority holds the as alike and one product for the purpose of defining the 'product under consideration'.

#### **D. Scope of Domestic Industry and Standing**

#### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

10. The interested parties have made following submissions with regard to the issue of standing and scope of domestic industry:
- a. The petitioners don't constitute 'major proportion' of the total Indian production as they produce only 32% of the total domestic production. Hence relying on the data of the petitioners, the Authority can't determine the trend of Indian producers as a whole.

- b. The requirements of "major proportion" for domestic industry and the threshold for standing are two distinct requirements under the AD Rules as the position of WTO's Appellate Body in EC-Fasteners (China). Petitioners' production at 32% of the total domestic production considered as sufficient to constitute the domestic industry is a material risk of distortion within the meaning of Rule 2(b) of AD Rules, particularly since the industry is not fragmented and the remaining 68% is held by only two major producers of the subject goods.
- c. RIL and IOCL to should file their full-fledged injury data so that the Authority may conduct an undistorted analysis for material injury considering the data of all four producers. It is undisputed that supporters are not required to file detailed injury submissions, but RIL and IOCL's participation as mere supporters is inadequate given that they actually constitute a major proportion.
- d. The letter by RIL dated 14<sup>th</sup> June, 2016 was fraught with errors and was filed after more than 7 months after initiation of investigation. No combined data for RIL along with the petitioners has been made available.
- e. At the stage of second hearing, interested parties contended that the authority should not accept RIL data, as this was significantly belated.
- f. As per the revised application one of the petitioners have imported subject good which reduces the proportion of sales of the petitioners. No details about imports have been given by the domestic industry.

### **Views of the Domestic Industry**

11. The domestic industry has made the following submissions with regard to standing and scope of domestic industry
  - a. The production of the petitioners constitutes a major proportion of total Indian production and so the petition should be considered as having been made by the domestic industry. The petitioners produce 32% of the total Indian production which constitutes 'a major proportion' under Rule 2(b) of the AD Rules. *Ratio decidendi* in the matter of *Lubrizol (India) Pvt. Ltd vs The Designated Authority* are relied upon in this regard.
  - b. None of the petitioner companies has imported the product from amongst subject countries.
  - c. Apart from the Petitioners, there are two more producers of Linear Alkyl Benzene in India, i.e., M/s. Indian Oil Corporation Limited and M/s. Reliance Industries Ltd. Both the producers have supported the present petition.
  - d. As regards the issue of RIL and IOCL filing injury data is concerned, the petitioners had made efforts and had requested these companies. While Petitioners cannot force any company to provide relevant information, the Authority for the purpose of injury analysis called for data from M/s RIL which has provided injury information during the course of the investigations.
  - e. As regards the issue of belated injury information by RIL, interested parties themselves had raised the issue of Reliance's participation contending that the share of petitioners constituted low share in Indian production. It is therefore not logical to refute the information on the pretext of it being filed much after the initiation of investigation. In any case, the interested parties have got sufficient opportunity to comment on the information provided by RIL.
  - f. The certification filed by the companies and the initiation notification shows that the petitioners have not imported subject goods from subject countries. The error in Part IV of the petition filed has been rectified.

### **Examination by the Authority**

12. Rule 2(b) defines domestic industry as under:-

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*

13. The application was filed by M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd. and M/s. Nirma Ltd. None of the petitioner companies have imported the subject goods from subject countries during the period of investigation nor are the petitioner companies related to an importer or an exporter of the product under consideration from subject countries. There are two other domestic producers of the subject goods, namely, M/s. Reliance Industries Ltd (RIL) and M/s Indian Oil Corporation Limited (IOCL) who have supported the application. While RIL's letter of support was part of the petition, IOCL has also sent its letter of support to the Designated Authority.

14. The production of the applicants during the POI accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods. Therefore, the Authority holds that the petitioners command a major proportion in the production of the subject goods in India and they meet the standing in terms of Rule 5(3) and also qualify as domestic industry in terms of Rule 2(b).

15. Post initiation, interested parties contended that share of petitioners in total Indian production was low and other large producers of the product under consideration have not provided their injury information. RIL provided their injury information during the course of the investigation. The information provided by RIL was made available to the interested parties through public file and various interested parties have offered comments on the same. As per information on record, RIL has not imported the product under consideration from amongst subject countries, nor is related to an exporter of an importer of the product under consideration in India. The information filed by RIL was verified by the Designated Authority by conducting an on the spot verification at their premises. Further, RIL has provided other relevant information deemed necessary by the authority.

16. The application was filed by M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd and M/s Nirma Ltd. The table below shows the share of applicants in the production of PUC.

<b>Statement of Indian Production</b>				
	2011-12	2012-13	2013-14	POI
TNPL	***	***	***	***
NIRMA	***	***	***	***
<i>Petitioners</i>	<i>185,781</i>	<i>173,646</i>	<i>138,651</i>	<i>184,836</i>
RIL	***	***	***	***
IOCL	***	***	***	***
<i>Petitioners with supporters</i>	<i>453,722</i>	<i>455,618</i>	<i>421,962</i>	<i>519,420</i>
Share of various parties				
TNPL	***	***	***	***
NIRMA	***	***	***	***
<i>Petitioners</i>	<i>41%</i>	<i>38%</i>	<i>33%</i>	<i>36%</i>
RIL	37%	36%	39%	36%
IOCL	***	***	***	***
Total Indian Production	100%	100%	100%	100%

As noted above M/s Reliance Industries Ltd. and M/s Indian Oil Corporation Ltd. had also supported the petition earlier. The applicants also accounted as a major proportion and met the standing and domestic industry requirement as per Rule 5 (3) and Rule 2 (b) of AD Rules. However as M/s Reliance Industries Ltd during the course of investigation has provided injury data and cost of production, the Authority has considered the same and included Reliance Industries Ltd in the scope of Domestic Industry. With this inclusion, the share of Domestic Industry i.e. M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd, M/s Nirma Ltd. and M/s Reliance Industries Ltd. is as under

<b>Statement of Indian Production including Reliance Industries Ltd. as part of DI</b>				
	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Domestic Industry	351,722	336,098	302,442	370,020
IOCL (supporter)	***	***	***	***
<i>Domestic Industry with supporter</i>	<i>453,722</i>	<i>455,618</i>	<i>421,962</i>	<i>519,420</i>
Share of various parties	%			
Domestic Industry	78%	74%	72%	71%
IOCL	22%	26%	28%	29%
Total Indian Production	100%	100%	100%	100%

17. Considering that domestic industry under Rule 2(b) is defined as domestic producers as a whole, or those domestic producers whose collective output constituted a major proportion in Indian production, interested parties contended that the share of petitioners in Indian production was low, and that share of RIL alone in the Indian production is significant. Addition of RIL to the domestic industry has resulted in share of domestic producers to 78 %. The Authority notes that WTO's Appellate Body has held that the share of producers in gross domestic production should be significant and that

the authority should include as many producers within the ambit of domestic industry as possible in a particular case. The authority has in view of above and submissions of various interested parties considered it appropriate to include RIL data within the scope of the domestic industry, and holds M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd., M/s Nirma Ltd. and M/s Reliance Industries Ltd. as Domestic Industry as per Rule 2 (b).

### **E. CONFIDENTIALITY**

18. With regard to confidential information, Rule 7 provides as follows:

*7. Confidential information- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

19. The interested parties have made following submissions with regard to confidentiality:

- a. Contradictory data regarding production of petitioners was filed in the petition which was also acknowledged by the domestic industry in the letter dated 2<sup>nd</sup> June 2016, where it was also stated that the confidential version contained the correct data. However the correct information was never provided to the interested parties. The figures in the non-confidential version of the petition was not corrected which is a violation of Rule 7 of AD Rules.
- b. Everything related to the calculation of normal value is kept confidential.

### **Views of the Domestic Industry**

20. The domestic industry has made following submissions with regard to confidentiality:

- a. There was a minor inconsequential error in the data filed in the petition. The error has since been rectified much before the public hearing. This error was in any case irrelevant, as it was in the import volumes reported in undercutting table for the year 2013-14, which is not the POI for the present case. Further, the price undercutting was determined by considering CIF import price, which was correctly reported.
- b. All information has been provided in the non-confidential version as per the legal provision and the practices being followed by the Authority in this regard. Only that information has been claimed confidential, which is not publicly disclosed by the Petitioner companies.

### **Examination of Authority**

21. The Authority holds that the information provided by interested parties on confidential basis meets the sufficiency requirement of the confidentiality claim. The authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted. Any information being considered confidential has not been disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available such non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file, following a consistent practice on this aspect.

### **F. Miscellaneous Issues**

### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

22. The interested parties have made following miscellaneous submissions:



- 
- a. At the time of initiation of the investigation, both confidential and non-confidential versions of the application should be in the files of Authority. Relying on Article 6.1.3 of WTO anti-dumping agreement, a delay of 37 days in providing the copy of the petition cannot be considered as acting promptly, so the present investigation must be terminated.
  - b. The document provided to the interested parties cannot be said to be the application for initiation of the investigation because the Authority did not initiate the investigation based on the same. The application filed by the domestic industry included the data relating to Saudi Arabia however the copy of application which has been provided to the interested parties doesn't include any data relating to Saudi Arabia hence the present investigation must be terminated.
  - c. The application used by the Authority for the initiation of the investigation is a piece of document / evidence relevant for the interested parties and the interested parties must have access to all the information used by the authority to initiate the anti-dumping duty investigation. In the present investigation, Article 6.4 has been violated so it must be terminated.
  - d. The application for initiation in the present investigation has been filed subsequent to the initiation based on the information published in the initiation notice.
  - e. The interested parties should have been served with the application for the initiation of the investigation because:
    - i. They have a right to comment on the initiation of the investigation. Also, Rule 5(3) prohibits DA to initiate the investigation unless conditions in (a) and (b) are met.
    - ii. Imports from China from April 2015 to June 2015 are 10,584 MT and if the imports for the POI includes the imports from April 2015 to June 2015, then imports from April 2014 to March 2015 for the POI was only 9,720 MT coupled with the fact that there was no import in two consecutive previous years and negligible quantity in 2011-2012. Similar is the case from Iran where import quantity during POI was less than imports from the previous year. So the initiation failed to satisfy Rule 5.
    - iii. No certificate of correctness has been filed by the domestic industry for the data in the application which has been filed subsequent to the initiation of the investigation. The total of CIF value of the imports in Rs.Lacs for the subject countries is not equal to the sum of CIF value of imports from each country which converted an insignificant price undercutting into a significant one.
    - iv. The data of the production for Nirma may be only for the POI because the capacity shown is also for and the total production of Applicant domestic producers doesn't tally with the figure in injury statement.
    - v. Domestic industry cannot be permitted to submit the correct information only in the CV of the application.
    - vi. The Landed price from Saudi Arabia is not significantly higher than that from Qatar and China during the revised POI. Also the application was restricted to the period upto March 2015 which allowed the Authority to initiate investigation against Qatar and China. The new application doesn't contain information to enable the domestic industry to establish that injury margin from other countries was positive.
    - vii. Domestic industry may have provided the DGCI&S T/T import data only with the earlier application and the same may be filed in printed form with the new application, so no soft copy has been made available.
    - viii. The Authority didn't examine the data of the output of the domestic producers to determine the standing for filing the application as the data for POI and Injury period was not made available on record at the time of initiation of the investigation.
  - f. Saudi Arabia is excluded from the scope of the subject countries without any basis:
    - i. Imports from Saudi Arabia are almost double the imports from Iran and more than three times the imports from China during the POI;
    - ii. Imports from Saudi Arabia during the POI came into India at a price comparable to the subject countries; and



- iii. Imports from Saudi Arabia during the most recent period (April, 2015 to June, 2015) came into India at a price lower than all the subject countries. There is no sanction in either Indian law or WTO law to consider a country as “subject country” based on whether the imports are effected in each quarter or the month of the POI.
- g. Authority held a public hearing in the present investigation despite there being contradictory statements made in the petition regarding production of petitioners which did not provide a fair opportunity to the exporters to meaningfully comment on the information provided.
- h. The interested parties don’t have access to the alleged support letter by IOCL.

### **Views of the Domestic Industry**

23. The domestic industry have made following miscellaneous submissions:

- i. Domestic industry provided copies of non-confidential version of petition immediately after initiation. However, the Designated Authority considered it appropriate to circulate the updated petition. On being informed about requirement of filing data for the POI chosen by the authority, domestic industry consolidated all relevant information for the POI chosen by the authority and all relevant information for the POI chosen by the Authority.
- ii. Since the Authority has granted 40 days time to the interested parties to defend their interests after issuance of letter seeking information, no prejudice can be claimed because of alleged delay in issuance of questionnaire and providing a copy of the petition. It is not a situation that Authority has not given 40 days time from the date of issuance of letter. Thus, as far as right to defence is concerned, authority has provided sufficient opportunity to the interested parties.
- iii. The Authority had given 90 days to interested parties from date of initiation for filing questionnaire response and submissions. Even if it is admitted that the parties did not have access to the petition until 37 days from initiation, in any case, parties had 53 days time available to them to file questionnaire response and make submissions after the petition was made available to the parties. Thus, the Designated Authority effectively gave 53 days to the parties when the rule provides only for 30 days and 7 days are provided for transmission of documents. Thus, as against 37 days provided under the rules and the agreement, the Designated Authority in fact provided 53 days to the interested parties after the petition copy was made available to the interested parties.
- iv. In WTO Panel Grey Portland Cement from Mexico, the Panel also analysed whether violations nullified or impaired the benefits accruing to a Member Country under the AD Agreement. In the present case, no prejudice has been caused to the interested parties as 40 days time period has been granted to the interested parties to defend their interest.
- v. The producers in Qatar have been giving post invoicing discounts. The goods are invoiced at a higher price and subsequently the exporters give discounts to the importers.
- vi. With regard to exclusion of Saudi Arabia from the investigation, although the petitioners filed the petition in respect of Saudi Arabia, the Designated Authority is justified in excluding it on the basis of negative injury margin, since India follows lesser duty rule and injury margin cannot improve during the course of investigation. Imports from subject countries are coming at lower rate than that of imports from Saudi Arabia. IOCL had submitted its letter directly to the Designated Authority which it may forward to the interested parties.
- vii. As regards conducting public hearing despite contradictory statements, the petitioners provided correct information regarding the production of petitioners in a letter dated 2<sup>nd</sup> June, 2016 filed with the DGAD, well before the public hearing was held.

IOCL had submitted its letter directly to the Designated Authority which it may forward to the interested parties.

### **Examination by the Authority**

24. The aforesaid miscellaneous submissions made by the interested parties have been analysed as follows:

- i. With regard to the argument that the petition has been circulated after 37 days delay from the date of initiation, it is clarified that the Authority considered it appropriate to call updated information from the petitioners for the POI chosen for the case and thereafter issue the Questionnaire along with the petition with updated POI data to the interested parties. The Authority gave 40 days from the date of circulation of the petition to all interested parties to file Questionnaire response and provide any other information in order to defend their interests. Thereafter, some interested parties sought additional time for filing Questionnaire response and making their submissions, which were also liberally considered in the present case. Further, some interested parties made their legal submissions for the first time at the stage of oral hearing, which was held 184 days after initiation of investigation. The Authority however permitted these interested parties to present their views and information given by these interested parties and has also been taken into consideration in the investigation. The Authority has ensured that all interested parties get as much opportunity as they wish to defend their interests and has not allowed any interested party to suffer on the grounds that the submissions by them are belated. In fact, the Authority notes that preliminary issues such as alleged difference in molecular weight of the imported and domestic product were raised for the first time significantly after initiation of investigation and yet the same have been taken into account and addressed by the Authority.
- ii. With regard to the argument that the Authority has not provided the petition that was considered for initiating the investigation, the Authority notes that in order to afford a proper and meaningful chance to the interested parties to respond to the investigation with comments on the submissions made by the domestic industry on the POI being considered by the Authority, the Authority made available to interested parties both the petition relied upon by the authority for initiation of investigation and information for the updated period decided by the authority. The effort was to give effective opportunity to the interested parties and seek comments on the period and data that is relevant for the purpose of initiation and thereafter determination under this investigation. A copy of the petition relied upon by the authority for initiation was in fact made available to the interested parties and a number of interested parties collected and have commented on the same.
- iii. With regard to the argument that imports from Iran and China appears to be quite low for the POI originally considered by the domestic industry, the Authority notes that only after satisfaction of share of imports being beyond de minimis, the present investigation was initiated. In fact, none of the interested parties have contended that the share of imports from these countries was de-minimis.
- iv. As regards the argument that certification from the domestic industry has not been submitted and has led to incorrect figures, the Authority notes that the information provided by the domestic industry was Prima Facie verified and then adopted for the purpose of initiation.
- v. As regards the argument that standing and scope of domestic industry has not been analysed for the POI, the Authority notes that the determination of standing at the time of initiation is based on information contained in the petition for the period for which data is available in the petition. In the instant case, it was seen that the domestic industry had requisite standing for the POI considered by the domestic industry in their petition. Even in cases where POI is kept the same as proposed by the domestic industry, the fact of standing is open for further verification and scrutiny. There is no material on record which shows that the petitioners prima facie might not have standing in the POI chosen by the authority. In case the petitioners loose standing in the POI chosen by the authority, the investigation would have to be terminated under Rule 14. The argument of the interested party tantamount to contending that the authority cannot chose a investigation period different from what has been suggested by the petitioners. There is however no obligation on the authority to consider only such period as the petitioners have proposed. The POI for the detailed investigation can be much different from the POI proposed in the petition. As noted in the relevant part of this finding, the domestic industry considered in this investigation has the requisite standing and fulfils the requirements of Rule 2 (b) in the proposed and adopted POI.
- vi. As regards exclusion of Saudi Arabia, the Authority had examined imports from Saudi Arabia at the stage of initiation and found that the injury margin in case of imports from Saudi Arabia was negative. Therefore Saudi Arabia was not considered as a subject country in the present investigation. In fact, there was a sufficient difference in the import price from China, Qatar and Saudi Arabia. Further during the investigation, the Authority confirms the aforesaid that injury margin of imports from Saudi Arabia is negative.

**G. Normal Value (NV), Export Price(EP) and Dumping Margin(DM)**

**Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

25. The exporters, importers, consumers and other interested parties have raised following issues with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- a. The normal value computed for Iran and Qatar is in contravention of Section 9A(1c) the Act, Annexure I of the AD Rules and Article 2 of the WTO ADA because it has been constructed by utilizing certain cost components relating to Indian domestic producers and certain cost components relating to other countries. The non-availability of information can't be cited as a reason for constructing the normal value based on methodologies that are inconsistent with the applicable legal provisions.
- b. N-paraffin is produced by the manufacturers in Iran and Qatar from kerosene rather than purchased for manufacturing LAB. So, the use of import prices of N-paraffin for constructing the normal value for Iran and Qatar is erroneous.
- c. The construction of normal value for China is also erroneous as it has been done based on the last option without exhausting the first 2 options of paragraph 7 of Annexure I of AD Rules.
- d. No evidence has been provided by the domestic industry for the adjustment made to arrive at the Export Price.
- e. The dumping margin determined by the Petitioners based on a flawed normal value and a lowered export price has artificially skewed the dumping margin upwards. The alleged dumping margin determined for the subject countries have been negative and nil during certain quarters in the POI. So, even with a skewed dumping margin imports from the subject countries have not been dumped in India.

f. M/s ELP Advocates representing M/s SEEF, M/s Muntajat and M/s Renish have through letter dated 28<sup>th</sup> December, 2016 submitted that considering the third country sales to countries like South Africa for normal value may not be appropriate on account of different customer profile, level of trade etc.

### **Views of the Domestic Industry**

26. The following are the submissions made by the petitioners in respect of normal value.
- i. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
  - ii. Market economy status cannot be granted unless following conditions are fulfilled.
    - a. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity
    - b. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values
    - c. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards
    - d. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied
    - e. The onus/obligations to establish market economy status is onto responding Chinese exporters and not onto the Designated Authority
    - f. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim
    - g. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
27. Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
28. Normal Value in China has been determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted.
29. For determining the normal value for Iran and Qatar, efforts were made to get an evidence of actual transaction price of sale of the LAB in the domestic market of subject countries and prices at which the material is being exported from subject country to other countries. However, petitioners have not been able to get adequate and accurate evidence of the transaction prices either for the domestic market of the subject country or for exports to other countries. So the petitioners have constructed the normal value for subject countries on the basis of estimates of cost of production in subject countries.
30. As regards the evidence for export price adjustments, the petitioners provided evidence to the extent available and have made most conservative estimates wherever evidence is not available.
31. As regards N-paraffin as well, the petitioners have used the best information available. Since responses have been filed from exporters from the subject countries, the Authority is likely to consider them for determining normal value.

32. As regards utilizing the first two methods for normal value of China, it is submitted that firstly the relevant information is not publically available and secondly the petitioners have not been able to procure such information from a producer in a market economy third country.

33. The normal value and export price used for determining the dumping margin have been calculated as per the rules laid down in this regard. The dumping margin so determined, is not only more than de-minimis, but is also significant.

### **Examination by the Authority**

#### **Methodology for Dumping Margin evaluation – China**

The Authority notes that under section 9(A)(1)(c), normal value in relation to an article means:

*"The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-*

*(a) Comparable representative price of the like article when exported from exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

34. The Authority further notes that as per Paragraph 8 of the Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy needs to be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the criterias specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China were required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider according MET status to them.

35. The Authority sent questionnaires to the known exporters from China advising them to provide information in the form and manner prescribed, in the prescribed questionnaire and also as in para (35) above. However, only M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. provided response and none of the other producers/exporters from China have filed questionnaires' responses. M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd has also not claimed Market economy treatment.

Since none of the Chinese companies have claimed market economy treatment, the Designated Authority has not determined the aspect of market economy and has adopted the consistent methodology of evaluating Normal Value, on the basis of the best available information as per Rule 6 (8).

The Authority notes that M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Limited, producer, has exported goods in three transactions through two related entities viz M/s Sharpinvest and M/s Hotung Chemical Corp. Limited a quantity of \*\*\* MT and also approximately \*\*\* MT directly to two end users. M/s Sharpinvest and M/s Hotung Chemical Corp. Limited have filed response to questionnaire. It has also sold \*\*\* MT to an un-related trader, Dino-wik who has not cooperated. The Authority has undertaken analysis for the POI limiting to the data provided by the producer on its sales through related entities and directly to India and as for the other channel where the trader has not participated, analysis is not feasible. Therefore individual Dumping Margin determination for the cooperating producer is limited to its cooperating channels of exports, and the non responding export channel is treated as part of the residual category. The dumping margin evaluation is undertaken for the entire POI on a weighted average basis

### **Normal value in China**

As none of the producer/exporter from China have responded regarding normal value, the Authority has constructed the normal value for all producers/exporters on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) by adopting cost of production in India with adjustments on account of international raw material prices, power costs as per Domestic Industry's data, normated conversion costs, SGA and a reasonable profit of \*\*\* % on the cost of production. The normal value comes to \*\*\* \$/MT for the POI.

**Export Price for all producers/exporters in China**

36. The Authority has determined export price of two channels of exports of M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Limited separately.

The exfactory export price of \*\*\* MT of exports by M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Limited through M/s. Sharpinvest and M/s. Hotung Chemical Corp. Limited has been determined by considering adjustments on account of bank charges, credit cost, packing and custom broker charges to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*and \*\*\*US\$/MT respectively from the gross CIF invoice value, considered as \*\*\*US\$/MT (CIF). The exfactory export price comes to \*\*\*\$/MT.

The Ex-factory export price of M/s. Jiangsu Jintung Chemical Corp. Limited directly to end consumers in India is determined by considering adjustments on account of bank charges, credit cost, packing, custom broker charges, ocean freight and ocean insurance to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*US\$/MT respectively on the gross invoice value considered as \*\*\*US\$/MT (CIF). The landed values of two channels have been computed by applying applicable basic customs duty and cess on the assessable value which is considered as CIF import price plus \*\*\* % landing charges. Transactions on FOB/CFR have been converted to CIF by adding appropriate expenses on insurance/ocean freight as applicable. For the non cooperating producer/exporter, highest dumping margin and injury margin are adopted from the margins of cooperating channels.

**Dumping margin for Iran and Qatar**

37. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to questionnaire was filed by the following in respect of product under consideration originating in Qatar. However, none of the producer/exporter from Iran co-operated in this investigation by filing Questionnaires' responses.

- i. M/s. SEEF Limited, Qatar. (Producer)
- ii. M/s. Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C., Qatar (Exporter)
- iii. M/s. Renish Petrochem FZE

**Dumping Margin Determination for Qatar**

In view of questionnaire response from the producer and exporter in Qatar, normal value and dumping margin in case of responding producer & exporters have been determined on the basis of questionnaire response filed by the producer and exporter from Qatar. The dumping margin has been determined separately for 2 channels viz through Muntajat to India and through Muntajat and Renish to India. The Authority keeping in view of submission of various interested parties on dumping evaluation aspects in respect of SEEF, Qatar has considered the normal value computed on the cost of production for the POI along with SGA and normal profits as per AD Rules. For the non responding channel i.e. M/s West Ford, the dumping and injury margin is considered as per methodology adopted for non-cooperating producer/exporter i.e. considering highest dumping margin and injury margin during the POI on the basis of evaluation results for cooperating channels.

M/s. SEEF Limited, the producer and its associated exporter i.e. M/s. Qatar Chemicals and Petrochemical Marketing and Distribution Co. (Muntajat) Q.J.S.C. filed Questionnaire Response. The exporter and producer have an agreement on grant of exclusive selling rights to M/s Qatar Chemicals and Petrochemical Marketing and Distribution Co. (Muntajat) Q.J.S.C., the exporter, as per an agreed marketing fee formula for sales of all Quantity of subject goods produced by M/s. SEEF Ltd. to all destinations viz domestic market, India and countries other than India. During POI, the exporter sold \*\*\* MT of subject goods to India and \*\*\* MT to countries other than India with no sales in their domestic market. The exporter has further exported to India through traders outside India and also directly to importing entities in India who are also traders. The response besides M/s. Qatar Chemicals and Petrochemical Marketing and Distribution Co. (Muntajat) Q.J.S.C. has also been filed by M/s. Renish Petrochem FZE trader in UAE. Out of \*\*\* MT sales to India in POI. M/s Qatar Chemicals and Petrochemical Marketing and Distribution Co. (Muntajat) Q.J.S.C. exported \*\*\* MT to M/s. Ardor group (3 importers) in India and \*\*\*MT through M/s. Renish Petrochem FZE.

The producer, 'M/s. SEEF Limited' has also filed response stating the net proceeds received by it from M/s. Muntajat and the Cost of Production (COP) of subject goods as per Questionnaire indicating claim of same cost of production for the PUC being sold to all destinations. For determining the COP/NV for Seef, the per unit cost of the product under consideration has been determined by considering various cost elements as verified and after adjusting by product realisation and adding actual profit during POI. For determining per unit cost of different elements, inventory adjustment, Administration and selling and by product realisation have been divided by Sales Quantity while the other cost elements have been divided by production quantity. The normal value comes to \*\*\*US\$/MT including \*\*\* % profit on cost of production.



**Export Price - Qatar**

Adjustments considered on CFR price during POI are on account of Discounts, Freight, Credit Cost, Bank Charges, Custom Clearance Fee, Shifting Charges, Additional War Risk, interest charges, Surveyor Charges, and Marketing fee to an extent of \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, and \*\*\*/MT respectively (on a weighted average basis) to determine Ex-factory Export Price in POI to India for exports by other channel i.e. Muntajat to India. In case of exports by Muntajat and M/s. Renish the adjustments considered to determine Ex-factory export price in \$/MT are Freight (\*\*); Custom clearance (\*\*); Surveyor Charges (\*\*); Marine Insurance (\*\*); Marketing Fee (\*\*); and Discounts (\*\*). The 'marketing fee' paid to M/s. Muntajat has also been adjusted to arrive of Ex-factory export price of M/s. SEEF Limited. As regards adjustment on higher molecular weight of PUC, no substantive evidence with quantification in cost or price was provided to consider this adjustment and is therefore not being considered. As regards the adjustment claimed on level of trade, the exporter provided difference in price to traders and users in different quarters of POI but the range and direction of price variation does not suggest any consistent trend for consideration of any such difference especially when quantity discounts are being granted by the exporter as a matter of its considered pricing policy to all its customers. Therefore the Authority has not considered this adjustment on export price. The Ex-factory export price for exports through Muntajat and that through Muntajat and Renish comes to \*\*\*/MT and \*\*\*/MT respectively.

**IRAN****38. Normal value in case of Iran**

As none of the producers/exporters from Iran have responded, the Authority has constructed the normal value for all producers/exporters on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) by adopting cost of production in India with adjustments on account of international raw material prices, power costs as per Domestic Industry's data, normated conversion costs, SGA and a reasonable profit of \*\*\* % on the cost of production. The normal value comes to \*\*\*/MT for the POI.

**Export Price**

As none of the producers/exporters have cooperated, the Authority has adopted the DGCIS's import data for determining the CIF price. To evaluate the exfactory export price, the Authority has considered adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges and port expenses to an extent \*\*\* US\$/MT, \*\*\*% of CIF (\*\*\*/US\$/MT), for all 3 adjustments i.e. commission, bank charges and port expenses is \*\*\* % of FOB (\*\*\*/US \$/MT) respectively. To determine the landed value of imports, basic customs duty and cess have been applied on assessable value considered as CIF with \*\*\* % landing charges. The CIF, exfactory export price and landed value are evaluated as \*\*\*/US\$/MT, \*\*\*/US\$/MT, \*\*\*/US\$/MT respectively.

**Dumping Margin**

39. The Ex-factory export price to India has been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from subject countries have been determined as provided in the table below.

40. It is seen that the dumping margins are significant and more than the limits prescribed under the Rules in respect of exports made from each of the subject countries.

**Dumping Margin**

A.

		Qatar		
S. No.	Producer	Exporter	Dumping Margin \$/MT	Dumping Margin % (Range)
i.	M/s. SEEF Limited	M/s Muntajat	***	0 - 10
ii.	M/s. SEEF Limited	M/s Muntajat and M/s Renish Petrochem FZE (Trader)	***	30 - 40
iii.	M/s. SEEF	Weighted average i and ii above	***	0-5
iv.	Any	Any	***	30 - 40

**B.**

		China PR		
S. No.	Producer	Exporter	Dumping Margin\$/MT	Dumping Margin % (Range)
i.	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	M/s Hotung Chemical Corp. and M/s Sharpinvest	***	10 - 20
ii.	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	***	20 - 30
iii.	Any other than above (i) and (ii)	Any other than above (i) and (ii)	***	20 - 30

**C.**

		Iran		
S. No.	Producer	Exporter	Dumping Margin \$/MT	Dumping Margin % (Range)
i.	Any	Any	***	10 - 20

**H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

41. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure- II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

42. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s. Tamilnadu Petroproducts Ltd and M/s. Nirma Ltd on behalf of the domestic producers of the product concerned and was supported by IOCL and Reliance Industries Ltd. However later at the time of initiation, the Authority considered applicability i.e. M/s Nirma Ltd, M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd as Domestic Industry. However during the course of investigation M/s. Reliance Industries Ltd. who has initially supported the petition provided data which was verified and at the stage of final determination all 3 producers i.e. M/s. Nirma Ltd, M/s. Tamilnadu Petroproducts Ltd and M/s. Reliance Industries Ltd. are considered as Domestic Industry. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the domestic industry as defined earlier has been examined.

**Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

43. The exporters, importers, consumers and other interested parties have raised following issues with regard to the injury to the domestic industry:

- The trends of sales and market share of the petitioners is exactly opposite from that of the other Indian producers.
- The analysis of the relevant economic factors and indices like (a) stock volume (b) No. of employees (c) wages (d) production (e) domestic sales (f) market share (g) profitability and (h) return on capital shows that domestic industry did not suffer any injury.
- The rate of goods from China PR has increased from INR / MT 94632 to INR / MT 96381 in the injury period. The assessable value has also increased from INR/MT 95578 to INR / MT 97344.
- There is lack of causal link because the injury to the domestic industry, if any, the same may be attributed to other factors as admitted by TNPL in its 30th Annual Report for 2014-15.

- e. Performance has not improved in terms of production, sales, capacity utilization, productivity, wages and inventory. Moreover the performance of the two petitioners is very different in that TNPL has outperformed Nirma.
- f. The volume of imports from subject countries has been alleged to have increased by 26% while the sales of the petitioners have decreased by 8% over the injury period. However, volume of imports from other countries has risen substantially by 197%.
- g. There is an undue dropping of prices in the range of 10% below the prices of imports from subject countries and other countries by the petitioners.
- h. The Saudi Arabia imports have had greater impact in terms of both volumes and prices.
- i. The other economic factors such as volume of sales, market share and production improved during POI. The closing stock reduced notable and the wages increased significantly. Productivity per day and per employee also enhanced over the POI. During 2012-13 and 2013-14 the decline in subject country imports were not alleged to be sold at dumped prices, the sales and production of the petitioners were decreasing significantly and the market share remained stable while the inventory increased significantly.
- j. In 2012-13 and 2013-14 when the prices of imports were increasing, the domestic prices of the petitioners were also increasing.
- k. TNPL cannot suffer injury from imports of the subject goods from Qatar because TNPL is established in the South East of India while the Exporter only sells to the North West.
- l. Nirma is a detergent manufacturer that has a backward integrated plant to produce its own LAB and therefore does not directly compete with subject imports from Qatar. Nirma find it difficult to sell its LAB to direct competitors and its market share has deteriorated due to shifting of focus on non-detergent and non-LAB based industries.
- m. The petitioners are not integrated and therefore their costs are not competitive. TNPL uses old technology as reported in its 2014-15 Annual Report.
- n. Due to high kerosene costs and feedstock quality issues, as reported in TNPL's 2014-15 Annual report, the cost of production of LAB in India has been relatively higher than the international standards.
- o. The Petitioners started suffering losses because of the fall in crude oil prices and cash flow issues as reported by TNPL in its Annual Report for 2014-15.
- p. Sales of other domestic producers are nearly twice the volumes of sales of the Petitioners. Also, the sales of the other domestic producers have been steadily increasing through the course of the injury period and the POI. While the sales the domestic industries declined in 2013-14 as compared to the previous year, the sales of the other domestic producers increased in the same period.
- q. Both RIL and IOCL are backward integrated unlike the petitioners, as a result of which the petitioner companies have significant disadvantages as compared to RIL and IOCL. As the domestic industry relies on RIL and IOCL for supply of feedstock, the domestic industry is at a significant disadvantage.
- r. The trend in the import volumes from the subject countries has been the same as the trend in the sales of the domestic industry. Also, during 2013-14 when imports from the subject countries declined, so did the sales of the domestic industry. The sales of the other domestic producers increased. So, if at all the domestic industry is being negatively impacted, the same is being caused by sales of the other domestic producers.
- s. Certain domestic producers have faced electricity issues which resulted in increase in its fixed costs and production costs of LAB for the domestic industry is higher as compared to international standards due to higher raw material prices as reported in the TNPL Annual report for 2014-15.
- t. TNPL has a constraint in respect to converting kerosene to normal paraffin which is a source of injury, as reported in the TNPL Annual Report 2014-15.
- u. The internal transfers of Nirma Ltd have decreased during last four years which must be examined into the injury assessment.
- v. Imports from the subject countries are at nearly the same price as imports from Saudi Arabia. If the reason for terminating the investigation against imports of Saudi Arabia is based on the negative injury margin then the imports from the subject countries cannot be found to have a negative price effect on the sales of the domestic industry. The prices from China PR in the POI were only 2% lower than the prices from Saudi Arabia. And the import prices from Iran and Qatar were only 4% and 2% lower than the prices from Saudi Arabia respectively.
- w. There is no decline in the economic parameters of the domestic industry like production, capacity utilization, sales volume, sales value and inventory.
- x. The difference between Farabi price and China price is only 2% as per the petitioners' data. The Designated Authority has found negative margin in case of Farabi and the same should be applied in GOC's case.
- y. GOC has started exporting to India only in 2014-15 and therefore there cannot be any injury on account of GOC.
- z. Chinese exports to India in POI is meagre 1.48% of the Indian demand which cannot be termed as dumping.
- aa. As per Indian import data, average import price of Chinese product is US\$ 1540 per tonne during May 2014 to Jan 2016. From a high of USD 1800 in May 2014 to low of 1200 in Jan 2016. Average export price of Indian manufacturer in that period is USD 1380 that is 10% lower than at the price being imported. From a



- high of USD 1580 in May 2014 to low of USD 900 in Jan 2016. Indian LAB producers are exporting their product at lesser price than the price at which LAB is being imported into the country.
- bb. The decline in output, if any, was because, two middle-east based n-paraffin producers underwent maintenance in March and April 2015; technical issues at the plants or feedstock normal paraffin (n-paraffin) shortages; and continued increase in production from 2012-2015 as shown by Reliance data.
  - cc. IOCL is now producing at 120% of their capacity, it should be verified.
  - dd. Market share of domestic industry is 82%, whereas in their submission to DG Safeguard, market share in 2008-09 was 78.84%. That means the import market share has come down from 21.16% in 2008-09 whereas demand has gone up by 66% in last 5 years.
  - ee. As regards contention of the petitioners concerning decline in profits, the interested parties have contended as follows:
    - i. decline in profits, if any, would be on account of volatility, no secure supply of raw material to petitioners, maintenance shut down, low production due to normal paraffin shortage and price under cutting with other two leading domestic manufacturers.
    - ii. The lack of upstream integration to key raw materials may be reason for low profitability of petitioners.
    - iii. The selling price has declined internationally due to fall in crude oil price and subsequently raw material.
    - iv. Big manufacturers are selling most of their produce on formula based pricing so as it is shielded from import price.
  - ff. One petitioner's most of the production is for captive consumption. Further their exports are down by 75%.
  - gg. Another petitioner is exporting at lesser price than the price at which it is being imported, whenever they export.
  - hh. LAB imports are coming in India from China at International prices like they come into any other country of the world.
  - ii. China has sold only 20304 MT POI which is 3.5% of total India's demand.
  - jj. GOC has sold just 600 MT in Chennai port from April 2014 to June 2015 which is 0.5% domestic manufacturer TPL production capacity in South.
  - kk. Import at Chennai from all exporters is less than 5000 MT in a year which is 4% of TPL monthly production capacity. This in turn means 96% market is available for domestic producer.
  - ll. GOC has not sold any quantity in west coast of India except for 2 months in POI and even till date.
  - mm. LAB export has also started from Chennai port resulting in domestic shortage in South as there is only one manufacturer there.
  - nn. There is no manufacturer at East coast. Logistic cost is high from west coast to east coast. Most of the supplies from one of the countries in year 2015 have been to East Coast, i.e., Kolkata of meagre 3600 MT for PIO.
  - oo. GOC's all exports to India have been done at par or at higher price as compare to China domestic prices.
  - pp. The customs duty of 7.5% is sufficient protection for the domestic industry.
  - qq. There is no significant increased import causing material serious injury.
  - rr. The imports meant to manufacture final products destined for export should be excluded. If done so, then share of import becomes significantly lower. Beside there have been so many imports on behalf of Indian HUL meant for their Bangladesh and Nepal factory so those are also for exports.
  - ss. The companies seeking anti dumping duty protection are financially strong and large conglomerates.
  - tt. Domestic sales are being substituted by Exports. Chennai has also started exporting.
  - uu. There is no causal link. Plant shut downs are not on account of imports. The injury if any is on account of crash in crude oil price and volatility in the price.
  - vv. There is huge shortage in India due to demand more than installed capacity.
  - ww. LAB market will expand globally at a compound annual growth rate of 4.3% during 2012-18 and consumption in India is expected to reach 5,95,000 MT by 2016-17 which far exceeds domestic production capacity. So there is enough space for domestic producer to grow.
  - xx. There is plenty of opportunity in international market for domestic industry; if they focus on exports, they can regain their lost ground.
  - yy. Any imposition of anti-dumping duty will impose hardship on users of LAB.
  - zz. Import has not caused any injury to LAB manufacturers as overall economy worldwide is in stress.
  - aaa. There has been an increase in demand over last 5 years by almost 66% but installed capacity has not increased. On the contrary, capacity has gone down by 60,000 MT. Also there has been increase in sales by domestic manufacturer by 50% as per their data in last 5 years. This is despite the fact that their export has fallen by 60% in 2006-07.
  - bbb. During 2013-14, there was a decline in imports, the sales of the domestic industry also declined during this same period. That means import is not the reasons for their loss.
  - ccc. The remaining inventories with the domestic industry are on account of substantial decline in the exports of the domestic industry.
  - ddd. The petitioner's data shows 93% capacity utilization and the Reliance data also shows increase in capacity utilization due to continuous increase in production.

- eee. The reduced return on investment is likely to affect the profit growth.
- fff. The imposition of anti-dumping duty is not in public interest since the demand supply gap is addressed by imports. The product under consideration is also used in production of key products such as detergents and pesticides and industries that cater to lower strata of society.

#### **Views of the Domestic Industry**

44. The following are the submissions made by the petitioners in respect of injury determination:
- a. There has been an increase in volume of imports from subject countries over the injury period with significant increase in the POI.
  - b. Imports from subject countries constitute almost 62% of share amongst total imports.
  - c. There has been a significant increase in imports over the period in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
  - d. The landed price of imports is below the selling prices of domestic industry resulting in significant price undercutting of the prices of the domestic industry in the market.
  - e. Landed price of Imports have remained below the level of cost of production throughout the injury period.
  - f. Both, cost of sales and selling price increased upto 2013-14 and then declined in the POI. However, decline in selling price is much below the level of cost of sales. Thus, imports have had significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market during the POI. Furthermore, even when selling price increased in the previous years, i.e 2012-13 and 2013-14, the same remained below the level of cost of sales resulting into losses.
  - g. The principal factor responsible for the domestic industry prices is the landed prices of the subject goods. Given lower import prices, the domestic industry is facing significant suppressing effects of the dumping in the domestic markets.
  - h. Production of domestic industry has declined drastically over the injury period. Production improved slightly in the POI as compared to the previous year; however, the same was still below levels achieved earlier and at the cost of significant financial losses.
  - i. Sales of the domestic industry declined till 2013-14 and have thereafter increased in the POI. However, sales still remains at lower level as compared to 2011-12 and 2012-13.
  - j. Despite demand for the product under consideration being more than capacity available in India, the capacity utilisation of the domestic industry has declined significantly. The capacity utilisation which was 81% in the base year declined to 64% in the POI.
  - k. Market share of the dumped imports has increased over the injury period, whereas the market share of the domestic industry declined over the injury period. Market share of other domestic producers increased till 2013-14, however declined thereafter in the POI.
  - l. Profits of the domestic industry declined sharply throughout the injury period.
  - m. Cash profit also declined over the injury period. Profit before interest also declined significantly over the period and is negative since 2012-13. Resultantly, return on investment has also remained negative in 2012-13.
  - n. The employment level of the domestic industry shows an increase over the injury period. Wages have shown normal increases highlighting an increase in cost for labour. Further, productivity per day as well as per employee has declined in consonance with the decline in production.
  - o. The level of inventories increased upto 2013-14 and has declined in the proposed POI, however, remains significant.
  - p. In response to the submissions of opposing interested parties on existence of injury to the domestic industry and causal link, the domestic industry has made following submissions.
    - i. The allegation of opposite trend of sales and market share is factually incorrect. The market share of the domestic industry has declined whereas the market share of the other Indian producers remained stagnant over the injury period.
    - ii. With regard to argument pertaining to increase in rate of goods from China, it should be noted that there is positive price undercutting i.e. the landed value of China PR is still below the net selling price of the domestic industry.
    - iii. With regard to admission of other factors causing injury in TNPL's annual report, it is to be noted that statements in Annual report are not with regard to deterioration in performance of the domestic industry over the injury period. The statements in the annual report do not provide complete picture with regard to deterioration in performance over the injury period of the product concerned in the anti-dumping case.
    - iv. Contrary to allegations, both the petitioners were suffering losses.

- v. As regards the increase in volume of imports from other countries it is noted that the domestic industry is facing volume injury as well price injury. The volume and price injury faced by the domestic industry is only on account of the dumped imports from the subject countries.
- vi. The allegedly undue decrease in price is denied to be factually incorrect. The domestic industry has sold at prices higher than that of subject countries as reflected from the positive price undercutting.
- vii. As regards the argument of declining subject country imports during 2012-13 and 2013-14, the performance of domestic industry declined on account of many parameters and it is not necessary to show that each listed parameter is declining. Domestic industry has suffered losses on account of dumped imports and therefore seeking relief under Anti-Dumping Rules.
- viii. As regards the price increase trend in 2012-13 and 2013-14 is concerned the price of domestic industry could not increase in proportion to the increase in the landed value of imports. While the landed value has increased by 121 points as compared to 2011-12, the selling price has increased by only 113 points during the same period.
- ix. As regards the argument of exporter selling product under consideration only to the North and West India, it is submitted that injury has to be seen for the domestic industry as a whole and not for the constituents separately.
- x. As regards captive consumption of LAB by Nirma, it is submitted that substantial portion of its production is meant for merchant market. Further Nirma is forced to shift its focus to non-detergent and non-LAB based industries because of the unviable price of LAB due to dumped subject imports.
- xi. As regards the costs and integration of petitioners, TNPL uses comparable technology and it is not required under the anti-dumping law that all the producers of subject goods should be integrated in order to seek protection.
- xii. As regards the issue of higher cost of kerosene and feedstock quality issues, it is submitted that the cost of production of the domestic industry is to be seen as per the cost and price prevailing in India and not on the basis of international price. The impact of feedstock is on production and not on profits. In fact, if the domestic industry produced lower volume, it had lower pressure to sell the product and if the domestic industry has lower volumes, it had lower pressure for sales. Therefore, the alleged factor should not have resulted in steep decline in profits to such an extent where domestic industry suffered significant financial losses from a situation of profits.
- xiii. The domestic industry started suffering losses only on account of steep fall in the price of LAB due to the dumped imports of the product concerned from the subject countries, and has not suffered injury due to fall in crude oil prices or cash flow issues.
- xiv. As regards the argument that sales of domestic producers have increased substantially, it is submitted that while the market share of the domestic industry has declined, the market share of other domestic producers remained stagnant, therefore it is not correct to state that domestic industry has not suffered injury on account of dumped import.
- xv. As regards backward integration of RIL and IOCL and its impact on feedstock supply, it is submitted that domestic industry never had any problem in procurement of raw material. The injury to the domestic industry is solely on account of the dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- xvi. The allegation with respect to trend of import volumes and its comparison with sales trend of domestic industry is factually incorrect. While the domestic industry sales have declined, the imports from the subject countries have increased.
- xvii. As regards the argument based on TNPL annual reports pertaining to electricity issues and other issues being faced by domestic industry it is reiterated that public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to the injury suffered by the domestic industry. The statements in the annual report are not with regard to deterioration in performance of the domestic industry over the injury period. The Authority is concerned with performance of the domestic industry over the injury period. The Annual Reports are however focused only on the period under consideration. Also, the Authority is concerned about domestic operations, whereas the Annual Reports are concerned about company's overall operations. Thus,

- the statements in the annual report do not provide complete picture with regard to deterioration in performance over the injury period of the product concerned in the anti-dumping case. Further, the cost of production of the domestic industry is to be seen as per the cost and price prevailing in India and not on the basis of international price.
- xviii. As regards the issue of internal transfers of Nirma Ltd, what is more relevant is the domestic sales of the domestic industry and not its captive transfer. The injury needs to be determined for domestic market/sale. It may be seen from the data provided by domestic industry that the domestic industry has suffered material injury on the domestic sale segment.
  - xix. As regards injury on account of GOC, it is to be seen whether there were imports beyond de-minimis limits in the POI, whether the same were at dumped price, and whether the same were causing injury to the domestic industry. There is no legal requirement that imports from each of the subject countries must have been occurring throughout the investigation period.
  - xx. It is factually incorrect that the Chinese export to India is only 1.48% of the Indian demand. The correct figure is more than more than 3%. Further, this argument is irrelevant as the import from China is 10% of the total imports as against the de-minimus limit of 3%.
  - xxi. The argument with regard to exports by Indian LAB producers is irrelevant for the present investigation as the domestic industry has exported very negligible volume of the subject good and in any case, injury if any, on account of such exports has already been segregated.
  - xxii. The arguments to show reasons for decline in output are baseless. The decline in output is due to cheap import of LAB and not the shortage of feedstock. The domestic industry has consumed imported n-paraffin only 14% of its total requirement. Further the petitioners have not claimed volume injury. Petitioners have claimed adverse price effect of dumped imports of the domestic industry.
  - xxiii. As regards post POI performance of IOCL, post POI performance of other domestic producer is irrelevant for the present investigation as the domestic industry is seeking protection from the injurious effect of dumped imports during the POI from the subject countries.
  - xxiv. It is factually incorrect that the market share of domestic industry is 82% and the market share of imports from subject country has come down. On the contrary, the market share of imports from subject country has increased over the injury period and the market share of the domestic industry has declined from 35% to 26% during the injury period.
  - xxv. Reduced profit is on account of lower selling price due to dumped imports. The injury to the domestic industry is required to be determined in respect of PUC. Injury is not required to be determined in respect of producer and all its operations. In fact, it is very well understood that in case the company were backward integrated or forward integrated, the authority shall determine injury to the domestic industry only in respect of production and sale of PUC.
  - xxvi. As regard decline in selling price internationally, if the selling prices have declined in the domestic and export market to the same extent, there should be no dumping. However, if the product has exported at dumped price, it implies that the product was being sold in the domestic market at the price higher than the export price.
  - xxvii. As regards captive consumption, the information on record clearly demonstrates that the significant proportion of production is meant for merchant market.
  - xxviii. As regards exports at low price, petitioners submit that the same is result of dumping in the Indian market. Further, the petitioners are facing low price exports being made by subject countries to other markets where petitioners are exporting. Evidently, the petitioner will get a low price in exports.
  - xxix. The import price from China is at dumped prices. The argument that the imports are coming at International prices are not relevant. What is more relevant is the fact that the imports are coming at dumped prices.
  - xxx. As regards various arguments of GOC pertaining to Geographical locations in India and its impact of the injury it is submitted that the injury has to be seen for the domestic industry as a whole and not for its constituents separately. Further as regards export of LAB, the domestic industry has exported only a small quantity of LAB during POI.
  - xxxi. The imports from GOC whether done at par or at higher price as compared to China domestic prices is not relevant as China is an NME country and the domestic price is not relevant for normal

- value determination. Based on the normal value computed by domestic industry, the dumping margin for China PR is significant.
- xxxii. The submission with regard to customs duty of 7.5% has no relevance.
  - xxxiii. There were significant imports at dumped prices in POI causing at material injury to domestic industry.
  - xxxiv. As regards argument concerning imports meant for products destined for exports, there have been plethora of cases wherein the Authority has included imports under advance license for examination of dumping and injury. Authority has in other cases also held that the fact that the imports were made under advance licence does not mean that the same does not cause injury to the domestic industry.
  - xxxv. As regards arguments concerning financial strength of the petitioner companies, it is submitted that the domestic industry is suffering financial losses since 2012-13 and the same has intensified in the POI. The deterioration is significant and material.
  - xxxvi. As regards exports by domestic industry, they are very insignificant during the POI.
  - xxxvii. As regards the demand supply argument, it is submitted that exporters from the subject countries cannot export at dumped prices causing injury to the domestic industry on the plea that there is a demand supply gap. Further, during POI, the installed capacity of the producers in India is more than the demand of the subject goods. The domestic industry is having unutilised capacity due to the dumped imports from the subject countries.
  - xxxviii. As regards global expansion of LAB market, the domestic industry will manage to grow only when there would be imposition anti-dumping duty on the dumped imports of LAB from subject countries.
  - xxxix. The advice to domestic industry to focus on exports is misplaced as the domestic industry is not seeking any concession rather it is praying for a level playing field.
  - xl. The users of LAB will have more competitive sources of supply due to imposition of anti-dumping duty.
  - xli. As regards allegation of high capacity utilization, the petitioners have not claimed volume injury in the present case. Petitioners have claimed adverse effect of dumping on the price parameter of the domestic industry.
  - xlii. Assumption of reduced return on investment affecting profit growth established dumping causing injury to the domestic industry.

#### **Examination by the Authority**

45. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.

46. Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

47. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

*“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*

48. All parameters of injury need not show deterioration. While some parameter may show deterioration, some may show improvement. The Designated Authority must consider all injury parameters and thereafter conclude whether the domestic industry has suffered injury.

49. The landed value has been appropriately adjusted with discounts offered by M/s Muntajat as credit adjustments on export proceeds to them.

50. The Authority has examined the injury parameters taking into account facts and various submissions. The examination below addresses issues raised by the interested parties.

51. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules supra.

#### **Cumulative Assessment**

52. Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three per cent, the imports cumulatively accounts for more than seven per cent of the imports of like article, and;
- b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

53. In the present case,

- a) the margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed above;
- b) the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
- c) cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods produced and sold by the domestic industry in the Indian market. There is no submission made by any interested party disputing cumulative assessment in the present case.

54. In view of the above, the authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of imports.

#### **Assessment of Demand**

55. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

##### ***Demand including Captive consumption***

	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI- A	POI
Sales of DI	MT	2,72,963	2,76,097	2,68,849	2,77,987	3,47,483
Other producers	MT	***	***	***	***	***
Subject imports	MT	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
Other imports	MT	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
Demand/consumption	MT	***	***	***	***	***
Demand/consumption	Indexed	100	109	105	117	147

##### ***Demand Excluding Captive consumption***

	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI-A	POI
Sales of DI	MT	2,24,390	2,27,036	2,27,605	2,44,078	3,05,097
Other producers	MT	***	***	***	***	***
Subject imports	MT	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574

Other imports	MT	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
Demand/consumption	MT	***	***	***	***	***
Demand/consumption	Indexed	100	109	108	123	153

POI-A = (POI annualized)

56. It is seen that the demand shows rising trend whether captive consumption is included or excluded. Interested parties contended that injury to the domestic industry is due to decline in captive consumption. However, since demand excluding captive consumption has also increased, injury to the domestic industry cannot be attributed to decline in captive consumption.

#### **I. Volume Effects of Dumped Imports**

##### **Import volume and market share**

57. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the DGCIS's import data. The volume of imports of the subject goods from the subject countries are as under:

<b>Import</b>	<b>Units</b>	<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>POI –A</b>	<b>POI</b>
China	MT	514	-	-	16,227	20,283
Iran	MT	37,587	30,941	20,841	28,610	35,762
Qatar	MT	46,117	39,777	47,362	58,023	72,529
Subject Countries	MT	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
Others	MT	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
Total	MT	1,05,507	1,26,081	1,17,807	1,66,095	2,07,619

58. It is noted that imports from subject countries declined in 2013-14. However Imports increased significantly in the POI from subject countries.

59. Imports from subject countries declined in relation to production and consumption in India till 2013-14. Imports from subject countries increased significantly in POI in relation to production and consumption of the subject goods in the domestic market, as is seen from the table below.

<b>Particulars</b>	<b>Units</b>	<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>POI -A</b>
Share of Subject import in consumption inclusive of captive consumption	%	17.60	13.61	13.53	18.32
Share of import in consumption excluding captive consumption	%	19.59	15.03	14.74	19.50
Imports in relation to production	%	23.94	21.04	22.55	34.74

#### **J. Price effect of imports**

60. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of

the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

### **Price Undercutting**

61. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. The Authority has noted the argument of the domestic industry of significant fluctuation in raw material prices and has thus determined quarterly undercutting for the POI.

Price undercutting	China					
Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI-A	POI
Import	MT	514	-	-	16,227	20,283
Import value	Rs. Lakhs	486	-	-	15,638	19,547
CIF price	Rs./MT	94,632	-	-	96,370	96,370
Assessable value	Rs./MT	95,578	-	-	97,334	97,333
Custom duty amount	Rs./MT	7,168	-	-	7,300	7,300
Cess	Rs./MT	215	-	-	219	219
Landed value	Rs./MT	1,02,961	-	-	1,04,853	1,04,852
Selling price DI	Rs./MT	***	-	-	***	***
Price undercutting	Rs./MT	***	-	-	***	***
Price undercutting	Range	0-10	-	-	0-10	0-10

Price under cutting	Iran					
Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI-A	POI
Import	MT	37,587	30,941	20,841	28,610	35,762
Import value	Rs. Lakhs	32,626	30,897	22,461	26,838	33,547
CIF price	Rs./MT	86,801	99,859	1,07,772	93,806	93,806
Assessable value	Rs./MT	87,669	1,00,857	1,08,849	94,744	94,744
Custom duty amount	Rs./MT	6,575	7,564	8,164	7,106	7,106
Cess	Rs./MT	197	227	245	213	213
Landed value	Rs./MT	94,442	1,08,648	1,17,258	1,02,063	1,02,063
Selling price of DI	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price under cutting	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price under cutting	Range	0 to(-10)	0 to(-10)	0 to(-10)	0-10	0-10

Price under cutting	Qatar					
Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI-A	POI
Import	MT	46,117	39,777	47,362	58,023	72,529
Import value	Rs. Lakhs	42,096	40,756	52,385	56,213	70,266
CIF price	Rs./MT	91,281	1,02,462	1,10,606	96,880	96,880
Assessable value	Rs./MT	92,194	1,03,486	1,11,712	97,849	97,849
Custom duty amount	Rs./MT	6,915	7,761	8,378	7,339	7,339
Cess	Rs./MT	207	233	251	220	220
Landed value	Rs./MT	99,316	1,11,481	1,20,341	1,05,407	1,05,407
Selling price of DI	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0 to(-10)	0-10	0-10	0-10	0-10



62. It is seen that the landed price of the subject goods from each of the subject countries were below the selling price of the domestic industry during POI, showing price undercutting being caused by the dumped imports from subject countries.

### **Price Suppression / depression**

63. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	116	124	114
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	108	115	98
Landed Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	113	123	107

The selling price in POI has declined as compared to base year while cost of sales has increased.

64. The Authority notes that cost of sales and selling price increased upto 2013-14 and then declined in the POI. However, the decline in selling price over the period is far more than decline in cost of sales. In fact, whereas the selling price declined by Rs. \*\*\* pmt as compared to preceding year, the costs declined by Rs. \*\*\* as compared to previous year. Thus, imports have had significant suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry in the domestic market.

### **Price-underselling**

65. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries, as follows:

Price under selling (POI)		
Non-Injurious Price	US\$/MT	***
Selling price	US\$/MT	***

The selling price is below the NIP determined for POI. Price underselling is 5 – 15 %.

66. It is seen that the landed price of imports were below the non-injurious price of the domestic industry. The domestic industry has suffered significant price underselling during the investigation period on account of imports of the subject goods from the subject countries.

### **K. Economic parameters of the domestic industry**

67. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

#### **i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

68. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI -A	POI
Capacity	MT	4,12,400	4,12,400	4,12,400	4,12,400	5,15,500
Production of DI	MT	3,51,722	3,36,098	3,02,443	2,96,064	3,70,080
Capacity Utilization	%	85%	81%	73%	72%	72%
Sales of DI	MT	2,24,390	2,27,036	2,27,605	2,44,078	3,05,097
Captive consumption	MT	***	***	***	***	***
Export sales	MT	***	***	***	***	***
Total sales of DI	MT	3,45,092	3,23,109	3,09,374	3,07,264	3,84,080

69. It is noted from that

- capacity with the domestic industry have remained at the same levels;
- production of domestic industry declined significantly over the injury period.
- capacity utilisation of the domestic industry declined significantly over the injury period, when compared to base year.
- sales of the domestic industry increased over the injury period.

## ii. Market share in demand

70. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined as below:

### *Share in Demand including captive consumption*

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Domestic industry	%	57%	53%	53%	50%
Other producers	%	21%	23%	23%	21%
Subject imports	%	18%	14%	14%	18%
Other imports	%	4%	11%	10%	11%
Demand/consumption	%	100%	100%	100%	100%

### *Share in Demand excluding captive consumption*

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Domestic industry	%	52%	48%	49%	46%
Other producers	%	23%	25%	25%	22%
Subject imports	%	20%	15%	15%	19%
Other imports	%	5%	12%	11%	12%
Demand/consumption	%	100%	100%	100%	100%

71. Market Share of Domestic Industry has decreased from 52% in 2011-12 to 46% in POI. The market share of the subject countries declined upto 2013-14 and then increased in the POI, whereas the market share of the domestic industry declined upto 2013-14 and then increased in the POI. It is further noted that market share of other domestic producers increased till 2013-14 and declined thereafter in the POI. However as compared to base year Market share of other producers has risen.

## iii. Profits, returns on investment and cash profits

72. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI -A	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	116	124	114	114
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	108	115	98	98

Profit/loss	Rs./MT	***	***	***	(***)	(***)
Indexed	Trend	100	11	13	(101)	(101)
Total profit/loss	Rs.Lacs	***	***	***	(***)	(***)
Indexed	Trend	100	11	13	(110)	(137)
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	(***)	(***)
Indexed	Trend	100	79	52	63	78
PBIT-Domestic	Rs.Lacs	***	***	***	(***)	(***)
Indexed	Trend	100	28	26	(88)	(110)
ROI	%	***	***	***	(***)	(***)
Indexed	Range	35 - 45	5-15	5 -15	(30) to (40)	(30) to (40)

- whereas the cost of production and selling price increased till 2013-14, both declined in the POI. As imports were suppressing and depressing the domestic prices, the profitability of the domestic industry declined. The domestic industry also suffered financial losses in the POI.
- cash profit declined significantly over the period and became negative from base year;
- profit before interest declined significantly over the period and became negative in POI. Resultantly, the return on investment declined significantly over the injury period and became significantly negative in POI;
- Interested parties contended that the domestic industry suffered financial losses due to inter-se competition. The interested parties also contended that there is a demand-supply gap in the product under consideration and imports are inevitable. It is noted that the demand for the product under consideration during the POI was 561,442 MT. As against this, the capacity created by the Indian industry is 5,15,500 MT. Thus, there was an admitted demand-supply gap for the product in the Country. In a situation where the demand for the product under consideration in the country is higher than the combined capacities with the domestic industry, significant decline in profitability of the domestic industry to the extent that the domestic industry has suffered significant financial losses, negative cash flow and negative return on capital employed cannot be addressed by possible increasing inter-se competition amongst domestic producers. It is also noted in this regard that the capacities with the domestic producers have not increased over the injury period, whereas the demand for the product under consideration has shown 22% increase over the injury period. This should have in fact led to somewhat decline in competition but not increase in inter se competition.

#### iv. Inventories

73. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI -A
Opening stock	MT	***	***	***	***
Closing stock	MT	***	***	***	***
Average stock	MT	12,195	21,999	24,704	13,902

It is noted that the level of inventories with the domestic industry increased upto 2013-14 and has declined towards end of the POI.

#### v. Employment, Productivity and Wages

74. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI -A
Employment	No.	853	984	791	797
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	104	94	116
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	96	86	84
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	83	93	90

It is noted that the employment level with the domestic industry has decreased over the injury period. Wages paid have also increased. Further, productivity per day as well as per employee has declined.

**vi. Growth**

<b>Growth (Year on Year)</b>		<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>POI-A</b>
Production	%	-	-4.44%	-10.01%	-2.11%
Domestic Sales	%	-	1.18%	0.25%	7.24%
Inventory	%	-	80.40%	12.30%	-43.73%
Market Share	%	-	-3.91%	0.20%	-3.83%
Profitability	%	-	-88.97%	20.34%	-861.14%
Return on Capital Employed	%	-	-19.46%	-0.73%	-33.57%

The Market Share and production of Domestic Industry has witnessed a negative growth rate in POI and injury period.

75. Overall growth of the domestic industry with regard to production, capacity utilisation, market share, profits, cash profits and return on investment was negative over the injury period.

**vii. Level of dumping & dumping margin**

76. It is seen that subject country imports are entering into India at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

**viii. Factors affecting domestic prices**

77. Consideration of the import prices from subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from subject countries were below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. Import price from Saudi Arabia have remained all along higher than the import prices from the subject countries. Analysis of month wise import price from Saudi Arabia further shows that the import price from subject countries were lower than the import prices from Saudi Arabia. The benchmark for the Indian producers prices are the import prices. There is no viable substitute to this product. Demand for the product was showing significant increase and could not have been a factor responsible for price suppression faced by the domestic industry. The only factors responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product in India and the cost of production of the domestic industry. Imports caused significant price suppression when the costs were rising and imports caused price depression when the costs were falling.

**ix. Ability to raise capital investments**

78. The authority notes that despite growing demand of the product under consideration in the country, the domestic industry has not planned any enhancement in their production capacity. Nor other domestic producers have planned any capacity enhancement. The domestic industry has claimed that due to continued adverse performance of the product attributable to adverse impact of imports have restrained them from expanding capacities.

**Conclusion on material injury**

79. After examining the volume and price effects of imports of subject goods from subject countries and its impact on the domestic industry, it is noted that there is an absolute increase in the volume of imports of subject goods from subject countries during the injury period, the market share of the subject countries in the demand has increased in the POI as compared to preceding year with significant increase in the imports in this period. With regard to price effect on account of imports of subject goods from subject countries, that imports of the subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price suppression and depression on account of imports of subject goods from subject countries. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is noted that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of sales, production, capacity utilisation, market share, profit, cash flow, return on investment. The domestic industry is running into significant financial losses. Thus, the Authority holds that the domestic industry has suffered material injury.

**Injury Margin**

The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry when compared with the landed value of the exports from the subject countries shows positive injury margin during POI as under:-

a.

Qatar			
S. No.	Producer	Exporter	Injury Margin %
i.	M/s SEEF Limited	M/s Muntajat	0-10
ii.	M/s SEEF Limited	M/s Muntajat through and M/s Renish Petrochem FZE Trader	20-30
iii.	M/s SEEF LIMITED	Weighted Average of i and ii above	5-10%
iv.	Any	Any	20-30 %

b.

China PR			
S. No.	Producer	Exporter	Injury Margin %
i.	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	M/s Hotung Chemical Corp. and M/s Sharpinvest	0-10
ii.	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	0-10
iii.	Any	Any	0-10

c.

Iran			
S. No.	Producer	Exporter	Injury Margin %
i.	Any	Any	0-10

#### L. Other known factors & Causal Link

80. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to examine whether any factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

##### a. Volume and price of imports from third countries

81. The Authority notes that imports of product under consideration from other countries are at higher price or are negligible in terms of volume data of the subject goods. As regards imports from Saudi Arabia is concerned, it is noted that domestic industry had filed application for imposition of antidumping duty on imports of subject goods from Saudi Arabia. However it was noted that the prices at which the goods were imported from Saudi Arabia were not causing injury to the domestic industry, during the POI from Saudi Arabia has once again been found negative in the present findings.

##### b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

82. There has been a rise in demand of the product concerned throughout the injury period and therefore. Decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

##### c. Developments in technology

83. Technology for production of the product concerned has not undergone any disruptive change. Thus, possible developments in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

**d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

84. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

**e. Export performance of the domestic industry**

85. The exports of the domestic industry constitute low share in their total sales. Even though the export volumes of the domestic industry have declined, injury information examined by the Authority is for domestic operations and therefore decline in exports volume is not relevant for the injury to the Domestic Industry considered by the Authority.

**f. Productivity of the Domestic Industry**

86. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee has declined over the period. It is however, noted that the decline in profits, cash profits and return on capital employed for the domestic industry is so high that the decline in the same cannot be attributed to decline in productivity.

87. It is noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

- a. The imports of subject goods from subject countries were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce its prices significantly. The price depression suffered by the domestic industry is primarily noted to be due to dumping of the product in the Country.
- b. The domestic industry was forced to reduce its prices causing financial losses. The price depression caused by the imports thus resulted in significant deterioration in profits of the domestic industry to such an extent that the domestic industry suffered financial losses.
- c. Performance of the domestic industry with regard to sales, production, capacity utilisation, market share, profits, cash flow and return on investments deteriorated as a result of dumped imports from subject countries. Even if it considered that the decline in production, capacity utilisation and sales was not entirely due to dumping, the decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material. To further eliminate injury due to factors of inefficiencies and conversion operation, the non-injurious price determinations eliminates such factors. The domestic industry is running into significant financial losses. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry.

**Comments to the disclosure**

88. Following comments have been made by various interested parties i.e M/s TPM for Domestic Industry, M/s ELP on behalf of Seef, Muntajat and Renish PetroChem, M/s Dua associates on behalf of M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd, M/s Hotung Chemical Corp. and M/s Sharpinvest, M/s Great Oriental Company China, M/s LKS on behalf of DMAI ;and Hindustan unilever Ltd. in response to the disclosure

**i. Product Under Consideration and Like Article**

- a. The product manufactured and sold by Domestic Industry is different from product exported by China PR and Iran particularly. The extra dosage required in case of product from Iran and China is 0.8% and 1.6% respectively by the user industry. Therefore a adjustment on this account be factored in either in landed price or injury margin.

**ii. Domestic Industry Standing/Scope**

- a. The Designated Authority has not appropriately disclosed the procedure followed in determining 'major proportion' for domestic industry at the time of initiation. Even though Nirma and TNPL formed only 32% of the total production in India, the investigation was initiated. Further, even if the Designated Authority deemed it necessary to include RIL into the present investigation, which is also an inadvertent admission that Nirma and TNPL do not form a 'major proportion' of the production in India. The inclusion of RIL has been accepted by the Hon'ble Designated Authority despite the fact that RIL's data was filed over six months after initiation. The

inclusion of RIL at such a belated stage of the investigation is not only a violation of due process, but also violative of the principles of natural justice.

- b. The combined data is not available in the public file.
- c. By including RIL as part of Domestic Industry the Authority has implicitly agreed that Nirma Ltd and Tamilnadu Petroproducts Ltd. cannot be considered as a major proportion.
- d. The disclosure statement establishes that the interested parties were attempting to mislead the Designated Authority by presenting as if the domestic industry did not have a case of injury if RIL data is included.
- e. The Authority has not followed established procedure to include RIL as part of domestic industry and by not terminating the investigation did not fulfil its duty.

**iii. Normal Value**

- a. Normal Value for China and Iran has not been constructed in accordance with Anti-Dumping provisions. The Authority has not applied the provisions of paragraph 7 of Annexure 1 of AD Rules properly to determine normal value for China and Iran.
- b. The Authority has not considered various submissions on Normal Value and export price computation, injury analysis, condonation of delay in RIL's filing letter of support at a belated date, and many other issues as made by various Interested Parties.
- c. Normal value is computed in case of Qatar erroneous as by product sales revenue is not excluded from cost.

**iv. Injury**

- a. There is no volume effect with respect to imports from subject countries. These imports are not having a negative effect on performance of domestic industry. The capacity of domestic industry has not been recorded properly as it has not shown closure of Vadodara plant of RIL.
- b. The profitability of RIL has decreased due to increase in depreciation. The decline in cost of sales needs to be seen in light of increased depreciation of RIL. There is no causal link between injury and dumping.
- c. The injury to domestic industry is on account of other factors like increase in power cut, higher cost of kerosene and its quality issues, uncertainty of availability normal paraffin imports and fluctuating exchange risk as reported by Tamilnadu Petroproducts Ltd.
- d. The NIP has been determined on the basis of the data of domestic industry. The detailed break up of the NIP determined should be disclosed to the domestic industry so as to enable petitioners to provide comments.
- e. Determination of non injurious price is inappropriate and is against the object and intent of the dumping law, as interpreted by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Reliance Industries Ltd. vs. Designated Authority
- f. Authority has not disclosed about negative injury margin of imports from Saudi Arabia and should clarify whether the same is done on an annual or quarterly basis.
- g. There is no price injury to domestic industry. Authority has considered only movement of price and cost but not mirrored the cost of sales with feedstock cost properly. The cost increase of domestic industry is due to its inherent inefficiencies.
- h. There is a clear lack of causality between injury to domestic industry and alleged dumping.
- i. Authority should provide CIF import price of Saudi Arabia and negative injury margin computation.
- j. Great Oriental Chemical (Taicang) Co. Ltd. has not been provided opportunity to respond, though it has submitted information regarding MET and FOB prices and if it was not accepted we should have been informed.

- k. The NIP price computed for domestic industry be shared with other interested parties.
- l. Landed value has been determined differently with different yardsticks.
- m. Its import material arrived in west coast and as well as east coast. The price differences on account of these have not been factored.
- n. Sales of domestic industry have increased in POI. It is only the petitioners who have shown injury and not the two other producers. The price decline of PUC by domestic industry is due to raw material prices only. The domestic sales of domestic industry, with capacity utilization of domestic industry do not indicate injury.
- o. Authority has not considered the issues of an integrated facility to produce LAB and have not computed NIP properly.
- p. The Authority has not appropriately disclosed the procedure and calculations relied upon for the exclusion of Saudi Arabia from the scope of subject countries.
- q. The Authority though sought it important to carry out a price comparison on a quarterly basis to determine undercutting, the same methodology should have been used and a quarterly analysis should have been carried out for calculating the Dumping and Injury Margin.
- r. The injury suffered by the Petitioners cannot be attributed to import of the products under consideration from the subject countries as the volume injury suffered by the Petitioners is due to imports from Saudi Arabia, there is no correlation between the price of the product under consideration imported from the subject countries and the Petitioners' price, there is no correlation between the volume and value of imports and the performance of the Petitioners and economic parameters such as the volume of sales, market share, production, closing stock, productivity show a positive trend.
- s. The Authority has not appropriately disclosed and addressed various non-attributive factors such as:

Volume and price of imports from third countries (Saudi Arabia), Development in technology, Imports of the PUC from Qatar do not compete with TPL's production, the Petitioners have experienced feedstock quality issues and the Petitioners started incurring losses because of the fall in crude oil prices and cash flow issues.
- t. M/s Renish, an exporter has filed their questionnaire but has not co-operated with the verification, cannot be deemed to be co-operative in the present factual matrix. Therefore its data must accordingly be excluded from the dumping margin calculation. Without prejudice if the data of Renish is taken on record, there has to be well justified reasons with regard to the unprecedented practice being followed when a party remain non-cooperative as well as when there have been clearly sales exports made periodically and that too when the Authority is not following a quarterly methodology but an average methodology for calculations of dumping and injury.
- u. M/s Dua Associates representing M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd., M/s Hotung Chemical Corp. and M/s Sharpinvest International Ltd. have stated that exfactory export price disclosed to them in confidential disclosure is correct. They have submitted that there is no price undercutting on account of imports from China and that Domestic Industry has not suffered any volume or price injury. The computation of no price undercutting or injury due to imports from Saudi Arabia be reconfirmed by the Authority.
- v. Great Oriental Chemical (Taicang) Co. Ltd. sale prices are at the same level as Farabi and constitutes only 1.35% of domestic sales in India. The reduction of production or profits to Domestic Industry is on account of other reasons i.e. feedstock shortages, no secure supply of raw material and its volatility and decline in prices of crude oil.
- v. **Dumping Margin**
  - a. The non- confidential version of verification report of the exporters/producers from subject countries should be disclosed to domestic industry.



- b. In case of Qatar for both sales channels the exporter is de facto same i.e. Muntajat irrespective of presence of Renish in one channel. Therefore to prevent undue advantage, the dumping margin and injury margin should be collapsed. The dumping margin and injury margin as in the disclosure statement are lower in respect of direct sales by *Muntajat*. Thus, it would be very easy for the exporter to adopt direct sales in order to attract lower anti-dumping duty despite higher dumping margin and injury margin in respect of exports made through Renish. They shall completely frustrate the higher quantum of dumping margin and injury margin determined by the authority.
- c. M/s ELP has stated that the Authority should adopt the quarterly method of comparison. It seems Authority has changed approach to calculate a higher margin of duty, Authority has considered S&D cost of M/s Seef Ltd. in adjusting exfactory export price which has also been included in the cost of production, the marketing fee deducted for exfactory export price is not proper as selling price to customers are determined exclusively by M/s Muntajat without negotiations with M/s Seef Ltd., the Authority has not appropriately disclosed the procedure and reasons for deviating from the verified data in its dumping margin calculation and that Renish Petrochem cannot be considered as cooperative in the present investigation as they have clearly not participated with the Authority including verification of the data that was provided by them in their questionnaire response.

**vi. Other issues**

- a. The authority had delayed providing the non-confidential version of petition to all interested parties by 37 days making it inconsistent with Article 6.1.3 of WTO ADA. The procedural delay of 37 days calls for termination and cannot be condoned. Judgment of Guatemala- Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico WT/DS156/R dated 24<sup>th</sup> October 2000 has been cited in which it was held that the making available the petition 8 days after the initiation is in contravention to the AD Agreement. The present investigation must be terminated with immediate effect.
- b. Imposition of ADD is not in public interest as it will lead to increase in prices of detergents and pesticides.
- c. Copy of the communications sent by the Authority and copy of replies filed by the interested parties should also be disclosed.
- d. Fixed quantum of duties should be levied as there are significant changes in the cost of production over the injury period. Custom port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer. It is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price. Directorate has accepted benchmark form of duty as not an appropriate form of duty and has changed the form of measures in several cases, and that the duty should be imposed in terms of US\$.

**Examination of Authority**

89. The Authority has examined submissions made by various interested parties in response to the disclosure as under:
  - a. The Authority holds that the petitioners M/s Nirma Ltd. and M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd. constituted a major proportion of Indian production even at the time of filing the petition. However on submissions made by various interested parties, to strengthen the injury analysis, M/s Reliance Industries Ltd. who in any case was a supporter earlier, has also been included in the scope of Domestic Industry to enhance objectivity and representativeness for a comprehensive injury assessment. Its inclusion as part of domestic industry in no way be construed that petitioners lacked standing to file the petition. Further consideration of RIL's data to complete injury assessment is part of the investigation process which Authority considered it important to undertake in view of various representations. The analogy of delay in submitting response with request of Authority to

various interested parties at the time of initiation to file time bound response is misplaced as it is entirely a different obligation casted on various interested parties.

- b. As regards injury to domestic industry in various economic parameters, the Authority has undertaken injury assessment of all stipulated economic parameters listed in Annexure II to Rule 11 (2) of AD Rules and has observed analysed impacts separately on different parameters, collectively the analysis evidences injury to Domestic Industry especially on price in the POI which has been quantified as Injury margin. The inefficiencies in weighted average cost of production determined for domestic industry have been eliminated by undertaking normation on various cost components as per Annexure III of AD Rules.
- c. As regards delay of 37 days in providing NCV copy for updated POI to the interested parties the Authority holds that the NCV petition with 12 months period submitted by domestic industry was all through available in the public file which was even inspected/collected by desiring interested parties. The initiation notification was available on website of DGAD for information of all. Though the revised NCV version of petition was made available later, sufficient time to file responses and even extension was granted by the Authority. Therefore no prejudice has been caused to any interested party. Infact submissions were made by various interested parties in two oral hearings held in this investigation. To ensure fair opportunity the Authority even held a post disclosure hearing on 2<sup>nd</sup> March, 2017 on limited issues of normal value and NIP raised by cooperating producer/exporter for Qatar and Domestic Industry.
- d. The Authority noting the repeated submissions on non-inclusion of Saudi Arabia reiterates that the weighted average landed value of imports from Saudi Arabia of the PUC implies a negative injury margin thereby validating the stand of the Authority to exclude Saudi Arabia from the scope of investigation at the stage of initiation itself.
- e. The Authority had issued Questionnaires to all known producers/exporters from the subject countries. M/s Jiangsu, M/s Sharpinvest and M/s Hotung represented by M/s Dua Associates only filed response to the Questionnaire within prescribed timeline as per the stipulated format. None other producer/exporter including Great Oriental Chemical (Taicang) Co. Ltd. filed any timely response. Request by producer/exporter to file data after expiry of the extended timelines is not considered by the Authority. As regards Great Oriental Chemical (Taicang) Co. Ltd.'s contention of having filed the Questionnaire response, the Authority holds that time was provided to all producers/exporters of subject countries to file data in the structured questionnaire by 22<sup>nd</sup> February, 2016. Based on request by certain producer/exporter the timeline was extended till 8<sup>th</sup> March, 2016. No belated responses by any producers/exporter have been considered by the Authority. The questionnaire response mentioned by Great Oriental Chemical (Taicang) Co. Ltd. was an incomplete data submitted not in the prescribed format with no submission on export price adjustments nor any supportive evidence on data filed. Such an incomplete response at an extremely belated date has not been considered by the Authority as per its consistent practice. The producer/exporter has been classified under the residual category. However submissions made by the producer/exporter on Domestic industry's standing, injury and causal link aspects have been appropriately considered. The producer/exporter has also not filed any MET Questionnaire even though claimed having provided such an information. The company merely stated that they are wholly owned by Great Oriental Chemical (Taicang) Co. Ltd. in Singapore and a business profile of ACRA with no Questionnaire response was filed.
- f. Some of users have mentioned that their submissions have not been considered. The Authority has as per its consistent practise addresses all relevant issues raised by various interested parties appropriately under respective parts of the finding avoiding repetitive submissions. The main contentions on scope of domestic

industry, injury to domestic industry and causality of injury with dumping, adjustment on account of differences in the molecular weight have been appropriately considered. The authority in particular notes the request by the user industry regarding such an adjustment and reiterates that the quantification of an adjustment on the exfactory export price due to any difference in the goods imported and the Domestic Industry's like article needs to be demonstrated by a cooperating producer/exporter. The two cooperating producers/exporters in this case have not evidenced and not claimed an adjustment in their exfactory export price on account of this variation even in their submission in a limited hearing held on 2<sup>nd</sup> March, 2017. Therefore no such adjustment has been considered.

- g. The Authority notes that M/s ELP represents M/s SEEF Ltd., M/s Muntajat, M/s Renish Petrochem FZE has stated that M/s Renish is a non cooperative producer/exporter. The Authority notes that M/s Renish has filed a questionnaire response wherein the CIF prices have been provided. The basis of the normal value and exfactory export price data for this channel of exports is the data as available from SEEF, the producer and its associated exporter viz. Muntajat. Therefore contention of the legal representative who filed the questionnaire on behalf of Renish Petrochem to declare it as non cooperative as neither tenable nor logical. The Authority has therefore determined dumping margin and injury margin for this channel as well.
- h. The S&D expenses of SEEF considered for Exfactory Export Price adjustment for Muntajat have been corrected as the same has been included in the cost of production of SEEF.
- i. M/s Seef's entire production is sold by Muntajat, the exporter to domestic and all global destinations through a decree law of 2012. The price setting is done by Muntajat and the net proceeds after deducting marketing fee and various expenses on exports are paid to seef. It is noted that M/s ELP has filed data for both channels of exports i.e. through Muntajat to India and also from Muntajat and Renish Petrochem FZE to India. Separate determination of Dumping and Injury Margin has been done for both the channels. Keeping in view the fact that producer and its exclusive exporter is the same for both the channels, the Authority has determined weighted average Dumping Margin of both the channels and also weighted average injury margin to apply Lesser Duty Rule .
- j. As regards sharing of NIP/other data of confidential nature with the other interested parties the Authority has followed consistent practise of not disclosing NIP to interested parties other than domestic industry.
- k. As regards the submissions on injury and causal link the Authority has followed the same methodology for evaluating landed value for cooperating and non-cooperating producer/exporter irrespective of the port of clearance. The Authority considers that adopting comparison of normal value with exfactory export price on a weighted average basis for entire POI would equally be representative and appropriate.
- l. Based on the submissions made by M/s ELP in the limited hearing held on 2<sup>nd</sup> March, 2017 and its clarification dated 2<sup>nd</sup> March, 2017, the Authority has adjusted the sales revenue of the by product from the cost of production. The S&D expenses of M/s Seef Ltd. have not been reduced from the export price as claimed and clarified by the exporter in the hearing held on 2<sup>nd</sup> March, 2017.

90. It is noted that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports.

**M. Indian industry's interest & other issues:**

91. As regards submissions of user industry on demand supply situation, impact on prices of user industry, the Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the

contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

#### Conclusions

92. Having examined the contention of various interested parties and on the basis of the analysis as above, the Authority concludes that:

- i) There is dumping of product concerned from the subject countries.
- ii) Imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry.
- iii) Performance of domestic industry has deteriorated in the terms of market share and profitability.
- iv) Injury to domestic industry has been caused by dumped imports.

#### Recommendations

93. Having concluded as above the Authority considers it necessary to recommend following definitive Anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner as described in the duty table given below.

94. The Authority recommends the imposition of Anti-dumping duty equal to lesser of the margin of dumping and margin of injury keeping in view the lesser duty rule. Accordingly the Anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods originating in or exported from subject countries.

**DUTY TABLE**

SN	Sub heading or Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	38170011	Linear Alkyl Benzene	China PR	China PR	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd.	M/s Hotung Chemical Corp. and M/s Sharpinvest International Ltd.	23.78	US\$	MT
2	38170011	Linear Alkyl Benzene	China PR	China PR	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd.	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd.	147.11	US\$	MT
3	38170011	Linear Alkyl Benzene	China PR	China PR	Any combination other than mentioned in S.N. 1 & 2 above.		147.11	US\$	MT
4	38170011	Linear Alkyl Benzene	China PR	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Any	Any	147.11	US\$	MT
5	38170011	Linear Alkyl Benzene	Any country other than those subject to	China PR	Any	Any	147.11	US\$	MT

			anti-dumping duty						
6	38170011	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Qatar	M/s SEEF Limited	M/s Muntajat*	46.49	US\$	MT
7	38170011	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Qatar	M/s SEEF Limited	M/s Muntajat* and M/s Renish Petrochem FZE (Trader)	46.49	US\$	MT
8	38170011	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Qatar	Any combination other than mentioned in S.N. 6 & 7 above.		300.22	US\$	MT
9	38170011	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Any	Any	300.22	US\$	MT
10	38170011	Linear Alkyl Benzene	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Qatar	Any	Any	300.22	US\$	MT
11	38170011	Linear Alkyl Benzene	Iran	Iran	Any	Any	71.8	US\$	MT
12	38170011	Linear Alkyl Benzene	Iran	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Any	Any	71.8	US\$	MT
13.	38170011	Linear Alkyl Benzene	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Iran	Any	Any	71.8	US\$	MT

\*M/s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C., Qatar  
Further Procedure

95. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority